लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र

Eleventh Session

PAR 340
DATE 21.6.65

सत्यमेव जयते

Preservation 27-5-92
Fumigated On 26.12.83
Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं

Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंगेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summars from of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची

अंक 3, शुक्रवार, 19 फरवरी, 1965/30 माघ, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
31	छोटी कार	127
39	छोटी कार	129
33	बोकारो इस्पात परियोजना	133
34	काठमांडू में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी	139
35	खड़गपुर के समीप गाड़ी और ट्रक की टक्कर	142
36	दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात परियोजना	145
37	सीमेन्ट की कमी	147

प्रश्नों क लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
32	राज्य व्यापार निगम	151
38	नेपाल और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए पारगमन सुविधाएं	152
40	चाय वित्त समिति	152
41	आयात नीति	153
42	उपभोक्ता उद्योग	154
43	सरकारी उपक्रम	154
44	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	155
45	भिलाई इस्पात परियोजना	156
46	रूस से सीसे का आयात	156
47	कच्चा लोहा सम्बन्धी तकनीकी समिति	157
48	दुर्गापुर में कांग्रेस का अधिवेशन	158
49	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	158
50	खानों का वैमानिक सर्वेक्षण	159
51	खानों के मुहानों पर कोयला	159
53	दुर्गापुर इस्पात परियोजना	160
54	केरल में औद्योगिक बस्तियां	160

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. **3** *Friday, February* **19, 1965**/*Magha* **30, 1886** (*Saka*)

Oral Answers to Questions

Starred Queistion Nos.	*Subject*	Pages
31.	Small Car . .	127
39.	Small Car .	129
33.	Bokaro Steel Project	133
34.	Indian Industrial Exhibition in Kathmandu .	139
35.	Train-Truck Collision near Kharagpur . .	142
36.	Alloy Steel Project at Durgapur	145
37.	Shortage of Cement . .	147

Written Answers to Questions

Starred Question Nos.		
32.	State Trading Corporation	151
38.	Transit Facilities for trade between Nepal and Pakistan	152
40.	Tea Finance Committee	152
41.	Import Policy	153
42.	Consumer Industries	154
43.	Public Enterprises	154
44.	H.E.L. Bhopal .	155
45.	Bhilai Steel Project .	156
46.	Import of Lead from U.S.S.R.	156
47.	Technical Committee on Pig Iron	157
48.	Durgapur Congress Session	158
49.	Export of Textiles to U.K. .	158
50.	Air-borne survey of Mines	159
51.	Coal at Pit heads .	159
53.	Durgapur Steel project	160
54.	Industrial Estates in Kerala	160

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
55	धनुषकोटि में रेल दुर्घटना	161
56	व्यापार गृह .	162
57	एल्यूमिनियम का उत्पादन	162
58	पांचवां इस्पात कारखाना .	163
59	अमरीका के आयात-निर्यात बैंक से ऋण	164

अतारांकित

प्रश्न संख्या

44	बख्तियारपुर में रेलवे पुल . .	165
45	अमरोहा स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	165
46	दिल्ली क्षेत्र में रेल का ऊपरी पुल .	165
47	मुगलसराय-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण	166
48	दौराला-मवाना-हस्तिनापुर के बीच रेलवे लाइन	167
49	माल डिब्बे . . .	168
50	राजस्थान विमान, रेल परिवहन यात्री संस्था	168
51	भावनाथपुर तक बड़ी रेल लाइन	169
52	ईंधन के मूल्य	169
53	भोजन कार . . .	170
54	रेलवे भोजन व्यवस्था देखभाल समितियां	171
55	उत्तर रेलवे पर सामान बेचने सम्बन्धी ठेकेदार	171
56	अम्बाला सुधार न्यास .	172
57	लोह-अयस्क का निर्यात	170
58	तिरुचि में बायलर संयंत्र . . .	172
59	छपरा जंक्शन के निकट रेलगाड़ी और बस की टक्कर	173
60	डीज़ल इंजन	173
61	यमुना पर रेलवे पुल	174
62	यमुना पुल, दिल्ली . . .	174
63	हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस गाड़ी में शव का पाया जाना	175
64	ऊनी कपड़े के खुदरा बिक्रेता	175
65	राजनयिक कारों की बिक्री .	176
66	गोआ में औद्योगिक विकास निगम	176
67	रेलवे श्रमिकों का तैनात किया जाना .	177
68	गया के निकट रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना	177
69	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	177
70	लाहोल-स्पिती में तांबे के निक्षेप	178

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
55.	Train Disaster at Dhanushkodi	161
56.	Trading Houses	162
57.	Production of Aluminium	162
58.	Fifth Steel Plant .	163
59.	U.S. Import-Export Bank Loan	164

Unstarred Question Nos.		
44.	Railway Bridge at Bakhitiarpur	165
45.	Derailment at Amroha Station .	165
46.	Railway Over bridges in Delhi Area .	165
47.	Electrification of Moghulsarai Kanpur Section .	166
48.	Daurala-Mawana-Hastinapur Rail Line .	167
49.	Wagons	168
50.	Rajasthan Air, Rail Transport Passengers Association	168
51.	Broad Gauge Rail Line to Bhavanathpur. .	169
52.	Prices of Cotton . .	169
53.	Dining Car	170
54.	Railway Catering Supervisory Committees .	171
55.	Vending Contractors on Northern Railway .	171
56.	Ambala Improvement Trust . . .	172
57.	Export of Iron Ore	170
58.	Boiler Plant in Tiruchi	172
59.	Train-Bus Collision Near Chupra Junction .	173
60.	Diesel Engines	173
61.	Railway Bridge over Jamuna.	174
62.	Jumna Bridge Delhi	174
63.	Dead Body in Howrah-Bombay Express . . .	175
64.	Woolen Textile Retailers	175
65.	Sale of Diplomatic Card	176
66.	Industrial Development Corporation in Goa . . .	176
67.	Posting of Railway Workers	177
68.	Derailment near Gaya	177
69.	National Industries Development Corporation . . .	177
70.	Copper Deposits in Lahaul-Spiti	178

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
71	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार	178
72	इटावा के समीप दुर्घटना	179
73	कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग	179
74	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	179
75	दिल्ली स्टेशन पर इंजन का पटरी से उतर जाना	180
76	लघु उद्योग	180
77	खनिज सम्पत्ति का सर्वेक्षण	181
78	त्रिपुरा तथा बिहार में पटसन मिलें	181
79	रूई का आयात	182
80	कपास का आयात	182
81	इटावा-भिण्ड रेल सम्पर्क	183
82	पंजाब में कागज का कारखाना	183
83	यूकेरिया-तलवारा रेलवे लाइन	183
84	लुगदी निर्माण संयंत्र	183
85	मद्रास और अरकोणम के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ी	184
86	फ़ैजाबाद-लखनऊ यात्री गाड़ी में खतरे की जंजीर	184
87	राजेन्द्र पुल हाल्ट तथा हथीदा जंक्शन के बीच रेल किराया	185
88	रम का निर्यात	185
89	चोरी के मामले	185
90	कर्जत खोपोली लाइन	186
91	उत्तर रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टैंडेण्ट के कार्यालय	186
92	इटारसी-जबलपुर लाइन को दोहरा करना	187
93	अरब साझा बाजार	187
94	रेल यात्रियों पर चुंगी	187
95	आयरलैण्ड को वस्त्रों का निर्यात	188
97	भटिंडा तथा नोखा के बीच विशेष गाड़ी सेवा	188
99	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	188
100	येल्लान्दु में कच्चे लोहे का संयंत्र	189
101	कोठागुडियम में लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट	189
102	कटिहार की जूट मिल	190
103	मैसूर की अलोह धातुओं का आवंटन	190
104	जूट की कमी	191
105	रावी नदी पर रेलवे पुल	191

Unstarerd Question Nos.	*Subject*	PAGES
71.	President's Awards to Public Sector Industrial Undertakings	178
72.	Accident near Etawah .	179
73.	Substitution of Oil for Coal	179
74.	H.E.L. Bhopal	179
75.	Derailment of Engine at Delhi Station	180
76.	Small Scale Industries .	180
77.	Survey of Mineral Wealth	181
78.	Jute Mills in Tripura and Bihar	181
79.	Import of Cotton	182
80.	Import of Cotton .	182
81.	Etawah-Bhind Rail Lihk	183
82.	Paper Mill in Punjab .	183
83.	Mukerian Talwara Railway Line	183
84.	Pulp Manufacturing Plant .	183
85	Electric Train between Madras and Arkonam .	184
86.	Alarm Chain in Faizabad-Lucknow Passenger Train .	184
87.	Railway Fare between Rajendra Pul Halt-Hathidah Junction	185
88.	Export of Rum .	185
89.	Pilferage Cases . ,	185
90.	Karjat-Khopoli Line	186
91.	Divisional Superintendent Office, Northern Railway . .	186
92.	Doubling of Itarsi-Jabalpur Line .	187
93.	Arab Common Market	
94.	Terminal Tax on Railway Passengers . .	187
95.	Export of Textiles to Ireland . .	188
97.	Special Train between Bhatinda and Nokha .	188
99.	Cement Factories in Andhra Pradesh . .	188
100.	Pig Iron Plant at Yellandu	189
101.	Low Temperature Carbonisation Plant at Kothangudium .	189
102.	Katihar Jute Mills	190
103.	Allotment of non-ferrous Metals to Mysore .	190
104.	Shortage of Jute	191
105.	Railway Bridge Over Ravi	191

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
106	कठुवा रेलवे स्टेशन	191
107	पथखेड़ा कोयला क्षेत्र	192
108	व्यापार सम्बन्धी एकाफे समिति	192
109	उड़ीसा को इस्पात का आवंटन	193
110	तलचर कोयला खानें	193
111	उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग	194
113	लघु उद्योग निगम, उड़ीसा	195
115	कालीकट रेलवे स्टेशन	195
116	महाराष्ट्र में उद्योग	196
117	निर्यात संवर्धन सम्बन्धी राज्य बोर्ड	196
118	कोयले का सेम्पलिंग तथा ग्रेडिंग	197
119	घटिया किस्म का कोयला	197

स्थगन प्रस्ताव के बारे में 198

भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां . 198

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . 198

वियतनाम में हुई हाल ही की घटनाएं और उनके बा रे में सरकार की प्रतिक्रिया 198

सभा पटल पर रखे गये पत्र 201

लोक लेखा समिति 203

इक्तीसवां प्रतिवेदन . 203

सभा का कार्य 203

कार्य मंत्रणा समिति 203

चौंतीसवां प्रतिवेदन . 203

आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1965---पुरःस्थापित . 204

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . 204

श्री ति० न० कृष्णमाचारी . . 204

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
106.	Kathua Railway Station.	191
107.	Pathakhera Coal Field .	192
108.	ECAFE Committee on Trade	192
109.	Steel allotment to Orissa	193
110.	Talchar Coal Mines	193
111.	Small Scale Industries in Orissa	194
113.	Small Scale Industries Corporation Orissa	195
115.	Calicut Railway Station	195
116.	Industries in Maharashtra	196
117.	State Boards for Export Promotion	196
118.	Sampling and Grading of Coal . .	197
119.	Low-Grade Coal . .	197
Re : Motion for Adjustment		198
Arrests under D.I.R.		198
Calling Attention to Matter of Urgent Public importance		198
Recent development in Vietnam and reaction of Government thereto		198
Papers liad on the Table . . .		201
Public Accounts Committee		203
Thirty-first report		203
Business of the House		203
Business Advisory Committee		203
Thirty-fourth Report		203
Income (Amendment) Bill 1965—Introduced		204
Statement re : Income-Tax (Amendment) Ordinance .		204
Shri T.T. Krishnamachari : . .		204

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	204
श्री हेडा	204
महाराजकुमार विजय आनन्द . .	206
श्री रंगा .	214
श्री उ० मू० त्रिवेदी .	217
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	219
पचपनवां प्रतिवेदन	219
विधेयक पुरःस्थापित : .	220
1. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 368 का संशोधन) [श्री यशपाल सिंह का]	
2. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 तथा 220 का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]	
3. समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा 13क का रखा जाना, धारा 293 आदि का संशोधन) [श्री यशपाल सिंह का]	
मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक . .	221
(धारा 3, 4 आदि का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	
विचार करने का प्रस्ताव	221
श्री हरिविष्णु कामत	221
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	223
श्री सरजू पाण्डेय	224
श्री हुकमचन्द कछवाय	225
श्री दी० चं० शर्मा .	225
डा० मा० श्री अणे . .	226
श्री यशपाल सिंह	226
श्री खाडिलकर	227
श्री स० मो० बनर्जी	227
श्री बाल्मीकी .	228
श्री राम सहाय पाण्डेय	228
श्रीमती रेणुका राय	229
श्री भागवत झा आजाद . .	229
श्री हेडा . .	230
श्री अ० सि० सहगल . . .	231
श्री हाथी	231

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
	Motion on President's Address	204
	Shri Heda . . .	204
	Maharajkumar Vijaya Ananda	206
	Shri Ranga .	214
	Shri U.M. Trivedi	217
	Committee on Private Members' Bills and Resoluations .	219
	Fifty-fifth Report .	219
	Bills introduced . .	220
	1. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Article 368*) by Shri Yashpal Singh .	
	2. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of Articles 124 and 220*) by Shri C. K, Bhattacharyya	
	3. Constitution (Amendment) Bill (*Insertion of new section 13A, amendment of sections 293 etc.*) by Shri Yashpal Sungh	
	Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill (*Amendment of sections 3, 4, etc.*) by Shri Hari Vishnu Kamath.	
	Nagatived	
	Motion to consider . . .	221
	Shri Hari Vishnu Kamath	221
	Shri Narendra Singh Mahida . .	221
	Shri Sarjoo Pandey	223
	Shri Hukam Chand Kachhavaiya .	224
	Shri D.C. Sharma .	225
	Dr. M.S. Aney . .	225
	Shri Yashpal Singh .	226
	Shri Khadilkar . . .	226
	Shri S. M. Banerjee	227
	Shri Balmiki	227
	Shri R.S. Pandey. . . .	228
	Shrimati Renuka Ray	228
	Shri Bhagwat Jha Azad	229
	Shri Heda	229
	Shri A. S. Saigal	230
	Shri Hathi	231

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 19 फरवरी, 1965/30 माघ, 1886 (शक)

Friday, Feb. 19, 1965/Magha 30, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या 31 और 39 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा ।

श्री दी० चं० शर्मा : प्रश्न संख्या 31 ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : प्रश्न संख्या 39 को भी इस प्रश्न के साथ ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा करना सुविधाजनक है तो प्रश्न संख्या 39 का उत्तर भी इसी के साथ दिया जाये ।

छोटी कार

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री राम नाथन चेट्टियार
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

*31. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री अब्दुल गनी गोनी :
श्री रामचन्द्र उलाक्का :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रा० बरुआ :
श्री दाजी :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री वारियर :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार के निर्माण के बारे में विदेशी फर्मों से हुई बातचीत के कोई परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या चतुर्थ योजना अवधि में छोटी कार के बाजार में उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग). अभी बात चीत चल रही है तथा इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है । लघुकार प्रायोजना समेत चौथी योजना के अतिरिक्त कार्यक्रमों पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श हो रहा है ।

छोटी कार

*39. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कार के बारे में पांडे समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ख) प्रस्तावित कार का कितना निर्यात होने का अनुमान है ;

(ग) पांडे समिति के प्रतिवेदन के पेश किये जाने के पश्चात् तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक (वर्षवार) कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ; और

(घ) आगामी पांच वर्षों में देश में वर्तमान किस्म की कारों के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा की अनुमानित मांग क्या है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) पाण्डे समिति ने छोटी कार बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर विचार किया था। इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, यह विभिन्न विदेशी निर्माताओं ने अलग अलग बताई है। पाण्डे समिति द्वारा सिफारिश की गई योजना के लिए पूंजी लेखे में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान लगभग 10 करोड़ रु० लगाया गया है ।

(ख) निर्यात का कोई भी अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) 1961-62 से कार उद्योग के लिये जो विदेशी मुद्रा आवंटित की गई है वह नीचे दिखाई गई है :--

वर्ष	पूंजी लेखे में विदेशी मुद्रा लाख रु० में	देखभाल लेखे में विदेशी मुद्रा
1961-62	+143.00	579.21
1962-63		422.20
1963-64 . . .		404.00
1964-65	+ 29.00	332.25

+चौखटे बनाने में काम आने वाले प्रेस टूलों और सांचों के लिये ।

(घ) वर्तमान मेकों की कारें बनाने के लिये अगले 4 से 5 वर्षों में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता उनकी वर्तमान स्थापित क्षमता और 90 प्रतिशत देशी हिस्से के आधार पर 5.70 करोड़ रु० प्रति वर्ष की होगी। इसमें से 2.12 करोड़ रु० पुर्जों तथा 3.58 करोड़ रु० कच्चे माल के लिये होंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : छोटी कार के निर्माण के लिये सरकार कितने देशों से बातचीत कर रही है और क्या उन देशों में से किसी एक देश ने अन्य किसी देश के मुकाबले अच्छी शर्तें रखी हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : विवरण में यह बताया गया है कि हम लगभग पांच संस्थाओं से बातचीत कर रहे हैं---जेकोस्लोवाकिया की 'स्कोडा' फ्रांस के मेसर्स रिनाल्ट के सहयोग से 'डोकाइन', इंगलैण्ड की रुट्स आर्गेनाइजेशन के सहयोग से 'हिलमेन इम्प' पश्चिम जर्मनी की 'डी० के० डब्लू' और जापान की 'डाट्सन ब्लूबर्ड' ये बातचीत अभी आरम्भिक ही हैं क्योंकि अभी उन्होंने अपने प्रस्ताव नहीं दिये हैं । जब तक हमें प्रस्ताव प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमारे लिये यह बताना बड़ा कठिन है कि कितनी प्रगति हुई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को इन कारों की लागत तथा अन्य जानकारी के सम्बन्ध में इन में से किसी देश से ब्योरे प्राप्त हुए हैं, और यदि नहीं, तो ये ब्योरे कब तक आ जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उन्होंने अभी तक निश्चित आकड़े नहीं बताये हैं । उन्होंने मेरे साथ सामान्य बातचीत की है और मैं ने कुछ चर्चा की थी । मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि चूंकि बातचीत अभी चल रही है इसलिये इन बातों के ब्योरे न पूछे ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हमने कितनी कारें बनाने की परियोजना बनाई है जिसके आधार पर बातचीत चल रही है और कार का मूल्य क्या होगा और संसद् में परियोजना के ब्योरे कब तक पूरी तरह से बता दिये जायेंगे ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस समय हम 50,000 कारें प्रतिवर्ष बनाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं मूल्य के सम्बन्ध में इस समय कुछ भी बताना कठिन है क्योंकि बातचीत अभी चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बताना संभव है कि इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं समय नहीं बता सकता ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : तीन वर्ष पहले फ्रांस के एक निर्माता से कुछ बातचीत की गई थी कि उन्हें 'टर्न की जोब' के आधार पर एक कारखाना स्थापित करना था । उस बातचीत के संबंध में क्या स्थिति है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : उसके बाद हाल ही में दोबारा बातचीत शुरू की गई है । उनका प्रति निधि आया था और मुझ से मिला था । वह अपने प्रस्ताव बता रहा है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : इस संस्था के साथ हो रही बातचीत को लेकर ही आगे बातचीत की जा रही है अथवा नये सिरे से बातचीत की जा रही है और सरकार कब तक निश्चित निर्णय ले लेगी?

श्री त्रि० ना० सिंह : नये प्रस्ताव तो वह संस्था ही देगी । संस्था नये प्रस्ताव बना रही है । कब तक बना लेगी इस बारे में कुछ भी कहना कठिन है ।

श्री इन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वर्तमान आटोमोबाइल कम्पनियां छोटी कार बना सकती हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : प्रत्येक मामले में आशा तो होती ही है ; ऐसा हो सकेगा अथवा नहीं यह एक अलग बात है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि हमारे बाजार में छोटी कार न होने से देश में नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है; यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आयात नीति में कुछ ढील देना चाहती है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जी नहीं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि देश के वर्तमान मोटर कार निर्माताओं ने सरकार को यह पेशकश की है कि वे देश की छोटी कारों की मांग को पूरा कर सकते हैं और और कार का मूल्य भी घटा सकते हैं यदि सरकार उनको कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक सुविधाएं दे ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री त्रि० ना० सिंह: : उन्होंने कीमतों में कोई कमी करने की पेशकश नहीं की है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether the principle adopted in this respect will not be changed and that small cars will be manufactured in the Public Sector ?

Shri T. N. Singh : This has already been accepted and no departure will be made.

श्री सरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि मेसर्स 'स्कोडा एण्ड कम्पनी' के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं और उसके विरुद्ध कुछ मामले चल रहे हैं ; यदि हां, तो क्या यह मामले निपटा लिये गये हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं जेकोस्लोवाकिया की मेसर्स स्कोडा के बारे में कह रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : उसी कम्पनी के विरुद्ध जालसाजी और कम बीजक बनाने के कुछ आरोप हैं और कुछ मामले चल रहे हैं । वित्त मंत्रालय द्वारा यह उत्तर दिया गया था ।

श्री त्रि० ना० सिंह : कुछ कहने से पहले मैं माननीय मंत्री से ब्योरे लेना चाहूंगा ।

श्री दाजी : क्या बातचीत केवल छोटी कार के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाना है अथवा पक्के निर्णय किये गये हैं कि सरकार छोटी कारें बनाने जा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी परियोजना के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं । परन्तु यह कह देना जरूरी है कि यह एक चतुर्थ योजना की परियोजना होगी और चतुर्थ योजना की परियोजनाओं पर योजना आयोग के साथ चर्चा की जा रही है । केवल यही बात है जो मैं ब्योरे नहीं बता रहा हूं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस योजना को अन्तिम रूप देने में सरकार को कितना समय लगेगा ? हम इसके बारे में पिछले 2 या 3 वर्षों से सुन रहे हैं । क्या सरकार यह बता सकती है कि योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि इसके बारे में वह नहीं बता सकते ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को जानकारी है कि जनता के दिमाग में यह बात समा गई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा दबाव डालने के कारण छोटी कार परियोजना को समय-समय पर स्थगित किया जा रहा है और यदि हां, तो इस शंका को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इस मामले में हम किसी भी दबाव से प्रभावित नहीं हुए हैं ।

Shri Vishram Prasad : May I know whether Government are coming in the way of the manufacture of small car or is it because of some industrialists that this is being delayed ?

Shri T. N. Singh : There is no question of coming in the way.

Shri Yashpal Singh : May I know the reasons for seeking foreign collaboration in the manufacture of small car and not giving opportunities to the Indian manufacturers when they are in a capacity to flood the market with small cars ?

Shri T. N. Singh : We have no such information.

Shri Gulshan : Have Government ever enquired that the imported cars are better in quality and cheaper as compared to the indigenously manufactured cars ?

Shri T. N. Singh : First of all we must admit that we have not enough foreign exchange for imports and much less for a thing like car.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Why the Pandey Report has not so far been implemented. ?

Shri T. N. Singh : It is a very old matter.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि हाल ही में मंत्री महोदय हिन्दुस्तान मोटर्स फैक्टरी को देखने गये थे और वहां पर प्रबन्धकों ने उन्हें बताया कि आयात की कमी के कारण न तो वे उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में हैं और नहीं किस्म में सुधार कर सकते हैं और यदि उन्हें समय पर माल आयात करने के लिये लाईसेंस मिल जायें और कोई प्रतिबन्ध न हों तो वे मोटर कार सस्ती कीमतों पर बेच सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में अन्य कारें शामिल नहीं हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : विवरण में यह दिया गया है कि विभिन्न विदेशी निर्माताओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी मांग अलग-अलग थी । अन्त में सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि लगभग 10 करोड़ रु० के मूल्य की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी । नई कम्पनियों से बातचीत करते समय क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी की विदेशी मुद्रा से आनेवाले पूर्जे बढ़ने न पाये अथवा क्या सरकार इस सीमा को बढ़ा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस बात के लिये प्रयत्न करूंगा कि विदेशी मुद्रा कम-से-कम लगे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन क्यों नहीं दे रही है कि छोटी कार परियोजना जब भी आरम्भ की जायेगी इसे सरकारी क्षेत्रों में रखा जायेगा ताकि लोगों के दिलों से सब शंकाएं दूर हो जायें कि पूंजीपतियों के दबाव के कारण ही सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यदि बेबुनियाद शंकाएं प्रकट की जाती हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? वे बिल्कुल बेबुनियाद हैं ।

बोकारो इस्पात परियोजना

+

श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती :
श्री रा० गि० दुबे:
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० न० तिवारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सेझियान :
*33. श्री परम शिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री रा० बरुआ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीम० ला० द्विवेदी :
श्रीसुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री चांडक:
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना के लिए रूसी वित्तीय सहायता सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या करार पर हस्ताक्षर होने में देरी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). 15 लाख से 20 लाख टन वार्षिक क्षमता के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में सहयोग देने और इस प्रयोजन के लिए ऋण उपलब्ध करने के लिए भारत और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ की सरकारों के बीच 25 जनवरी 1965 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए ।

करार की मोटी मोटी शर्तें इस प्रकार हैं :—

1. ऋण की रकम 19 करोड़ रुबल (100.5 करोड़ रुपये) तक होगी जो बारह समान वार्षिक किस्तों में वापिस की जायेगी । उपयोजित ऋण के अदत्त शेष पर ब्याज की दर 2.5 प्रतिशत होगी ।

2. कारखाने का रूपांकन करने और साज-समान के संभरण में अधिकाधिक भारतीय संगठनों को सम्मिलित किया जाएगा । यद्यपि कारखाने के बाहर की सुविधाओं का रूपांकन और निर्माण पूर्णतया भारतीयों के हाथ में होगा, कारखाने के अन्दर भी बहुत सी इकाइयों के रूपांकन और ड्राइंग कार्यों में भी भारतीय संगठन भाग लेंगे ।

3. सोवियत संगठन बोकारो के 40 लाख टन क्षमता के संयंत्र के लिए नौ महीनों के अन्दर एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा ।

4. बोकारो कारखाना गर्म और ठंडे वेल्लित स्ट्रिप और चादरें जिनमें जस्ती चादरें भी सम्मिलित हैं, का उत्पादन करेगा ।

5. सोवियत संगठन उन उपकरणों की पूर्ति करेगा जो 1966 और 1969 की अवधि में भारत में उपलब्ध नहीं होंगे ।

2. करार पर हस्ताक्षर होने में कोई देरी नहीं हुई है। 22 दिसम्बर 1964 को एक सोवियत शिष्टमण्डल भारत सरकार और सोवियत संघ की सरकार के बीच बातचीत करने और करार करने के लिए भारत आया था जिस के नेता सोवियत संघ की विदेशी आर्थिक मामलों की मंत्री-परिषद् की राज्य समिति के उप-सभापति श्री वी० सरगीव थे । सोवियत संघ की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न शर्तों पर समझौता करने में लगभग एक महीना लगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में यह बताया गया है कि रूसी संगठन ऐसे साज-सामान की सप्लाई करेंगे जो 1966 से 1969 की अवधि में भारत में उपलब्ध नहीं होंगे । रूसी संगठन द्वारा सप्लाई किये जाने वाले साज-सामान कुल लागत के कितने प्रतिशत होगा और इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी से प्रतिशतता के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता लेकिन यह भिलाई से काफी अधिक होगी । यह 30 या 33 प्रतिशत के करीब होगी ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह बताया गया है कि कारखाने की डिज़ाइन बनाने और इमारत बनाने की जिम्मेवारी भारत सरकार पर होगी । क्या मैं जान सकता हूं कि कारखाने का डिज़ाइन बनाने और इमारत बनाने की कितनी जिम्मेदारी संयंत्र के अन्तर्गत है और इस का खर्चा कितना होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कारखाने के डिज़ाइन और निर्माण का सवाल है, ब्योरे का परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही पता लग सकेगा ।

Shri Bishwanath Roy : May I know whether some training will be given to Indian engineers in connection with the technicalities of machines alongwith the construction of this project ?

Shri P.C. Sethi : Yes Sir, there is a programme for imparting training to Indian engineers. Here there is a separate cell where some drawings and designs of construction work are prepared.

Shri K.N. Tewari : In the statement, it is said कि डिजाइन बनाने और साज-सामान और सामग्री की सप्लाई में भारतीय संगठन अधिकाधिक योग देंगे । I want to know the names of organisations selected for designing and supply of equipments ?

Shri P.C. Sethi : There are Central Engineering and Designing Bureau of Indian steel limited and Heavy Engineering Corporation. The work will be entrusted to any of these whosoever can do that properly.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय संगठनों में दस्तूर एण्ड कम्पनी का नाम भी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इनका नाम भी हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जो भी इस काम को ठीक कर सकेगा, उस को यह काम सौंपा जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know the cost involved due to delay in the execution of the job and the amount expected to be spent on the commissioning of the project ?

Shri P.C. Sethi : No amount was spent due to delay. It is a fact that originally the Bokaro Steel Plant was to be received from America which was not received. That is the reason why we lagged behind the plan period.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : हम यह जानना चाहते हैं कि दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ किये गये ठेके को क्यों छोड़ा गया और क्या रूस सरकार के दबाव पर ही ऐसा किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी, नहीं । अभी इस पर विचार किया जाना है । जैसा बताया जा चुका है, परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद ही प्रतिशतता निर्धारित की जाएगी । इस बारे में केवल तब ही निर्णय किया जा सकता है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बोकारो परियोजना के अतिरिक्त रूस सरकार इस देश में किसी अन्य इस्पात परियोजना में धन लगाने को राजी है ?

श्री संजीव रेड्डी : भिलाई का भी विस्तार किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्राक्कलन समिति ने यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि 'टर्न-की जॉब' जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिये । यद्यपि यह कहा गया है कि इस कारखाने आदि का डिजाइन बनाने में भारतीय संगठनों का अधिकाधिक योग होगा । जिस प्रकार दस्तूर एण्ड कम्पनी को इसमें से निकाला गया है, इससे हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य में इस्पात संयंत्रों के लिये इसको अमेरिका से या अन्य अमरीकी सार्थों से 'टर्न-की जॉब' के लिये एक परम्परा माना जायेगा जैसा कि बोकारो के मामले में हो रहा है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं नहीं समझता कि हम इस प्रकार कल्पना क्यों करते हैं । कुछ भारतीय इंजीनियर हैं और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास भी कुछ विशेषज्ञ हैं, जिनको काम पर लगाया जायेगा । रूसी तकनीशन इनका माग-दर्शन करेंगे और सहायता करेंगे लेकिन अधिकांश कार्य भारतीय तकनीशनों द्वारा ही किया जायगा । इस को हम 'टर्न-की जॉब' नहीं कह सकते ।

Shri A.P. Sharma : Land from many villages has been acquired for this project. I want to know whether persons of the villages, from where land was acquired, will be given preference in employment ?

Shri P.C. Sethi : Yes, Sir preference will be given to them in respect of non-skilled jobs but not in respect of skilled jobs.

Shri D.N. Tewari : After refusal by America, the establishment of Bokaro Plant has been delayed much. May I know whether the preliminary work is complete so that the work is done in time and whether it is a fact that more than required land was acquired and whether arrangements are being made to return these lands to their owners ?

Shri P.C. Sethi : More land was not acquired and only that much land was acquired which was needed. While acquiring land, future expansion of the Plant has also been kept in view. We propose to start production by 1970 and this is kept in view while doing jobs.

श्री विभूति मिश्र : करार के अनुसार, रूसी संगठन बोकारो में 40 लाख मेट्रिक टन के संयंत्र के लिये 9 महीने में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेंगे । इसके लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : अभी ऐसी बात नहीं है । अभी हम केवल 15 से 20 लाख मेट्रिक टन की क्षमता का संयंत्र स्थापित कर रहे हैं । बाद में, यह ब्योरा तैयार किया जायगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether the terms of the agreement entered into in respect of this Bokaro Steel Plant are more favourable in comparison to other agreements such as Durgapur Steel Plant or the Steel Plant to be established with the American aid ?

श्री संजीव रेड्डी : ये शर्तें इस प्रकार सरल हैं कि अब हम भारतीय साज-सामान अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर सकेंगे । इस प्रकार विदेशी मुद्रा कुछ कम खर्च होगी । मूल्यों के बारे में तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मूल्य तो बढ ही रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद भी क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि वह इस बारे में नहीं बता सकते कि इसकी अन्य इस्पात संयंत्रों से क्या तुलना है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने प्रतिशत भारतीय साज-सामान लगाते हैं । यह 30 से 35 प्रतिशत हो सकता है । निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री भागवत झा आजाद : करार तो हुआ है ।

श्री विश्वनाथ राय : इसकी शर्तें अधिक सरल हैं या नहीं ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं समझता हूं कि ये सरल हैं । यह करार दोनों पक्षों के लिए है । निश्चय ही यह हमारे देश के लिये सरल है ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has said that Indian organisations will have more participation in the designing of the Bokaro Plant. I want to know as to what he exactly means by more participation and whether it was objected to by the Soviet Government that this work should not be assigned to Indian companies.

Shri P. C. Sethi : This is not the real case. The layout and designs prepared by them differ from the plans given in the preliminary report regarding this project and therefore it was agreed that they prepare the design report of the Project again. So far as Indian technicians taking part in this project is concerned, they would be participating in the designing, construction and erection work and they would be given full opportunity for the said participation.

Shri Madhu Limaye : Who would be responsible for the designs ?

Shri P. C. Sethi : That would be done under the Soviet supervision.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : विवरण में यह बताया गया है कि रूस सरकार से लगभग 100.5 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होगा । इस पर कुल कितनी लागत आएगी और बाक़ी धन किस प्रकार जुटाया जाएगा ?

श्री संजीव रेड्डी : वर्तमान अनुमानों के अनुसार यह धन पर्याप्त रहेगा । लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो और धन के लिये बातचीत की जाएगी । यदि कुछ लाख रुपयों की और आवश्यकता हुई तो संभवतः वे सहायता कर देंगे अथवा हमें सामान्य व्यापारिक साधनों के बारे में विचार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : महाराजकुमार विजय आनन्द ।

महाराजकुमार विजय आनन्द : इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : परियोजना प्रतिवेदन कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा । इस के बाद हम क्रयादेश देंगे । निर्धारित तिथि 1970 है । तब तक उत्पादन होने लगेगा ।

श्री दाजी : क्या यह सच है कि इस संयंत्र को नवीन खुली सतत भट्टी प्रणाली (न्यू ओपन कन्टीन्युअस हर्थ सिस्टम) के अनुसार बनाया जाएगा जिससे प्राथमिक लागत में लगभग 50 करोड़ रुपये और आवर्ती व्यय में लगभग 10 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत होगी ? क्या यह बात सही है ?

श्री संजीव रेड्डी : परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । ब्योरा परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के बाद ही पता लग सकता है । यदि अभी से मैं कुछ कह दूं, तो वह ठीक नहीं है ।

श्री दाजी : परियोजना प्रतिवेदन इस आधार पर तैयार किया जा रहा है या नहीं ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां । यह तैयार किया जा रहा है ।

Shri Vishram Prasad : May I know the target of production fixed and the deficit in production ?

Shri P.C. Sethi : The net production of the plant is from 1·5 to 2 million tonnes.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the average of land acquired for the establishment of the plant and whether it is a fact that the compensation for the land was not given at the market rate ?

Shri P. C. Sethi : The compensation is being paid by the Government of Bihar and the land has been acquired for that compensation.

श्री विद्याचरण शुक्ल : विवरण में बताया गया है कि इसकी क्षमता 15 से 20 लाख मेट्रिक टन होगी । क्या यह 19 करोड़ रूबल का ऋण 15 से 20 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के लिए है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह ठीक 15 या 20 लाख मेट्रिक टन ही नहीं होगी, यह इनके बीच की भी अर्थात् 16 या 17 लाख मेट्रिक टन भी हो सकती है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह 19 करोड़ रूबल की रकम 15 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के लिए है या 20 लाख मेट्रिक टन की क्षमता के लिए ?

श्री संजीव रेड्डी : मैंने भी यही उत्तर दिया है । इसकी क्षमता 15 लाख मेट्रिक टन से अधिक है, यह 16 या 17 लाख मेट्रिक टन भी हो सकती है। अभी निश्चित रूप से हम इस बारे में नहीं बता सकते। बातचीत से पहले यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस संयंत्र के लिये इतनी रकम पर्याप्त रहेगी।

श्री मुरारका : सरकार के वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार बोकारो संयंत्र में वास्तविक उत्पादन कब से आरम्भ होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : लगभग 1970 तक।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या यह भी सच है कि बोकारो करार के अनुसार रूस ने भारत की लौह-अयस्क खानों के विकास में भी सहायता करने का आश्वासन दिया है और यदि हां, तो इस बारे में रूस की क्या शर्तें हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। करार में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : इसमें कितने प्रतिशत भारतीयों को रोजगार दिया जाएगा और बोकारो इस्पात संयंत्र में कौन व्यक्ति काम करेंगे ? क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि क्या उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये, जिनकी भूमि इस संयंत्र के लिए ले ली गई है, भी कोई निश्चित योजना बनाई गई है ?

श्री संजीव रेड्डी : इसमें सलाहकारों और मार्ग-दर्शन करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त बाकी सभी व्यक्ति भारतीय होंगे। जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क बनाया हुआ है और हम जितना भी संभव होगा, उनमें से अधिकाधिक व्यक्तियों को गैर-तकनीकी कार्यों पर लगाने का प्रयत्न करेंगे।

काठमांडू में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी

\+

*34. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बरवा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० द० पुरी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल नरेश ने हाल में काठमांडू में भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रदर्शनी की मुख्य बातें क्या थीं ;

(ग) भारतीय उद्योगों के किन पहलुओं का वहां प्रदर्शन किया गया था ; और

(घ) उस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी, 1965 को नेपाल नरेश ने किया था।

(ख) और (ग). विभिन्न प्रकार के भारतीय निर्यात उत्पादों का प्रभावशाली प्रदर्शन इसकी मुख्य बातें थीं। इन में विशाल, मध्यम और लघु उद्योगों की मशीनें, अन्य इंजीनियरी उत्पाद, उपभोक्ता माल, एक आकर्षक वस्त्र मण्डप तथा सभा स्थल विशेषत: उल्लेखनीय है। नेपाल में भारतीय सहायता से चलाई जा रही प्रायोजनाओं पर उपयुक्त ढंग से प्रकाश डाला गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शनी की विशेषता थी जिसके अन्तर्गत फेशन प्रदर्शनी, फिल्म प्रदर्शन, गान तथा वाद्य संगीत और नृत्य प्रस्तुत किये गये।

(घ) प्रदर्शनी के व्यय के लिये 10 लाख रु० स्वीकृत किये गये थे पर चूंकि उसे एक सप्ताह के लिये और बढ़ा कर 15 फरवरी, 1965 को समाप्त किया गया इस लिये उस पर हुए वास्तविक व्यय का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि नेपाल के बाजारों में चीन से और अन्य साम्यवादी देशों से सस्ते एशो-आराम की वस्तुएं और कपड़े काफी मात्रा में पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो नेपाल की मंडी में ऐसे भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के बारे में इस प्रदर्शनी को किस हद तक सफलता मिली है ?

श्री मनुभाई शाह : नेपाल की मंडी में भारतीय वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं आया है। यह सच है कि अन्य देशों से भी कुछ वस्तुएं आ रही हैं। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक स्वतन्त्र देश किसी भी देश से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है।

श्री प्र० चं० बरुआ : यह प्रदर्शनी भारत-नेपाल सहयोग से कौन से उद्योग स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है और वहां पर भारतीय वस्तुओं और उद्योगों के विकास की कितनी गुंजायश पैदा हुई है ?

श्री मनु भाई शाह : जहां तक संयुक्त उपक्रम का सवाल है, एक भारतीय व्यक्ति ने वहां एक ऊन कारखाना स्थापित किया है। एक साबुन कारखाना भी बनाया जा रहा है और एक कपड़ा मिल भी वहां स्थापित की जा रही है। नेपाल में संयुक्त रूप से कारखाने स्थापित करने की संभावनाएं इमारती लकड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग और फलों तथा वनस्पति पर आधारित उद्योगों के बारे में अधिक हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या प्रदर्शनी के आयोजकों ने नेपाली उद्योगपतियों और बड़े लोगों के विचार जानने का प्रयत्न किया है कि क्या वे हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पद्धति के परिणामों से प्रभावित हैं ? यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले ?

श्री मनुभाई शाह वहां पर महाराजा, राज-परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में अन्य व्यक्ति मौजूद थे। बाद की रिपोर्टों से पता चला है कि हमारे नेपाली मित्र भारत में की गयी प्रगति से बड़े प्रभावित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यापारिक और मैत्री सम्बन्ध बढ़ेंगे।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister recently visited Kathmandu. Chinese watches, soap and fountain pens are flooding into Nepal market. May I know the items of Indian goods exhibited in this exhibition so that Nepalese like our goods not of other country's goods ?

Shri Manubhai Shah : According to their statement the goods sold by them contained 97 percent of Indian goods. The rest is other goods. So, there is no case of anxiety. However, we are watching the situation constantly.

श्री तिरुमल राव : यदि मंत्री महोदय प्रदर्शनी में मौजूद थे, तो क्या उन्होंने वहां पर भारतीय वस्तुओं और चीनी वस्तुओं की किस्म और मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ? यदि हां, तो क्या वह इस बारे में कदम उठा रहे हैं जिससे हम सफलतापूर्वक उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

श्री मनुभाई शाह : इस बारे में अध्ययन करने के लिए भारत सरकार अथवा इस सदन ने मुझे वहां नहीं भेजा था। लेकिन मैंने वहां पर भारतीय वस्तुओं की बढ़ती हुई लोकप्रियता और नेपाल की मंडी में भारतीय उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग का अध्ययन किया है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नेपाली नागरिकों ने भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिये प्रस्ताव रखे थे और इस प्रदर्शनी में किसी जलपान-गृह की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी ?

श्री मनुभाई शाह : वहां पर कोई जलपान-गृह तो नहीं था लेकिन चाय की दुकान जरूर थी, क्योंकि वे लोग कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक पीते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों और अन्य विभिन्न वस्तुओं की दुकानें थीं।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister has said that the cultural programme staged there was much appreciated. I want to know as to who staged that programme ? Whether some company or film stars were invited there ?

Shri Manubhai Shah : We had one cultural troupe which staged the programme successfully. There were some Nepalese girls also as we wanted to show them that Indian fabrics would suit them. We also gave chance to all the schools and colleges in Nepal. Indian fabrics were put on them to show their suitability to them.

श्री तुलशीदास जाधव : इस प्रदर्शनी पर कुल कितना व्यय हुआ और हमारी वस्तुओं की बिक्री से कितनी आय हुई ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया है कि 10 लाख रुपये की व्यय की मंजूरी दी गई है। लेकिन यह व्यय लगभग 13 लाख रुपये होगा क्योंकि इस प्रदर्शनी को वहां की सरकार के अनुरोध पर लगभग 10 दिन और बढ़ाना पड़ा है।

Shri R.S. Pandey : On what basis it has been assessed that in Nepal 97 percent Indian goods are being sold.

Shri Manubhai Shah : The officials of that place keep the custom's return. Statistics are maintained all the world over. In the market one can see with his own eyes as to which country's goods command a greater sale. It

is true that the commodities of other countries have also started coming, but we want that all countries should work for diversification of trade.

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दार्जीलिंग और उत्तरी बंगाल में चीन की उपभोक्ता वस्तुएं बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि ये वस्तुएं नेपाल के रास्ते आती हैं अथवा अन्य किन्हीं रास्तों से आती हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है कि नेपाल के रास्ते कुछ वस्तुएं बिहार और पश्चिमी बंगाल में आती हैं जिसका कि चीन के साथ कुछ व्यापार है। निश्चय ही यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सब को कुछ न कुछ चिन्ता होनी चाहिये, परन्तु इस समय हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि अधिक भारतीय वस्तुएं बेच कर व्यापार स्तर पर इसका मुकाबिला किया जाये। परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम दूसरे पहलू पर भी बड़े गौर से विचार कर रहे हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ: यह देखते हुए कि नेपाल की सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि कुछ उद्योगों में वह बहुत रुचि रखती है, जिनके आधार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने अभी बताया, क्या सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में भारतीय सहयोग से ऐसे उद्योग चलाने के लिये उन्हें बुलाने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : हम केवल वे उद्योग ही चला सकते हैं जिन को नेपाल सरकार स्वीकार करती है। क्योंकि इसमें हमारी मर्जी नहीं चल सकती है। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि संयुक्त सहयोग के लिये बड़ी तीव्र इच्छा है। आरम्भ में हम 3 एकक रख रहे हैं। यदि बाद में वे इसे ठीक समझेंगे तो अन्य क्षेत्रों में भी हम सहयोग को बढ़ा सकते हैं।

Shri Vishram Prasad : Was the Industrial Exhibition in Nepal held on the invitation of that Government or on the initiative of the Indian Government itself and the names of the other participating countries ?

Shri Manubhai Shah : Last year when I went there and signed the treaty in which it was provided with the concurrence of both the countries that we should also hold exhibition there and that Nepal Government should also hold exhibition here. I have again sent an invitation to Nepal Government to hold their exhibition this year in India. Such exhibitions are held for furthering cultural and Commercial relations.

Train-Truck Collision near Kharagpur

\+

*35. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri P.C. Borooah :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Yashpal Singh :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri P.R. Chakraverti :
Shri K.N. Tewari :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Narendra Singh Mahida :
Shri Solanki :
Shri Narasimha Reddy :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Bombay-Howrah Express collided with a truck

at an unmanned level crossing between Surdish and Kalaikunda stations near Kharagpur on the 30th December, 1964 ;

(b) if so, the number of persons killed and injured ;

(c) whether any inquiry had been made into the causes of the accident ; and

(d) if so, the findings thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes, sir. The accident occurred between Kalaikunda-Surdiah Block Hut and Kalaikunda stations.

(b) As a result of this accident 2 persons were killed and 3 sustained injuries.

(c) & (d). The case was investigated by a Committee of Railway Officers. According to their findings the cause of the accident was misadventure on the part of motor truck driver, who dashed across the level crossing in the face of the approaching train.

Shri Naval Prabhakar : Did the inhabitants of that place send a representation recently in which it was demanded that a watchman should be kept at that level crossing ?

Shri Sham Nath : No such representation has been received.

Shri Naval Prabhakar: Did the engine driver not pay any attention when the truck was coming to that siding ?

Shri Sham Nath : It is very difficult for the train driver to divert his attention and stop the train. Truck driver should have seen and not tried in this manner to cross the level crossing.

श्री प्र० च० बरुआ : केन्द्रीय सरकार के इस अनुरोध पर राज्य सरकारों ने क्या किया है कि जिन फाटकों पर कोई आदमी नहीं है वहां आदमी रखना चाहिये ?

श्री शाम नाथ : कुछ राज्य सरकारों से हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने सूचियां भेजी हैं जिनमें सुझाव दिया गया है कि खास फाटकों पर आदमी रखे जाने चाहियें ।

Shri A. P. Sharma : The hon. Deputy Minister just now said that the enquiry carried by Railway officers Committee has established the responsibility of the truck driver. May I know who will be liable for damages to the representatives of the deceased two persons, whether Railway will pay the damages or no damages will be paid ?

Shri Sham Nath : The truck driver was at fault and there was no negligence on the part of the Railway in this accident. Therefore, the question of giving compensation does not arise.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether the State Governments have agreed to share the expenditure for manning unmanned level crossings in view of the increasing number of accidents on such crossings ?

The Railway Minister (Shri S. K. Patil): That has already been decided. There are about 1200 important unmanned level crossings and the recurring annual expenditure will be borne by the Centre and the initial cost of manning by the States. In other States, such as Gujarat where there are more level

crossings, we shall bear more expenditure. But this is the question of only 1200 crossings and not all.

श्रीमती रेणुका राय : इस क्षेत्र में क्या किसी बिना चौकीदार वाले फाटक पर कोई पुलिस का सिपाही या अन्य कोई व्यक्ति तैनात किया गया है, और यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री स० का० पाटिल : किसी भी स्थान पर पुलिस के सिपाही को तैनात करने का कोई प्रश्न नहीं है । वहां पर एक रेलवे अधिकारी होता है जो किसी नौकर या चौकीदार को रख सकता है । परन्तु इसके बावजूद भी भारत में ऐसे हजारों फाटक होंगे । सभी फाटकों पर आदमी नहीं रखा जा सकता । दुनिया में कहीं भी सभी फाटकों पर आदमी हों ऐसा नहीं है ।

डा० मा० श्री अणे : क्या सरकार इस बात को मानती है कि जब तक उन फाटकों पर कोई चौकीदार नहीं रहता तब तक रेलवे की जिम्मेवारी होगी ?

श्री स० का० पाटिल : सरकार ऐसा नहीं मानती ।

Shri Yashpal Singh : In view of the fact that Railway is earning crores of rupees and Railway Ministry is also earning a lot by selling the trees which fall within its boundary, what are the reasons for writing to the State Governments so often and not arranging for manning those unmanned level crossings itself ?

Mr. Speaker: It cannot be arranged for 30-32 thousand.

Shri Yashpal Singh : The Minister told 19,000. You have reduced our one crossing.

Shri Sarjoo Pandey : There are many places, especially in U.P. where there is much of traffic and the State Governments are not prepared to share the expenditure, but central Government is considering manning the unmanned level crossings there. May I know what steps Government is going to take in that regard ?

Shri S. K. Patil : The responsibility is after all of the Government of India. But in every state new roads have been opened and that does not mean that at all level crossings it is our responsibility.

Mr. Speaker : If State Governments do not give their share of expenditure for manning unmanned level crossings then what the Central Government is going to do ?

Shri S. K. Patil : They have agreed to that. There is no difference of opinion in that regard.

श्री स० मो० बनर्जी : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि चालक का दोष था, इसलिये कोई मुआवजा नहीं दिया गया था । ऐसे मामलों में जब कि फाटकों पर आदमी नहीं रखा जा सकता है जांच का स्वरूप क्या है और कौन जांच करता है--रेलवे अधिकारी या न्यायिक अधिकारी ?

श्री शाम नाथ : रेलवे अधिकारी ।

श्री स० मो० बनर्जी : रेलवे तो स्वयं एक पक्ष है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि जांच कौन करता है और जब वे उत्तर देते हैं कि "रेलवे अधिकारी" तो यह आपत्ति उठाई जाती है कि वे तो इस मामले में एक पक्ष हैं और उनको जांच नहीं करनी चाहिये। सदस्यों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये।

Shri S. N. Chaturvedi : What is the fault of the deceased and why the question of giving them compensation is not being considered?

Mr. Speaker: Their fault lies in travelling by that truck.

दुर्गापुर में मिश्रित इस्पात परियोजना

\+

*36 **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर में इस्पात के ढांचों के निर्माण और मिश्रित इस्पात परियोजना की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना का पुनरीक्षित कार्यक्रम क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) विदेशों से संयंत्र तथा मशीनें कब तक आयेंगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) लगभग 27,000 टन इस्पात ढांचों की कुल आवश्यकता के मुकाबले में, लगभग 9700 टन ढांचे तैयार हो चुके हैं और लगभग 5000 टन स्थल पर खड़े किये जा चुके हैं।

(ख) विभिन्न इकाइयों--गढ़ाई का कारखाना, छड़ें तैयार करने का कारखाना, इस्पात पिघलाने का कारखाना नं० 1, चादरें बनाने का कारखाना और ब्लूमिंग और बिलेट मिलों के सितम्बर, 1966 और अगस्त, 1967 के बीच चालू होने की संभावना है। इस्पात पिघलाने का कारखाना नं० 2, 23 जनवरी, 1965 को चालू हुआ था।

(ग) प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग 67 करोड़ रुपये है।

(घ) अधिकतर उपकरण जापान से आ रहे हैं और अप्रैल, 1964 से आने आरम्भ हो गये हैं। समस्त उपकरणों के 1966-67 तक पहुंच जाने की संभावना है। अन्य उपकरणों की आमद की अनुसूची इस प्रकार बनाई गई है कि वह विभिन्न कारखानों के प्रस्तावित परिचालन की अनुसूची से मेल खाती रहे।

श्री स० चं० सामन्त : उन देशों के क्या नाम हैं जिन से इस समय ये संयंत्र और मशीनें आयात की जा रही हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी: जैसा कि मूल उत्तर में बताया जा चुका है, अधिकांश संयंत्र और मशीनें जापान से आयेंगी, लेकिन धमन भट्टी आदि के कुछ भाग ब्रिटेन से भी आयेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या जापान से ये संयंत्र और मशीनें खरीदने से पूर्व संसार के सभी देशों से टेन्डर मांगे गये थे ?

श्री प्र० चं० सेठी: जी, हां । जून, 1962 में संसार के सभी देशों से टेन्डर मांगे गये थे ।

श्री सुबोध हंसदा : जहां तक जापान से आने वाले अधिकांश साज-सामान का सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम में कम से कम धमन भट्टी बनाने के बारे में कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी: जी, नहीं । भारी इंजीनियरी निगम में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता । ये कनाडा के मेसर्ज़ एमको से मिलेंगी क्योंकि ये विशेष प्रकार की हैं जिनको यहां नहीं बनाया जा सकता ।

श्री प्र० च० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि संयंत्र के प्रथम चरण को पूरा करने के लिए कितनी भारतीय तकनीकी जानकारी उनको दी गयी और विदेशी सहयोगी किस हद तक हमारी सहायता कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस संयंत्र को बनाने और चालू करने के लिये हमारे पास एक विदेशी परामर्शदाता है और हम उनके सामान्य निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन काम कर रहे हैं ।

श्री कृ० च० पंत : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल रूप से निर्धारित समय का पालन किया जा रहा है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी: मूल रूप से निर्धारित समय का विभिन्न कारणों से पालन नहीं किया जा सका है । संयंत्र और इमारत के डिज़ाइन में फेर-बदल का बाद में पता लगा । इसके अतिरिक्त सलाहकार फेब्रिकेटरों और सप्लायरों से भी ड्राइंग के मिलने में विलम्ब हुआ । इसके अतिरिक्त श्रमिकों ने हड़ताल की और धीरे चलो की नीति अपनाई । अतः मूल रूप से निर्धारित समय को बदलना पड़ा ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या यह सच है कि परियोजना में किसी संरचना ठेकेदार द्वारा गड़बड़ी के कारण संरचना-कार्य में बड़ा विलम्ब हुआ और यदि हां, तो वे ठेकेदार कौन लोग हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : संरचना-कार्य में विलम्ब तो हुआ है लेकिन अब हम इसमें शीघ्रता कर रहे हैं और स्थिति में काफी सुधार हुआ भी है ।

श्री मुहम्मद इलियास : भारतीय ठेकेदार द्वारा की गयी गड़बड़ी के बारे में क्या उत्तर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): यह भी एक कारण है लेकिन विलम्ब होने का यह मुख्य कारण नहीं है । ठेकेदार भी लक्ष्य के अनुसार कार्य नहीं कर सका लेकिन इसके कुछ अन्य कारण भी हैं जिन के बारे में अभी मेरे साथी ने बताया है ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या मंत्री महोदय ठेकेदारों के नाम बतायेंगे ? मेरा मुख्य प्रश्न यह है ।

श्रीसंजीव रेड्डी : मेरे पास ठेकेदार का नाम नहीं है । लेकिन मेरे साथी ने अभी विलम्ब के कई कारण बताये हैं जिनके कारण निर्धारित समय में परिवर्तन करना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा बताया गया है, विलम्ब होने का एक कारण एक ठेकेदार द्वारा देरी किया जाना है और इसलिये प्रश्न उठता है कि उस ठेकेदार का क्या नाम है । मंत्री महोदय का कहना है कि इस समय ठेकेदार का नाम उनके पास नहीं है ।

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां । नाम मेरे पास नहीं हैं । लेकिन मैंने बताया है कि यह भी एक कारण है ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, आप कृपया मंत्री महोदय से नाम बताने को कहें ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Such a big job has been entrusted to them and their names are not known ?

Mr. Speaker: The name is not with him at present. If the Hon-Members insist, the names will be given. There is nothing extraordinary in it.

श्री प्र० के० देव : क्योंकि देश में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन नहीं होता और इसके लिये आयातित इस्पात की बड़ी मांग है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दुर्गापुर स्थित इस मिश्र-धातु इस्पात परियोजना में स्टेनलेस स्टील बनाने की कोई योजना है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसका भी उत्पादन किया जाएगा । वहां पर लगभग 18,000 टन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाएगा ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह बात कहां तक सच है कि हमारी परियोजनाओं में ऐसी अनेक मशीनें बनाई गई और इनके समन्वय के अभाव में इन संयंत्रों और मशीनों की खरीद के लिये आदेश दिया गया है और इस पर अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह बात सही नहीं है । यह तो विशेष इस्पात परियोजना के लिए आवश्यक मशीनों का प्रश्न है । उनको यहां बनाना संभव नहीं है और इसीलिए इनके लिए संसार के सभी देशों से टेन्डर मांगे गये थे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of contractors who submitted their tenders and whose quotations were the lowest and whose quotations were the highest and the names of contractors ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

Shortage of Cement

\+

*37. **Shri Prakash Vir Shastri ;**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri R. S. Tiwary :
Shri Yashpal Singh :
Shri Sidheshwar Prasad :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Man Singh P. Patel :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shrimati Ramdulari Sinha :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to refer to the reply

given to Starred Question No. 364 on the 4th December, 1964 and state the further steps taken to remove the shortage of cement ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : The Cement Corporation of India has been registered on 18-1-1965 as a private limited company fully owned by Government with an authorised capital of Rs. 5 crores. The new slag cement factory at Jamul has gone into production. An expansion scheme for an additional capacity of 100,000 tonnes of cement has been commissioned for full production at Panyam (Andhra Pradesh). Out of the existing 38 factories, production during 1964 at twenty factories has been higher than in the year 1963.

Shri Prakash Vir Shastri : During the last session of Parliament, this question was raised that for food production lack of irrigation facilities were due to shortage of cement. I want to know whether the Government have made efforts in this direction so that sufficient cement is made available for irrigation needs ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, हां । उत्पादन बढ़ रहा है और निश्चय ही ऐसा किया जाएगा ।

Shri Prakash Vir Shastri : My question was different.

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बारे में उपाय किये गये हैं कि लोगों को सिंचाई साधनों के लिए सीमेन्ट मिल सके ।

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh) : There is shortage of cement but as the supply is made, we try to give more cement for irrigation needs.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the time by when this shortage of cement will be made up ?

Shri T. N. Singh: I presume that if the plans of the Cement Corporation and Private Sector go ahead expeditiously, within 3 years this problem is likely to be solved.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Cement factory owners acquire the land surrounding the factory but do not fulfill their obligation to pay compensation. I want to know whether this responsibility is of the Central Government or the State Governments ? If this is the responsibility of the State Governments, whether the Central Government would compel the State Governments to fulfil their duties to pay compensation ?

Mr. Speaker : Whether land is acquired for production of cement ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The land may be taken for any purpose.

Mr. Speaker : Then it is a general question and cannot be taken now.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The farmers should be paid due compensation.

Mr. Speaker : This is a general question and this can be taken up at the time of discussion of the President's Address.

श्री मानसिंह पृ० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में सीमेन्ट के निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी है और नये कार्यों को मंजूरी दिये जाने

को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सिंचाई कार्यों के लिए सीमेन्ट की मांग को पूरा करने के लिए दो वर्षों में सीमेन्ट की उपलब्धि की स्थिति में सुधार कर सकेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस मामले में केवल सरकार की जिम्मेदारी का कोई प्रश्न नहीं है । यह अभी तक गैर-सरकारी क्षेत्र का उद्योग है । गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिन कारखानों के लिए लाईसेंस दिए गए हैं उनमें से अधिकांश अभी लगे नहीं हैं । कमी का यह भी एक कारण है । इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को विवश होकर सीमेन्ट निगम स्थापित करना पड़ा है जोकि सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की देखभाल करेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सीमेन्ट के स्थान पर 'पोज़ोलीन' नामक वस्तु का, जो भाखड़ा बाँध के आसपास उपलब्ध है, प्रयोग किया गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : वास्तव में हाल में कुछ नये लाईसेंस दिये गए हैं । मैं निश्चित स्थान के बारे में नही बता सकता । लेकिन जहां तक मुझे पता है एक लाईसेंस राजगंगपूर के लिए दिया गया है ।

Shri Yashpal Singh : May I know the total demand and the shortage in supply ? Will the Government lay on the table the figures of the shortage?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : आज मांग 120 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष है और सप्लाई लगभग 100 लाख मेट्रिक टन है । इस प्रकार 20 लाख मेट्रिक टन की कमी रहती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग उन्हें नीचा न दिखाएं और उन्हें लक्ष्य पूरा करने दें ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जैसे बताया चुका है, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए "भारत का सीमेन्ट निगम" बनाया है ।

श्री पु० र० पटेल : बड़ी बड़ी फर्मो को तो शहरों में इमारतें बनाने के लिए सीमेन्ट मिल जाता है लेकिन बेचारे किसानों को कुओं और अन्य सिंचाई साधनों के लिए भी सीमेन्ट नहीं मिल पाता ?

एक माननीय सदस्य : वे चोरबाजारी मूल्य नहीं दे सकते ।

श्री त्रि० ना० सिंह : हम सीमेन्ट राज्य सरकारों को आवंटित करते हैं जो उसका वितरण करती है । हम सीधे केन्द्र से सीमेन्ट का वितरण नहीं करते हैं ।

Shri A. S. Saigal : May I know the number of applications received from private sector for the setting up of new cement factories and the number of cement factories Government propose to set up in the public sector during the Fourth Plan ?

Shri T. N. Singh : Atpresent it is difficult to give this detail as the complete list of the applications in connection with the private sector is not with me. So far as the Government corporation is concerned, we are making enquiries at certain places for the cement limestone and the programme of production will be chalked out after the investigation proceedings are complete.

श्री जसवन्त मेहता : हाल ही में उन व्यक्तियों की, जिनको सीमेन्ट के उत्पादन के लिए लाईसेंस दिए गए हैं, एक बैठक बुलाई गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में लाईसेंसधारियों ने सीमेन्ट का उत्पादन अभी आरम्भ नहीं किया है हालांकि उनको लाईसेंस दो वर्ष पूर्व

दिये जा चुके हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जारी किए गए नये लाईसेंसों के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : इसके लिए वह दूसरे प्रश्न की सूचना दें ।

Shri Braj Raj Singh : In view of the shortage of cement which is not even available for smaller projects of agriculturists, are Government considering stopping the use of cement in construction of memorials of leaders ?

Mr. Speaker : But will this solve the problem ?

श्री स० मो० बनर्जी : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कमी राज्य सरकारों द्वारा सीमेन्ट के गलत ढंग से वितरण के कारण है, यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास इस बारे में क्या व्यवस्था है कि वितरण ठीक प्रकार हो ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं तो यह कहूंगा कि राज्य सरकारें इसका उचित और समान वितरण करने के लिये भरसक प्रयत्न करती हैं । मैं उन पर आदेश तो चला नहीं सकता ।

Shri D. N. Tiwari : It has just now been said that certain licencees in the private sector have not yet established cement factories. Could the Government not establish their cement factories in places where those licencees in the private sector proposed to establish cement factories ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी, हां; कुछ लाईसेंस रद्द किए गए हैं क्योंकि उन लोगों ने कारखाने स्थापित नहीं किये । सरकार सीमेन्ट निगम की सहायता से इन सब का अध्ययन करेगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मेरा प्रश्न यह था कि उन स्थानों पर जहां लाईसेंस रद्द किए गए हैं, क्या सरकार वहां सरकारी क्षेत्र में कारखाने स्थापित करने की संभावना पर विचार करेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यदि कोई गैर-सरकारी पार्टी इसके लिये तैयार नहीं हुई तो सीमेन्ट निगम इस बारे में विचार करेगा ।

डा० मा० श्री० अणे : सीमेन्ट की कमी और इसकी बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन सभी खानों में काम शुरू करने का प्रयत्न कर रही है, जहां सीमेन्ट उपलब्ध है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हमारी औसत क्षमता लगभग 13 प्रतिशत है । लेकिन ऐसे भी कारखाने हैं जहां शत प्रतिशत काम हो रहा है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not a fact that the Government proposed to establish cement factories in the public sector because no licencee in the private sector could establish them so far ?

Shri T. N. Singh: It is not so that they have totally failed. Some parties have established factories and expanded them.

Shri Bhagwat Jha Azad: Not even one has established any factory for the last five years.

Shri Gulshan : It was said that cement is given for irrigation facilities. I would like to know whether the Government are peeping in view the needs of cement of the agriculturists in Punjab ?

Mr. Speaker : No question can be put concerning a particular State.

Dr. L. M. Singhvi : So far as the establishment of cement factories in the public sector is concerned, whether the Government have agreed in principle to establish factories at places where limestone and gypsum were available ? Whether it is also in the knowledge of the Government that they were not established at those places ?

Shri T. N. Singh : Sir, I could not follow.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम

*32 { **श्री प्रभात कार :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार निगम की गतिविधियों का विस्तार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री लालभाई शाह) : (क) और (ख). मौजूदा परिस्थितियों में राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का काम बढ़ना अनिवार्य है । ऐसा इन निगमों के नियम उपनियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है । निगमों के कार्यों को जिस रूप में सरकार ने स्वीकृति दी है उनके अन्तर्गत मोटे तौर पर जो उद्देश्य आते हैं उन्हें संलग्न विवरण में दिया गया है जिसे सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) राज्य व्यापार वाले देशों के साथ समान्य रूप में और अन्य देशों के साथ उन वस्तुओं का व्यापार करना जो कि निगम को सौंपी जायं ।

(ख) निर्यात की पुरानी वस्तुओं के लिये और भी बड़े बाजार खोजना तथा नई वस्तुओं के निर्यात का विकास करना जिससे निर्यात व्यापार को बढ़ाया तथा विविध प्रकार का किया जा सके ।

(ग) सरकार के कहने पर कमी वाली किसी भी वस्तु का आयात करना अथवा उसका आन्तरिक वितरण करना जिससे मूल्य स्थिर किये जा सकें और वितरण को युक्तियुक्त किया जा सके ।

(घ) समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित वस्तुओं के आयात तथा निर्यात का विभिन्न माध्यमों से संचालित करना ।

(ङ) सरकार द्वारा जनहित के लिये निर्धारित विशेष वस्तु वर्गों के आयात निर्यात और अथवा आन्तरिक वितरण के लिये वस्तुओं के विनिमय, अदला-बदली आदि के विशेष प्रबन्धों को सामान्य रूप से अमल में लाना ।

(च) आन्तरिक अर्थव्यवस्था के मूल्य स्थिर करने के उपायों द्वारा सहायता देने के उद्देश्य से समीकरण भंडार चलाना ।

नेपाल और पाकिस्तान के बीच व्यापार के लिए पारगमन सुविधायें

*38. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल की सरकारों के बीच इस मांग के बारे में समझौता हो गया है कि नेपाल को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिये आने-जाने की सुविधा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) नेपाल पाकिस्तान व्यापार के लिये 1 फरवरी, 1965 में राधिकापुर होकर परिवहन की सुविधाएं देना मंजूर कर लिया गया है । इसके लिये एक वैगन से कम माल पर 9 पैसे प्रति क्विन्टल अथवा उसके भाग पर रेलभाड़ा लिया जायेगा । पूरे वैगन के माल पर 6 पैसे प्रति क्विन्टल अथवा उसके भाग पर रेलभाड़ा लिया जायेगा ।

आय वित्त समिति

*40. **श्री ज० ब्र० सिंह :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चाय वित्त समिति की मुख्य सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : चाय वित्त समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों पर सरकार शीघ्रता से विचार कर रही है ।

आयात नीति

*41. श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाली चालू छमाही के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं के आयात कोटे में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) वे कौन-कौन से उद्योग हैं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह :) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) . लघु उद्योगों सहित, अनुसूचित एवं गैर-अनुसूचित, दोनों क्षेत्रों के वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले लायसेंसों और इन वास्तविक उपभोक्ताओं को वर्ष की दूसरी छमाही अक्तूबर, 1964 से मार्च, 1965 में दिये जाने वाले पूरक लायसेंसों में अपेक्षित सीमा तक कुछ कटौतियां की गई हैं । वर्ष की दूसरी छमाही, अक्तूबर, 1964 से मार्च, 1965 के आयातों में यथासंभव न्यूनतम सीमा तक कटौती करने के प्रयास किये गये हैं । चूंकि कटौती नाममात्र होगी, अतः उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ।

उपभोक्ता उद्योग

*42. श्री मोहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ह्रे० वी० कौजलगी :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) किस प्रकार के उद्योग खोले जायेंगे; और

(घ) इन उद्योगों में कुल कितना धन लगाया जायेगा ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ). आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुयें तैयार करने वाले कुछ उद्योगों के अपर्याप्त विकास को देखते हुए अब इन उद्योगों का सरकारी क्षेत्र में विकास करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इन प्रस्तावों का ब्योरा अभी तैयार किया जाने को है ।

सरकारी उपक्रम

*43. श्री ईडा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान वाणिज्य मंत्री के उस अभिभाषण की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने 27 दिसम्बर, 1964 को नई दिल्ली में हुई सरकारी उपक्रमों के मुख्य प्रबन्धाधिकारियों तथा वित्तीय सलाहकारों की गोष्ठी में दिया था;

(ख) क्या विभिन्न निर्माण एककों को एक साथ न रखने का कोई नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये और क्या निश्चय किये गये हैं ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) क्योंकि हर एक मामले की गुणाधार पर जांच करने के बाद एक उचित संगठन को बनाना है अतः नीति सम्बन्धी कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(ग) कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए तो अनवरत प्रयास करना होता है और उस पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

*44. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **उद्योग और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के प्रशिक्षणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या आजकल बेकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको काम पर लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). हैवी इलेक्ट्रिकल्स में उन 597 प्रशिक्षणार्थियों को काम में लगाने के लिये खाली जगहें नहीं हैं जिनका प्रशिक्षण पूरा होने वाला है। प्रबन्धकों द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों तथा सरकारी संगठनों में रोजगार दिलाने के लिये अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। अब तक इसी प्रकार के काम में 114 प्रशिक्षणार्थी लगाये

जा चुके हैं तथा 4 प्रशिक्षणार्थी अपनी इच्छा से हैवी इलेक्ट्रिकल्स को छोड़ कर चले गये हैं। शीघ्र ही 137 और प्रशिक्षणार्थियों को भी इसी प्रकार का काम दिलाने के प्रयत्न जारी हैं ।

भिलाई इस्पात परियोजना

*45. **श्री बड़े :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 18 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात परियोजना के विस्तार कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : 215 मिलियन टन विस्तार कार्यक्रम के अधीन स्लेग ग्रेनुलेशन प्लांट, कोक ओवन बैट्री नं० 4, खुले मुंह की भट्टी नं० 7, धमन भट्टी नं० 4, सोख गडेढे ग्रुप नं० 6, 7 और 8, टर्बो जनरेटर नं० 3, भाप बायलर नं० 4 और टर्बो ब्लोअर नं० 5 चालू हो चुके हैं। अन्य इकाइयों का निर्माण-कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा हैं ।

छटी धमन भट्टी और सम्बद्ध सुविधाओं के बारे में सोवियत संघ, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन तथा अन्य देशीय स्रोतों से मंगवाये जाने वाले साज़-सामान की अलग-अलग सूचियां तैयार की गई हैं और सम्बद्ध एजेंसियों को दे दी गई हैं ।

रूस से सीसे का आयात

*46. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रूस से सीसे का आयात रुपयों में भुगतान करने के आधार पर कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उपयोग छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा किया जायेगा; और

(ग) इससे उनकी वर्तमान मांग कहां तक पूरी होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) रूस से सीसे का आयात खनिज तथा धातु निगम की मार्फत किया जाता है । रूस से होने वाला सीसे का तथा अन्य सभी आयात भारत तथा रूस के मध्य हुए व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों से किया जाता है ।

(ख) यह आयात मुख्यत: लघु तथा अनुसूचित उद्योगों के स्वयं उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये किया जाता है ।

(ग) आयातित सीसे का वितरण दोनों की आवश्यकताएं ध्यान में रख कर किया जाता है ।

कच्चा लोहा सम्बन्धी तकनीकी समिति

*47. **श्री रा० स० पाण्डेय :**
श्री उइके :
श्री राधेलाल व्यास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस तकनीकी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जो तकनीकी सुधारों द्वारा वर्तमान इस्पात संयंत्रों की धमन भट्टियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिये नियुक्त की गई थी ताकि कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

धमन भट्टियों में लोहे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कच्चे माल को तैयार करने तथा प्रौद्योगिक सुधार करने के विभिन्न उपायों पर सरकार को परामर्श देने हेतु स्थापित की गई तकनीकी समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

दीर्घकालीन कार्यक्रम :—

1. धमन भट्टियों के लिये लोह खनिज, कोक और चूना पत्थर के प्रच्छादन और आकार को अनुकूलतम करना ।
2. लोह खनिज विशेषत: बारीक खनिज का ठीक परिष्करण ।
3. कोक भट्टियों में धोये हुये और सुखाये गये कोयले का इस्तेमाल ।
4. सिन्टर का उपयोग-सेल्फ-फ्लक्सड-सुपर बेसिक फ्लक्सड सिन्टर—यथा समय पैलेट्स के उपयोग का भी परीक्षण किया जाय । सिन्टर की मिक्सड फायरिंग को भी शुरू करना चाहिए ।
5. धमन भट्टियों में हाई टॉप प्रेसर आप्रेशन का उपयोग ।
6. धमन भट्टियों में फालतू लाइट नैपथा का अन्त: क्षेपन ।

अल्पकालीन कार्यक्रम :

1. सभी इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल का अर्थात् लोह खनिज, कोक और चूने के

पत्थर की पर्याप्त मात्राओं में लगातार और नियमित संभरण। इस्पात संयंत्रों में कम से कम 3 सप्ताह तक पर्याप्त कच्चे माल का भंडार करने की व्यवस्था।

2. सभी धमन भट्टियों में आयल इन्जैक्शन सम्मिलित किये जाने चाहिए।

3. 850 डिग्री सेंटीग्रेड और इससे अधिक उच्च धमन तापमान शुरू किया जाना चाहिए।

4. कोयला शोधनशालाओं में शोधित कोयले को सुखाया जाना चाहिए। ऐसे कोयले का बराबर संभरण होना चाहिए जिसमें राख की मात्रा एक सम हो और इसकी राख की मात्रा को बढ़ने नहीं देना चाहिए।

5. छोटे साइज के सक्रैप को धमन भट्टियों में डालना।

6. इस्पात संयंत्रों में पिग कास्टिंग मशीनें अथवा पिघले हुए अपिधम लोहे को दानेदार बनाने की मशीनें लगाना।

7. धमन भट्टियों में नट कोक का इस्तेमाल बन्द होना चाहिए।

दुर्गापुर में कांग्रेस का अधिवेशन

*48. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री सेझियान :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1965 में दुर्गापुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दिनों में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया था तथा विशेष गाड़ियां चलाई गई **थीं;**

(ख) रेलवे ने इस पर कुल कितना व्यय किया; और

(ग) दुर्गापुर में बिके टिकटों तथा उस अवसर पर चलाई गई विशेष गाड़ियों से रेलवे को कुल कितनी आय हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नये फ्लैग स्टेशन की व्यवस्था पर 4.60 लाख रुपये का शुद्ध खर्च हुआ।

(ग) दुर्गापुर और विधान चन्द्र स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से और स्पेशल गाड़ियों सहित सभी गाड़ियों से आने वाले यात्रियों से लगभग 4.08 लाख रुपये की आमदनी हुई।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

*49. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का रुई बोर्ड इस बात से सहमत हो गया है कि ब्रिटेन

के लिए भारत में बने निर्यात योग्य कपड़ों का 1965 में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक कोटा रखा जाये;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी होगी; और

(ग) इस नये करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) यह वृद्धि 270 लाख वर्ग गज से बढ़ कर 325 लाख वर्ग गज हुई है ।

(ग) करार की एक प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी; देखिये संख्या एल० टी–3797/65]**

खानों का वैमानिक सर्वेक्षण

*50. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री 20 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 87 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण की सहायता से कुछ खनिज क्षेत्रों का विस्तृत वैमानिक सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी,हां ।

(ख) प्रस्ताव अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेंसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के हेतु भेजा गया है । जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण होना है उनका पक्का निर्णय नहीं हुआ है ।

खानों के मुहानों पर कोयला

*51. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों के मुहानों पर काफी मात्रा में कोयला जमा हो गया है ; और

(ख) इस स्टाक को वहां से हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का संचय 1-2-63 को 4.79 मिलियन मीट्रिक टन था । बढ़ती केवल 0.32 मिलियन मीट्रिक टन ही है ।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के संचय को कम करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं जैसे :---

(1) नीची श्रेणी के कोयले तथा साफ्ट कोक के वितरण नियन्त्रण को शिथिल करना ।

(2) ईंट के भट्टों तथा साफ्ट कोक के डिपो खोलने के बारे में लाइसेंस देने की नीति में उदा ता ;

(3) राज्य शासनों को मन्त्रणा दी गई है कि वे कोयले पर आधारित उद्योगों की बढ़ती में प्रोत्साहन दें तथा औद्योगिक भट्टियों में लकड़ी तथा लकड़ी के कोयले के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाये ।

(4) उपभोक्ता, उनका कोटा कुछ भी हो, कोयला प्राप्त कर सकते हैं ।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना

*53. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने भारत को ऋण देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण की कुल कितनी रकम है ; और

(ग) वह किन शर्तों पर दिया जायेगा ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) ब्रिटिश सरकार ने चौथी योजना अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की लागत के लिए आवश्यक सहायता देना सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है । ऋण की रकम और शर्तों के बारे में अभी तक समझौता नहीं हुआ है ।

केरल में औद्योगिक बस्तियां

*54. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री ओट्टेकाट्ट :

क्या **उद्योग और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में निजी क्षेत्र में तीन औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम इस योजना के लिए ऋण देने को राजी हो गया है ;

(ग) इन बस्तियों को स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) ये एकक कहां-कहां खोले जाएंगे ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा यथा समय इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

धनुषकोटि में दुर्घटना

*55. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्रीमती अकम्मा देवी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :
श्री ह० वी० कौजलगी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांबान और धनुषकोटि के बीच जाती हुई एक भरी हुई यात्री गाड़ी 23 दिसम्बर, 1964 को वहां आये भयंकर तूफान में पूरी तरह नष्ट हो गई ;

(ख) यदि हां, तो इसमें जान और माल की कुल कितनी हानि हुई ;

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मारे गए कुल व्यक्तियों के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, रेलगाड़ी में 100 से अधिक व्यक्ति थे। इस रेलवे दुर्घटना के फलस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान 3,70,000 रुपया लगाया गया है। सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में अभी कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) इस दुर्घटना की तीन वरिष्ठ रेलवे पदाधिकारियों की एक समिति ने जांच की और उनकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

व्यापार गृह

*56. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री विदेशों में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े विभागीय स्टोरों जैसे भारतीय व्यापार गृह स्थापित करने सम्बन्धी 18 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 578 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) अब तक ऐसे कितने व्यापार गृह खोले गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) यह मामला निर्यात संवर्द्धन परिषदों और हांगकांग तथा सिंगापुर स्थित हमारे व्यापार कार्यालयों को भेज दिया गया है।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

*57. **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम का उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच नयी परियोजनाओं की तथा और विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-3798/65।]**

पांचवा इस्पात कारखाना

†58. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री म० ला० त्रिवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सेझियान :
श्री के० द० पुरी :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कोल्लावेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री कोया :
श्री रा० बरुआ :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन-अमरीका इस्पात व्यापार संघ ने सरकारी क्षेत्र में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं। भारत में पांचवें इस्पात संयन्त्र के स्थल के बारे में ब्रिटिश अमेरिकन स्टील वर्क्स फार इण्डिया कन्सार्टियम की सिफारिशों के मई, 1965 तक मिल जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका के आयात-निर्यात बैंक से ऋण

*59. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के आयात-निर्यात बैंक ने बनारस लोकोमोटिव कारखाने को वित्तीय सहायता देने के लिये 1 करोड़ 70 लाख पौंड का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) वाराणसी डीज़ल रेल इंजन कारखाने पर विदेशी मुद्रा के खर्च में मदद देने के लिए वाशिंगटन के आयात-निर्यात बैंक ने अभी हाल में 170 लाख अमरीकी डालर का कर्ज़ मंजूर किया है।

(ख) औपचारिक करार पर अभी दस्तख़त होने बाकी हैं। लेकिन, कर्ज़ पर बैंक की चालू मानक दर, अर्थात् 5 प्रतिशत सालाना दर पर सूद लगेगा और इसकी अदायगी 1968 से शुरू होकर 12 वर्षों में की जायेगी।

(ग) वाराणसी कारखाने में 80 डीज़ल रेल इंजन तैयार करने के सिलसिले में संयुक्त राज्य अमरीका से सामान और रेल इंजन के पुर्ज़े खरीदने और उन्हें समुद्री जहाज से भारत भेजने और इंजनों के निर्माण से सम्बन्धित सेवाएं प्राप्त करने पर जितना खर्च आयेगा, उसकी अदायगी इस कर्ज़ से की जायेगी।

बख्तियारपुर में रेलवे पुल

44. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे पर बख्तियारपुर में रेलवे पुल के निर्माण कार्य में गत तीन महीनों में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पुल को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने बख्तियारपुर में सड़क के ऊपरी पुल के लिये मंजूरी नहीं दी है और इसके लिये पूर्वी रेलवे द्वारा बार बार स्मरणपत्र जारी किये जा रहे हैं ताकि वे काम शुरू कर सकें।

अमरोहा स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से नीचे उतर जाना

45. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1965 की रात्रि को उत्तरी रेलवे के दिल्ली–मुरादाबाद विभाग पर अमरोहा में एक इंजन माल गाड़ी के एक डिब्बे सहित पटरी से उतर गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का विवरण क्या है; और

(ग) जान तथा माल की यदि कोई हानि हुई तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां। एक इंजन और एक 'लोको रेस्ट वेन' दुर्घटनाग्रस्त हुए न कि माल गाड़ी का डिब्बा।

(ख) शंटिंग करते समय गाड़ी संख्या एम 38 डाउन वने गुड्स का इंजन एक लोको रेस्ट वेन सहित पाइंटों पर पटरी से उतर गया।

(ग) दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई। अनुमान लगाया जाता है कि रेलवे को लगभग 663 रु० की हानि हुई।

दिल्ली क्षेत्र में रेल का ऊपरी पुल

46. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्षेत्र में रेलवे के ऊपरी पुलों की ठीक प्रकार से मरम्मत की जा चुकी

है तथा उनको चौड़ा कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी मरम्मत कब तक हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) दिल्ली क्षेत्र में पुल बंगिश, डफरिन और पुल मिठाई तीन पुलों को चौड़ा किया जा रहा है।

(ख) जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है पुल बंगिश का काम पूरा हो गया है । आशा है कि डफरिन पुल का काम 31-3-1965 तक और पुल मिठाई का काम 30-6-1965 तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) इन पुलों को चौड़ा करने की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

(एक) पुल बंगश . . .	1,98,768 रु०
(दो) डफरिन पुल . . .	1,57,036 रु०
(तीन) पुल मिठाई . .	3,80,981 रु०

मुगलसराय-कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण

47. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के मुगलसराय–कानपुर सेक्शन का विद्युतीकरण प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) विद्युतीकरण कब पूरा हो जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) मुगलसराय–इलाहाबाद सेक्शन (157 मार्ग किलोमीटर) पर काम पूरा होने वाला है । इलाहाबाद–कानपुर सेक्शन (192 मार्ग किलोमीटर) के कार्य की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) मुगलसराय–इलाहाबाद सेक्शन पर काम पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 1965 है । परन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि इलाहाबाद–कानपुर सेक्शन पर यू० पी० स्टेट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड समय पर सब-स्टेशन बना दे ।

विवरण

इलाहाबाद-कानपुर सेक्शन पर विद्युतीकरण कार्य की प्रगति (192 आर० किलोमीटर)

असैनिक इंजीनियरिंग कार्य :

(क) यार्ड का ढांचा बदलना	87.5 प्रतिशत
(ख) पैदल पुल में परिवर्तन	100 प्रतिशत
सड़क पुल में परिवर्तन	50 प्रतिशत
प्लेटफार्म शेड में परिवर्तन	75 प्रतिशत
(ग) कर्मचारी क्वार्टर	80 प्रतिशत
(घ) ऊपरी उपकरणों की देखभाल के डिपो	100 प्रतिशत
(ङ) लोको शेड	50 प्रतिशत
(च) माल भरने के गेज और बचाव की स्करीनें	100 प्रतिशत

ऊपर के उपकरण :

(क) तार लगाने की योजनाएं	100 प्रतिशत
(ख) अधिकीलन योजनाएं	94 प्रतिशत
(ग) नींवों का ढालना	55 प्रतिशत
(घ) स्विचिंग एंड बूस्टर ट्रांसफार्मर स्टेशन्स	15 प्रतिशत

सिग्नेलिंग और तार संचार :

(क) सिग्नेलिंग अधिष्ठानों में परिवर्तन	38 प्रतिशत
(ख) रंगदार रोशनी का सिग्नेलिंग कार्य	28 प्रतिशत

बिजली की सप्लाई :

सभी ट्रांसफर्मर भारत में प्राप्त हो गये हैं। 132 किलोवाट पारेषण लाइनों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

डाक और तार विभाग कार्य :

(क) केबल लगाने के लिये खुदाई करना	100 प्रतिशत
(ख) केबल बिछाना	10 प्रतिशत

दौराला–मवाना–हस्तिनापुर के बीच रेलवे लाइन

48. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दौराला–मवाना–हस्तिनापुर के बीच रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के काम में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इंजीनियरिंग सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकार को दे दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कब तक दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण पूरे होगये हैं और सर्वेक्षण प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं और रेलवे बोर्ड उन पर विचार कर रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सर्वेक्षणों पर अब तक लगभग कुल 90 हजार रु० व्यय किये गये हैं ।

माल डिब्बे

49. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों ने अपनी कर्मशालाओं में विभिन्न प्रकार के माल डिब्बों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) अब तक कितने माल डिब्बे पूर्ण रूप से बनाये जा चुके हैं; और

(घ) उन पर कुल कितना खर्चा आया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे वर्कशाप में अब 4 पहियों वाले 7000 माल डिब्बे प्रति वर्ष बनाने की क्षमता हो गई है ।

(ग) जनवरी, 1960 से दिसम्बर, 1964 के बीच की अवधि में रेलवे वर्कशाप में चार पहियों वाले 15,150 माल डिब्बे बनाये गये ।

(घ) अनुमान है कि इन 15,150 के बनाने पर लगभग 24 करोड़ रु० खर्च हुए ।

राजस्थान विमान, रेल, परिवहन यात्री संस्था

50. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान विमान, रेल, परिवहन यात्री संस्था की वे सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं जो उसने अक्टूबर, 1964 में अपने जोधपुर में हुए सम्मेलन में की थीं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) अक्तूबर, 1964 में जोधपुर में उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन पत्र दिया गया था जिसमें अनेक सुझाव थे ।

(ख) ये सुझाव उत्तर रेलवे प्रशासन के विचाराधीन हैं ।

भावनाथपुर तक बड़ी रेल लाइन

51. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भावनाथपुर तक बड़ी लाइन चालू करने का निर्णय किया है ताकि बोकारो इस्पात कारखाने को चूने का पत्थर आसानी से ढोया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी हां । बोकारो इस्पात संयंत्र को चूने का पत्थर भेजने के लिये उत्तर रेलवे मेराल ग्राम से भावनाथपुर तक बड़ी लाइन का एक पार्श्व बनवा रही है जिसका खर्चा मैसर्स बोकारो इस्पात संयंत्र लिमिटेड वहन करेगा ।

(ख) कार्य अभी आरम्भ किया गया है ।

(ग) अनुमानित लागत लगभग 4 करोड़ रु० है ।

रुई के मूल्य

†52. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में रुई की बहुत अच्छी फसल हुई है ;

(ख) यदि हां, तो रुई के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मूल्यों में हुई इस प्रत्याशित वृद्धि का सूती कपड़े के उत्पादन तथा उसकी निर्धारित दरों पर बिक्री पर प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

लौह-अयस्क का निर्यात

57. श्री राम हरख यादव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64 में कितनी मात्रा में लोह-अयस्क का निर्यात किया गया ;

(ख) प्रत्येक देश द्वारा कितनी मात्रा में लोह-अयस्क खरीदा गया ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). 1963-64 के दौरान जितनी मात्रा में तथा जितनी मूल्य की (याने विदेशी मुद्रा जितनी कमायी गई) लोह-अयस्क के देश-वार निर्यात के बारे में एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) चालू मौसम (1964-65) के फसल के सरकारी अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । व्यापारी अनुमानों के आधार पर यह फसल 58 से 59 लाख गांठों तक होने की आशा है ।

(ख) कपास के मूल्यों में वृद्धि सट्टेबाजी तथा कुछ कपड़ा मिलों द्वारा खरीदारी करने के लिये उतावला होना और कुछ उत्पादकों तथा सहकारी समितियों द्वारा भण्डार रोके रखने की प्रवृत्ति कहे जा सकते हैं । विदर्भ तथा खानदेश जैसे क्षेत्रों में फसल के आने जाने में भी कुछ देर हुई है ।

(ग) जी नहीं । मूल्यों को संतोषजनक स्तरों तक रखने, उत्पादकों को अच्छे दाम मिलने तथा मिलों को पर्याप्त भण्डार बनाये रखने के बारे में निगरानी रखी जा रही है ।

भोजन कार

53. **श्री चुनी लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद-दिल्ली 203 अप तथा 204 डाउन डाक गाड़ियों के साथ जो भोजन कार की व्यवस्था थी वह अब बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसे फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा॰ राम सुभग सिंह): (क) और (ख). अहमदाबाद-दिल्ली 203 अप/204 डाउन एक्सप्रेस (डाक नहीं) में पहले से चल रही भोजन कार सेवा 1 अक्टूबर, 1957 से बन्द कर दी गई थी क्योंकि इन गाड़ियों में भीड़भाड़ को कम करने

के लिए भोजन कार के बदले एक यात्री डिब्बा लगाया गया था। रास्ते की खान-पान की सुविधायें उचित रूप से सुदृढ़ कर दी गईं।

(ग) जी नहीं ।

रेलवे भोजन व्यवस्था देखभाल समितियां

54. श्री चुनी लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोजन व्यवस्था संस्थानों की देखभाल के लिये प्रत्येक रेलवे के लिए रेलवे भोजन व्यवस्था देखभाल समितियों की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो उनके कृत्य क्या हैं और उनको क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ; और

(ग) ऐसी समितियों के गठन का क्या तरीका है और उन के सदस्यों को नियुक्त करने के लिये कौन प्राधिकारी सक्षम है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०--3799/65 ।]**

उत्तर रेलवे पर सामान बेचने सम्बन्धी ठेकेदार

55. श्री चुनी लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर सामान बेचने सम्बन्धी ठेकेदारों से लाइसेंस फीस और किराये के रूप में काफी बड़ी धन राशि वसूल की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो गत् तीन वर्षों की बकाया धनराशि कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ठेके प्राप्त करने के पश्चात् ये ठेकेदार ठेकों को प्रायः दूसरों को शिकमी दे देते हैं और उनको अपने कर्मचारियों के रूप में दिखाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ङ) उत्तरी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर उपरोक्त कालावधि में कितने ठेकेदारों को दो से अधिक ठेके दिये गये ; और

(च) क्या इन ठेकों को देते समय सहकारी समितियों, राजनीतिक पीड़ितों, बेरोजगार व्यक्तियों तथा अन्नपूर्णा जैसी संस्थाओं को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 31-12-1964 को 32,124.07 रुपये बकाया थे।

(ग) और (घ). यह ठीक नहीं है कि आम तौर से ये ठेकेदार अपने ठेके अपने कर्मचारियों को दे देते हैं। परन्तु जब भी इस बारे में विशेष शिकायतें मिलती हैं पूरी जांच की जाती है और उन मामलों में जहां यह बात सिद्ध हो जाती है ठेके एकदम समाप्त कर दिये जाते हैं।

(ङ) उत्तर रेलवे के 18 ठेकेदारों के पास सामान बेचने/खानपान के कुल २ एककों से अधिक ठेके हैं ।

(च) राजनीतिक पीड़ितों, बेरोजगार व्यक्तियों, अन्नपूर्णा तथा सहकारी समितियों जैसी संस्थाओं को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती ।

अम्बाला सुधार न्यास

56. **श्री चुनी लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला सुधार न्यास ने पारस्परिक करार के अन्तर्गत विनिमय के आधार पर, सुधार करने के लिये रेलवे भूमि को न्यास के नाम हस्तान्तरित करने की मांग की है । जिस से रेलवे और सुधार न्यास दोनों को लाभ हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे भूमि रेलवे के अपने विकास कार्यों के लिये दरकार है और इसलिये इसे नहीं छोड़ा जा सकता । इसकी सूचना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सभापति को दे दी गई है ।

विवरण

1963–64 के दौरान हुआ देशवार लोहे का निर्यात इस प्रकार है ।

देश	मैट्रिक टनों में मात्रा (लाखों में)	रुपयों में मूल्य (लाखों में)
जापान	23.81	1154
चेकोस्लोवेकिया . . .	7.07	317
रुमानिया . . .	4.89	234
युगोस्लेविया .	2.82	123
पोलेण्ड .	1.60	79
हंगरी . . .	1.03	53
जर्मनी (पूर्व) . . .	0.55	26
	41.77	1986

तिरुचि में बायलर संयंत्र

58. **श्री हिम्मतसिंहका** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 21 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या **232**

के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुचि (मद्रास) में चैकोस्लावाकिया के सहयोग से हाई प्रेसर बॉयलर संयन्त्र स्थापित करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : कारखाने के तीन मुख्य खण्डों की नींव, फर्श, नालियों तथा जल निस्सारण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । कलपुर्जों तथा रख-रखाव विभाग इस मास के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है । दूसरे कारखाना खण्डों का निर्माण कार्य चल रहा है । उपकरणों का 66 प्रतिशत भाग जो चेकोस्लोवेकिया से मंगाया जाना था तथा देश में उपलब्ध करना था, मिल चुका है । 'जिग्ज़', टूल्स और कुछ और साज सामान लगाने का काम आरम्भ हो चुका है ।

चेकोस्लोवेकिया में 121 तकनीशियन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; 19 तकनीशियन प्रशिक्षण के पश्चात् वापिस आ गये हैं ।

जिन 1310 मकानों के निर्माण की मंजूरी पहले दी गई थी उनमें से 1100 पूरे हो चुके हैं ।

छपरा जंक्शन के निकट रेलगाड़ी और बस की टक्कर

59. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट एक बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक पर 9 दिसम्बर, 1964 को रेलगाड़ी और बस में हुई टक्कर के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दुर्घटना मोटर बस चालक की बेपरवाही तथा बस तेज़ चलाने के कारण हुई । रेलवे के किसी कर्मचारी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया ।

Diesel Engines

60. Shri Hem Raj : Will the **Minister of Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 606 on the 27th November, 1964 and state :

(a) whether any decision has been taken regarding the allotment of narrow gauge diesel engines imported from abroad ;

(b) if so, the number of engines to be allotted to the Kangra Valley railway line of the Northern Railway ;

(c) whether it has been decided to run an additional train on this section during this year ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Of the total of 25 Narrow Gauge diesel locomotives ordered, 15 have been allotted to the South Eastern and 10 to the Northern Railway. The question of allotting any of the engines specifically to Kangra Valley is under technical examination.

(c) and (d). The question of introduction of an additional train on Kangra Valley section will be duly considered after the diesel engines now being positioned on the South Eastern Railway are commissioned and thereby some of the existing steam locomotives on that railway released for use elsewhere.

यमुना पर रेलवे पुल

61. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराना किला, दिल्ली के निकट यमुना नदी पर रेलवे पुल का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). यद्यपि यमुना पुल का निर्माण लगभग अनुमानानुसार है और उत्तर प्रदेश राज्य प्राधिकार तथा दिल्ली प्रशासन से मिल कर कई महत्वपूर्ण सड़कें जो पुलों के नीचे तथा ऊपर बनायी जानी हैं, में देर होने के कारण इस पुल को चालू करने में अभी कुछ समय और लग सकता है क्योंकि यह तुगलकाबाद और गाज़ियाबाद के बीच मुख्य लाइन का इस्तेमाल कम करने की परियोजना का एक अंग है ।

यमुना पुल, दिल्ली

62. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेडा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने नव वर्ष दिवस को चार घंटे के लिये यमुना पुल का नियंत्रण किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रथा समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). जी हां । हर वर्ष यमुना पुल पर सड़क यातायात कुछ घंटों के लिए इसलिये रोका जाता है जिससे रेलवे का स्वामित्व अधिकार मालूम होता रहे। इस अवधि में जनता को जाने दिया जाता है परन्तु वहीं पर स्थित रेलवे अधिकारी खुलेआम परमिट देते हैं । आम सूचनायें छपे विज्ञापनों के रूप में पुल को जाने वाले मार्गों पर चिपका दी जाती हैं और साथ के डिप्टी कमिश्नरों को भी बता दिया जाता है ।

समाचार-पत्रों में भी इसकी सूचना जनता की सुविधा के लिए दी जाती है। कानूनी दावपेचों के कारण यह प्रक्रिया चलती रहेगी।

Dead body in Howrah-Bombay Express

63. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Bahgwat Jha Azad :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dead body of a woman was found in an unclaimed trunk in a third class compartment of the Howrah-Bombay Express at Victoria Terminus Station on the 5th January, 1965 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether such incidents are repeatedly taking place on Railways ; and

(d) if so, what steps Government propose to take in the matter ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) On arrival of the Howrah-Bombay Express train at Bombay V.T. at 07.30 hours on 15-1-1965, one steel trunk was found unclaimed in the III class compartment. The Government Railway Police was immediately informed about it, who noticed some foul smell emanating from the trunk. The trunk was therefore, removed from the compartment and when opened in the presence of Panchas, a dead body of an unknown female was found inside it. No visible marks of injury were found on her body. The case has been registered by the police U/s 302 IPC and is under investigation. So far, the dead body has not been identified nor any arrests made.

(c) No.

(d) Does not arise.

ऊनी कपड़े के खुदरा विक्रेता

64. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जनवरी, 1965 के 'पैट्रियट' में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि ऊनी कपड़े के खुदरा विक्रेता उपभोक्ताओं से 41 प्रतिशत तक लाभ कमाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सचाई का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). ऊनी कपड़ों के मिल मूल्यों तथा खुदरा मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । ऊनी कपड़े विशषकर, वर्सटेड कपड़े के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है जिसके मुख्य कारण यह हैं :

(1) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी कच्चे माल का अभाव; तथा

(2) कपड़े तथा बुने माल के उत्पादन में परिणामस्वरूप कमी जो विदेशी ऊन से बनता है ।

कच्चे माल की उपलब्धि में कमी को देशीय ऊन के बड़ी मात्रा में उपयोग करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन दे कर दूर करने की चेष्टा की गई है ।

राजनयिक कारों की बिक्री

65. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न राजनयिक मिशनों से कितनी कारें खरीदी तथा बेची गईं ;

(ख) उन में से कितनी कारें सरकारी अधिकारियों तथा विभागों को स्टाफ कारों के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए दी गई ; और

(ग) इन कारों को खरीदने पर विभिन्न सरकारी विभागों ने कुल कितना व्यय किया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नवम्बर, 1962 में लागू की गई राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की क्रय योजना से ले कर 31 जनवरी, 1965 तक कुल 911 कारें खरीदी गई हैं ।

(ख) इन 911 कारों में से 192 केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभागों तथा कार्यालयों के लिए, 102 सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के लिए तथा 374 कारें आम नीलामी द्वारा बेची गई । 129 कारें अभी हमारे पास हैं ।

(ग) केन्द्र/राज्य सरकारों के लिए रखी गई 192 कारों के लिए 48,31,394.11 रुपया मिला ।

गोआ में औद्योगिक विकास निगम

†66. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ में 1965-66 में एक औद्योगिक विकास

निगम स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). गोआ में औद्योगिक विकास निगम स्थापित करने का प्रश्न गोआ सरकार के विचाराधीन है ।

Posting of Railway Workers

67. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board have issued instructions that the gangmen, trollymen, Khalasis and other such staff employed on running duties should be posted at places nearabout their homes ; and

(b) if so, how far these instructions are being followed by the various Railway Administrations ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

Derailment near Gaya

68. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwar Tantia :
Shri P.R. Chakravarty :
Shri P.C. Borooah :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P.H. Bheel :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two goods trains were involved in an accident on account of the sudden collapse of a culvert between Anugrah Narayan Road and Sone Nagar Road Stations on the Grand Chord Section of the Eastern Railway on the 31st December, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that the drivers of both the trains received serious injuries ; and

(c) if so, the causes of the sudden collapse of the culvert ?

Deputy Minister for Railways (Shri Sham Nath): (a) The accident was not caused by sudden collapse of a culvert.

(b) only the driver and the Assistant driver of the Down train sustained serious injuries.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

69. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा की जाने वाली परामर्श सम्बन्धी सेवाओं

का विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या प्रत्येक नये उत्पादन संयंत्र में, जहां विदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, डिजायन तथा विकास ग्रुप सम्मिलित करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रौद्योगिकीय परामर्श विभाग 1960 के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था। तब से इंजीनियरी परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है । उसके पास पहले ही मांग सम्बन्धी सर्वेक्षण, प्रौद्योगिक आर्थिक अन्वेषण, स्थान सम्बन्धी अन्वेषण आदि जैसे सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं के आयोजन आदि के बारे में कई काम हैं । इसने नये संयन्त्रों के डिज़ायन बनाने का काम भी आरम्भ कर दिया है और हाल ही में उसको दो बड़ी परियोजनाओं से सम्बन्धित यही काम सौंपा गया है ।

इस विभाग के क्षेत्र और क्षमता में और वृद्धि करने का विचार है ताकि आने वाले वर्षों में कुछ उद्योगों में इंजीनियरी परामर्श सेवाओं के बारे में परामर्श दे सके। बढ़ रहे काम को करने के लिए इस संगठन के लिए योग्य तथा अनुभवी तकनीकी व्यक्तियों की भर्ती की जा रही है ।

(ख) नये उत्पादन सयंत्रों में डिजायन तथा विकास वर्गों का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन संयंत्रों में भविष्य में काम का ध्यान रखे । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रौद्योगिकी परामर्श विभाग ऐसे मामलों में मंत्रणा देगा परन्तु इन वर्गों के काम की जिम्मेदारी सम्बद्ध उत्पादन एकक पर होगी ।

लाहौल स्पिती में तांबे के निक्षेप

70. **श्री हेडा :**
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौल-स्पिती जिले में तांबे के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) इन निक्षेपों से तांबा निकालने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) 1963 में भारतीय भौमिकी विभाग द्वारा भेजी गई सर्वेक्षण पार्टी ने लाहौल-स्पिती के कुछ स्थानों में तांबे की मौजूदगी के केवल कुछ संकेत पाये हैं । विस्तृत कार्य किये जाने के बाद ही इनके आर्थिक महत्व का पता लगेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार

71. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों को राष्ट्रपति का पुरस्कार देने के लिये

एक अच्छी तुलनात्मक आधार बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन का क्या ब्योरा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

Accident near Etawah

72. **Shri Bade :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three gangmen of Etawah (Northern Railway) were run over by 7-UP Express train while they were working on the 13th December, 1964.

(b) if so, whether an enquiry has been held ; and

(c) if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Three gangmen working on the track on Etawah-Ekdil section were run over and killed by train No. 7 UP Toofan Express on 11-12-1964 and not on 13-12-1964.

(b) and (c). The accident was enquired into by a Committee of Railway Officers. According to the Committee, the gangmen did not hear the whistle of the approaching Express train nor even the warnings by their fellow workers due to the noise of a goods train passing on the adjacent track. The smoke emitted by the goods train also obstructed the visibility.

कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग

73. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 564 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के स्थान पर तेल का प्रयोग करने के बारे में विश्व बैंक के अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सरकार अभी तक इन सिफारिशों के सभी पहलुओं पर विचार कर रही है ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

74. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बड़ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल ने जब से इस की स्थापना हुई है तब से

अब तक गैर सरकारी क्षेत्र के लिये क्रयादेश स्वीकार किये हैं तथा उनका निष्पादन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये क्रयादेश कुल कितने मूल्य के हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) अब तक स्वीकार किये गये क्रयादेश लगभग 9.6 करोड़ रुपये के हैं और अब तक पूरे किये गये क्रयादेश लगभग 2.4 करोड़ रुपये के हैं।

Derailment of Engine at Delhi Station

75. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of trains were delayed as a result of the derailment of the engine of the Amritsar-bound passenger train at Delhi Main Station on the 22nd December, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that the fish-plates of some lines were missing ;

(c) if so, whether any enquiry was made into the matter ; and

(d) if so, the findings thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) No.

(c) & (d). Do not arise.

लघु उद्योग

76. श्री सं० ब० पाटिल : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को चलाने के लिये जो वस्तुएं दी जाती हैं उस में से अधिकतर वस्तुयें उचित रूप से प्रयोग नहीं की जा रही हैं ;

(ख) क्या कोई ऐसी भी संस्था है जो यह देखती है कि क्या राज्यों को किसी प्रयोजन के लिये दी जाने वाली सामग्री जैसे स्टेनलैस स्टील, ताम्बे और काफूर उसी प्रयोजन के लिये इस्तेमाल की जाती हैं अथवा नहीं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि छोटे पैमाने के उद्योगों को चलाने के लिये जो वस्तुयें दी जा रही हैं उनमें से अधिकतर ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं हो रही हैं।

(ख) और (ग). विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले कच्चे माल का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिनके पास एककों का निरीक्षण करने और कच्चे माल के ठीक इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था है।

Survey of Mineral Wealth

77. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have asked for experts from U. S. A. to undertake a survey of mineral wealth in India;

(b) if so, when are they likely to arrive in India; and

(c) the projects proposed to be assigned to them for survey.

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy): (a) to (c). Government has not approached the U. S. A. for the services of experts to undertake a survey of mineral wealth of India. However, a scheme for air-borne survey of certain selected areas has been drawn up in consultation with the United States Agency for International Development which envisages the engagement on contract of a foreign firm with the necessary equipment and experts in geophysical and geological investigations. The scheme has been referred to the United States Agency for International Development authorities for the provision of necessary financial assistance. A firm decision regarding the areas to be surveyed has not yet been taken.

Jute Mills in Tripura and Bihar

78. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the people of Tripura and Bihar have urged Government to set up jute mills there;

(b) if so, the number of jute mills to be set up and their location; and

(c) whether these mills will be set up in the public, private or cooperative sector?

The Deputy Minister of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a), Yes, Sir. Government have been receiving representations from the people of Bihar or Tripura for setting up of jute mills there.

(b) & (c). One application made by a private party for setting up a small jute mill unit in Tripura had been recommended by the Tripura Administration and a Letter of Intent is proposed to be issued to them for establishig the mill. However, no large scale expansion of jute industry is possible or necessary and as such, excepting for helping the industrial development of Tripura which is totally backward in industries and where because of this reason one small jute mill unit has been approved, no new jute units are being set up.

रूई का आयात

79. **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मि० सू० मूर्त्ति :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 में देश में रुई के आयात से भारतीय रुई मिल संघ, बम्बई ने प्रीमियम के रूप में कितनी धनराशि इकट्ठी की ;

(ख) इस प्रीमियम को किस प्रकार से उपयोग में लाया गया ; और

(ग) मिलों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थापित की गई हैं और प्रत्यक मिल को निर्यात प्रोत्साहन अथवा किसी अन्य रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). भारतीय रुई मिल संघ सूती वस्त्र उद्योग का एक संगठन है, न कि सरकार का । अतः सरकार उस संघ द्वारा इकट्ठी की गई धनराशि अथवा उसके उपयोग के संबंध में कोई प्राधिकृत सूचना देने की स्थिति में नहीं है ।

कपास का आयात

80. **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री मि० सू० मूर्त्ति :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 में विश्व के देशों से टेंडर द्वारा तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत देश में कुल कितनी कपास का आयात किया गया ;

(ख) किन किन मिलों को कपास दी गई है और वे कहां कहाँ हैं ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक को कितनी कपास दी गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

	गांठें
विश्व के देशों से कपास (वस्तु विनिमय सहित) .	400,826
पी० एल० 480 के अन्तर्गत कपास	382,360
जोड़ . .	783,186

(ख) और (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इटावा-भिंड रेल सम्पर्क

81. श्री गो० ना० दीक्षित : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इटावा तथा भिंड के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये इटावा, भिंड तथा ग्वालियर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 1952 में की गई जांच से पता लगा है कि इस लाइन से काफी फायदा नहीं होगा। यमुना, चम्बल तथा कावेरी नदियों पर लम्बे पुलों की आवश्यकता के कारण उस समय इस लाइन (21 मील) पर लागत का अनुमान लगभग 433 लाख रुपये आंका गया था। इस समय लागत उससे दुगुने से भी अधिक होगी और इसीलिये इस परियोजना से अधिक लाभ नहीं होगा। नई लाइनों के निर्माण के लिये उपलब्ध साधन तथा सीमित धन होने के कारण निकट भविष्य में इस लाइन का निर्माण करने की सम्भावनायें बहुत कम दिखाई देती हैं।

पंजाब में कागज का कारखाना

82. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ फर्मों ने भाखड़ा के निकट तलवारा में कागज का एक कारखाना खोलने के लिये पंजाब सरकार के मार्फत लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). केवल एक फर्म ने उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजाब में भाखड़ा के निकट तलवाड़ा में अखबारी कागज का एक कारखाना खोलने के लिए आवेदन पत्र दिया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है।

मुकेरियां-तलवारा रेलवे लाइन

83. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री 1 सितम्बर, 1961 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3052 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर मुकेरियाँ-तलवारा रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): इस लाइन के लिये मिट्टी डालने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है और सभी पुल बना दिये गये हैं पटड़ी को बड़ी लाइन से मिलाने का काम चल रहा है। अब तक 85 प्रतिशत काम हो चुका है।

लुगदी निर्माण संयंत्र

84. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 229

के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में लुगदी निर्माण संयंत्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास और अरकोणम के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ी

85. **श्री श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और अरकोणम के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फैजाबाद–लखनऊ यात्री गाड़ी में खतरे की जंजीर

86. **श्री मुरली मनोहर :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1964 से फैजाबाद–लखनऊ यात्री गाड़ी में खतरे की जंजीरें हटा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन जंजीरों के फिर से कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) आई० एफ० बी० एल० फैजाबाद–लखनऊ गाड़ी पर अनधिकृत रूप से जंजीर खींचने की अधिक घटनायें होने के कारण 1 नवम्बर, 1964 से उस गाड़ी में खतरे की जंजीर हटा दी गई है ।

(ग) इस गाड़ी में खतरे की जंजीर को बहाल करने के प्रश्न पर मार्च, 1965 के मध्य में विचार किया जाएगा ।

राजेन्द्र पुल हाल्ट तथा हथीदा जंक्शन के बीच रेल किराया

87. **श्री दे० द० पुरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के मोकामा–बरौनी सैक्शन पर राजेन्द्र पुल हाल्ट तथा हथीदा जंक्शन के बीच वास्तविक दूरी तीन किलोमीटर है जब कि किराया 39 किलोमीटर की दूरी का लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). राजेन्द्र पुल हाल्ट और हथीदा जंक्शन के बीच वास्तविक फासला 3.34 किलोमीटर है और यात्रियों से 40 किलोमीटर का किराया लिया जाता है। चूंकि वित्तीय दृष्टि से पुल का निर्माण करना फासिले को अधिक दिखाये बिना उचित न था इसलिये ऐसा किया गया है। अधिक फासिला निर्धारित करने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि यात्रियों को इस महंगे पुल के निर्माण से पहले जो किराया देना पड़ता था उससे अधिक न देना पड़े।

क्योंकि फासिले को जानबूझ कर अधिक दिखाया गया है इसलिये इसको ठीक करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रम का निर्यात

88. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप में भारतीय रम बहुत लोकप्रिय है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्यात के लिये विदेशों में नये बाजार खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चोरी के मामले

89. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 में जनवरी 1965 के अन्त तक सभी भारतीय रेलों पर रेल के डिब्बों से रेलवे के सामान के खोने की और चोरी की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) उक्त अवधि में इसके कारण कुल कितने रुपये की हानि हुई ; और

(ग) वर्ष 1962 तथा 1963 में इसी कारण से कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क)

	रु०
1964 में	27,131
जनवरी, 1965 में .	1,910
(ख) 1964 में	16,74,613
जनवरी, 1965 में	1,09,433
(ग) 1962	10,24,448
1963	15,03,862

कर्जत-खोपोली लाइन

90. **श्री दिगे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई–पूना रेलवे लाइन का कर्जत–खोपोली रेल लाइन ही केवल ऐसी है जिसका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जनता ने इस लाइन के विद्युतीकरण की मांग की है ; और

(ग) सरकार का इस लाइन के विद्युतीकरण कार्य को कब आरम्भ करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) कर्जत-खोपोली भाग विद्युतीकरण करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यात्रियों को भाप से चलने वाले इंजनों द्वारा सरलता से ले जाया जा सकता है।

उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट का कार्यालय

91. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग ने दिसम्बर, 1964 तथा जनवरी, 1965 में उत्तर रेलवे के नई दिल्ली स्थित डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय पर छापे मारे थे और वाणिज्यिक शाखा के कुछ कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। विशेष पुलिस स्थापना ने 18-1-1965 को डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय पर छापा मारा और वाणिज्यिक शाखा के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। जबकि वह एक फर्म के एक व्यक्ति से रिश्वत के रूप में 300 रु० ले रहा था। उस फर्म ने साइकिल स्टैण्ड के ठेके के लिये टेंडर दिया हुआ था।

(ख) कर्मचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसे उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया गया था। विशेष पुलिस स्थापना अग्रेतर जांच कर रही है। कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है ।

इटारसी–जबलपुर लाइन को दोहरा करना

92. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे पर इटारसी तथा जबलपुर के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने संबंधी परियोजना को निर्धारित समय के अनुसार कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य को तेजी से करने तथा परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अरब साझा बाजार

93. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कई अरब देशों की सरकारों ने अरब साझा बाजार बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और किन परिस्थितियों के कारण उपरोक्त निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत के विदेशी व्यापार पर इसके प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). जी हां। सं० अ० गणराज्य, ईराक, सीरिया, जोर्डन और कुवैत इन पांच अरब देशों ने मिल कर साझा बाजार बनाने का निर्णय किया है। साझा बाजार उन प्रायोजनाओं में से है जो अरब संघ के सदस्यों के मध्य काहिरा में 1964 में हुए आर्थिक एकता करार के अधीन परिकल्पित की गई थी ।

(ग) तथा (घ). अरब साझा बाजार औपचारिक रूप से 1 जनवरी, 1965 से बना है और इस बात का अनुमान लगाना अभी असामयिक होगा कि इसका भारत के विदेश व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

Terminal Tax on Railway Passengers

94. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have demanded that terminal tax should be imposed on the passengers going to Patna, Gaya and Deoghar by railway trains; and

(b) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) & (b). No request has been received from the Bihar Government for levy of Terminal Tax on railway passengers going to Gaya, Patna and Deoghar in the recent past. A request was received in 1958 for the levy of tax on railway passengers from or to Patna, Deoghar, Sonepur, Hajipur, Gaya and Rajgir, and the State Government was informed that the question of levy of the tax could be considered only after the State Government had levied a parallel tax on road passengers.

आयरलैंड को वस्त्रों का निर्यात

95. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयरलैंड की सरकार भारत से वस्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे हमारे निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). यह पता लगा है कि आयरलैंड गणराज्य ने भारत सहित कुछ देशों से सूती वस्त्रों के आयात पर कुछ प्रतिबन्धों की घोषणा की है । ब्योरे का पता लगाया जा रहा है ।

Special Train Between Bhatinda and Nokha

97. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Surya Prasad:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether there is any proposal under consideration for making arrangements for running special trains between Bhatinda and Nokha for the facility of passengers going to visit the famous fair of Jambaji in district Bikaner of Rajasthan?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): Jambaji Fair which will be held at Nokha from 25th February to 2nd March, 1965 is of a local nature and the inward and outward rush on the occasion is not expected to exceed 300 to 400 passengers per day from different directions. This volume of traffic does not justify the running of special trains. However, a close watch is being kept on the traffic likely to materialise and suitable arrangements will be made to augment the loads of trains on the section to the extent feasible and justified.

आंध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

99. **श्री दाजी :**
श्री नारियर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 1962 से 31 दिसम्बर, 1964 की अवधि में आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि भोंगीर, बोनाकालू तथा येर्रा गुन्टला की परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ख). आन्ध्र प्रदेश में 1 अप्रैल, 1962 से 31 दिसम्बर, 1964 की अवधि में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया । इस अवधि में येरागुन्तला में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए दो योजनायें और बोनाकालू, तंदूर, आलमपुर तथा आसिफाबाद में कारखाने स्थापित करने के लिए चार योजनायें स्वीकार की गई हैं । येरागुन्तला के लिए दो योजनाओं में से एक रद्द कर दी गई है । शेष सभी योजनाओं तथा भोंगीर सीमेंट कारखाने की योजना, जिसे 1961 में लाइसेंस दिया गया था, की प्रगति पर पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

येल्लान्दु में कच्चे लोहे का संयंत्र

100. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने येल्लान्दु, जिला खम्मम, आंध्र प्रदेश में कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित करने में कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या कोई लाइसेंस दे दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थानीय उपलब्ध साधनों के उपयोग से कच्चा लोहा तैयार करने के विभिन्न प्रक्रमों के गुण दोषों का परीक्षण कर रहा है । उन्हें पश्चिमी जर्मनी, नार्वे और यू० के० की कुछ फर्मों से संयत्र और उपकरणों के संभरण के बारे में प्राथमिक प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है । इन फर्मों को कच्चे माल के नमूने प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे गए हैं । अब निगम अन्तिम प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहा है जिनके परीक्षण समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है ।

(ख) अभी तक नहीं । लाइसेंस देने का प्रश्न तब उठेगा जब निगम सरकार को ठोस प्रस्ताव दे देगा और वे मितव्ययी होंगे ।

कोठागुडियम में लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट

101. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी द्वारा कोठागुडियम (आंध्र प्रदेश) में लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट स्थापित किये जाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन की जांच अब पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लो टेम्परेचर कारबोनाइजेशन प्लांट स्थापित किये जाने की सम्भावनाओं के सम्बंध में प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार किया है। उस अध्ययन के निष्कर्ष ठीक होने के कारण कम्पनी को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिए कहा गया है ताकि इस योजना को चालू करने के बारे में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ।

कटिहार की जूट मिल

102. **श्री दाजी :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन कटिहार जूट मिल, कटिहार (बिहार) द्वारा निर्माण किए जाने वाले जूट टैक्सटाइल के उत्पादन में कमी के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) कटिहार जूट मिल्स (पी) लिमिटेड, कटिहार, के मामले में जांच करने के लिए नियुक्त की गई जांच समिति की मुख्य उपपत्तियां यह हैं :—

1-1-1965 से मिल को बन्द करने से बिहार राज्य में जूट टैक्सटाइल के कुल उत्पादन में, उक्त मिल में बनने वाली जूट टैक्सटाइल कम बनने के कारण काफी कमी हो जायेगी ।

मिल की मशीनरी खराब हालत में है और मालिकों ने मिल के आधुनिकीकरण की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किये हैं । मिल की वित्तीय स्थिति बहुत बुरी है ।

सरकार के एक अधिकृत नियंत्रक द्वारा मिल का प्रबन्ध सम्भाल लेने से मिल को पुनः चालू किया जा सकता है । यह सिफारिश की गई है कि मिल को इस प्रकार के प्रबन्ध करने पर खोला जा सकता है :—

कम से कम 330 करघों को चालू करने के लिए बिजली की पर्याप्त व्यवस्था ;

मिल का अंशतः आधुनिकीकरण;

पूर्णतः आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी निर्माताओं को आर्डर देना ;

राज्य सरकार तथा औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

मैसूर को अलौह धातुओं का आवंटन

103. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 के दौरान मैसूर राज्य को तथा सीधे मैसूर राज्य में स्थित बड़े पैमाने के उद्योगों को तांबे, जस्ती टीन के पिंड, जस्तीकृत टीन की चादरों, टीन की प्लेटों, स्टेनलैस इस्पात तथा दूसरी अलौह धातुओं की कितनी मात्रा दी गई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में मैसूर राज्य को किये गये आवंटन की तुलना में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा मद्रास राज्यों को कितना आवंटन किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्र से मांग की है कि उसको ये धातुएं अधिक मात्रा में दी जाएं जिससे वह पीतल तथा तांबे के बर्तन बनाने वाले हुबली के कारीगरों की सहायता कर सकें ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ). उपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जूट की कमी

104. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जूट मिलों को कच्चे जूट की अधिक कमी के कारण हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की कच्चे जूट की मांग क्या है और 1965 की प्रथम छमाही में उन्हें कितनी मात्रा में कच्चा जूट दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

रावी नदी पर रेलवे पुल

105. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावी नदी के ऊपर पठानकोट (पंजाब) को कठुआ (जम्मू और काश्मीर) से मिलाने वाले रेलवे पुल के पूरा होने की प्रस्तावित तिथि क्या है ; और

(ख) क्या पुल के निर्माण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). गरडरों (17–150′ स्पान और 2–60′ स्पान) के निर्माण और उनको लगाने की वर्तमान प्रगति के आधार पर यह अनुमान है कि पुल 30 सितम्बर, 1965 तक पूरा हो जायेगा । पहले पुल को 31-3-65 तक पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे थे । परन्तु निर्माण करने वाली फर्म के कारखाने में मजदूरों के झगड़े के कारण गरडरों की सप्लाई आशा के अनुसार नहीं हो सकी और 31-3-65 से पहले काम पूरा नहीं हो सका।

कठुवा रेलवे स्टेशन

106. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य में प्रस्तावित कठुवा रेलवे स्टेशन की श्रेणी के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) कठुवा रेलवे स्टेशन 'ख' वर्ग रेलवे स्टेशन होगा जिसमें पानी की सुविधा तथा माल के लिए शैड की सुविधायें होंगी । बुकिंग आफिस, तार घर तथा पारसल आफिस के अतिरिक्त स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था होगी ।

पथखेड़ा कोयला क्षेत्र

107. श्रीमती मैमुना सुल्तान : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पथखेड़ा कोयला क्षेत्र में अच्छी किस्म के कोयले की दो परतों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो निक्षेपों का स्वरूप क्या है तथा उनके कितनी मात्रा में पाए जाने का अनुमान है ; और

(ग) इन निक्षेपों के विदोहन की योजनाएं क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तथा (ख). पथखेड़ा कोयला क्षेत्र में लगभग छः करोड़ टन कोयले होने का पता लगा है । इसका कुछ प्रतिशत प्रथम श्रेणी का है, परन्तु अधिक कोयले के घटिया होने की आशा है ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने एक भूमिगत खान चालू की है जिसका उत्पादन लक्ष्य ४५०,००० टन होगा । इस कोयले की और मांग होने पर एक और खान में खुदाई करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

व्यापार संबंधी एकाफे समिति

108. श्रीमती मैमुना सुल्तान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1965 में व्यापार सम्बन्धी एकाफे समिति की एक बैठक बैंकाक में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर से बैठक में किसने भाग लिया था ;

(ग) उनके द्वारा क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां । यह बैठक २५ जनवरी से 2 फरवरी, 1965 को हुई थी ।

(ख) भारत का प्रतिनिधित्व सर्वश्री एच० डी० शोरी, महानिदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, एल० एन० रे० एकाफे में भारत के काउन्सलर तथा स्थायी प्रतिनिधि, भारतीय दूतावास, बैंकांक, हरबेल सिंह, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय तथा बी० एम० मनचंदा, द्वितीय सचिव, भारतीय दूतावास, बैंकाक ने किया था ।

(ग) और (घ). समिति ने एकाफे क्षेत्र के देशों के व्यापार पर विचार किया था और 1964 में हुये व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने जो काम किया उस पर चर्चा की गई । समिति ने एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग को एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें एकाफे देशों में व्यापार बढ़ाने के संबंध में उपायों की सिफारिशें की गई हैं । मार्च, 1965 में जब आयोग अपने अधिवेशन में विचार कर लेगा तभी कोई कार्यवाही करना संभव हो सकेगा ।

उड़ीसा को इस्पात का आवंटन

109. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में उड़ीसा को कुल कितने लोहे तथा इस्पात का आवंटन किया गया ; और

(ख) 1965-66 के लिए लोहे तथा इस्पात की कुल कितनी मात्रा आवंटित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रड्डी) : (क) 1964-65 में उड़ीसा को लोहे तथा इस्पात के आवंटन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

†इस्पात	.	1100 मीटरी टन
कच्चा लोहा	.	23388 मीटरी टन

†यह मात्रा नियंत्रित वर्गों के अधिकतम आवंटित कोटे को ही जाहिर करती है । इस्पात की अन्य किस्मों पर नियंत्रण नहीं है और इन्डैंट-कर्ता बिना किसी रोक के इन वस्तुओं के लिए आर्डर भेज सकते हैं ।

(ख) 1965-66 के वर्षों के लिए लोहे और इस्पात के आवंटन अभी तक निश्चित नहीं किये गये हैं ।

तलचर कोयला खानें

110. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में तलचर कोयला खानों (उड़ीसा) में कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ तथा उसका कुल मूल्य क्या है ; और

(ख) 1965-66 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सम्पूर्ण 1964 पत्री-वर्ष के आंकड़े प्राप्त हैं । इस अवधि में कुल उत्पादन लगभग 0.65 मिलियन मीटरी टन था । इस कोयले का मूल्य लगभग 170 लाख रु० था ।

(ख) 1965-66 में तलचर कोयला खानों में राष्ट्रीय कोयला निगम ने अपनी खानों की कोयला उत्पादन की क्षमता बढ़ा कर 0.80 मिलियन मीटरी टन कर ली है बशर्ते कि कोयले की मांग इस हद तक पहुंचे ।

उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योग

111. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 में उड़ीसा में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कोई योजनायें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ; और

(ग) योजना का स्वरूप क्या है ?

उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां । यह योजनायें राज्य की 1965-66 की वार्षिक योजना में हैं ।

(ख) 48.03 लाख रुपये ।

(ग)

	योजना का विवरण	1965-66 के लिए दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1	राज्य उद्योग सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण .	7.00
2	औद्योगिक सहकारी समितियों की अंश पूंजी और कार्यवहन पूंजी के लिए ऋण	0.51
3	पंचायत समिति उद्योगों की इक्विटी पूंजी में भाग लेने की योजना	1.00
4	औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रबंधक कर्मचारियों का प्रशिक्षण	0.05
5	औद्योगिक सहकारी समितियों के सुपरवाइजरी और प्रबंधक कर्मचारी .	9.06
6	सम्भरण और विक्रय के वैज्ञानिकरण सम्बन्धी संगठन	3.96
7	प्रदर्शनी और भाड़े . . .	0.40
8	विद्युत् शुल्क के समीकरण के लिए सहायता .	0.50
9	प्रचार साहित्य तथा तक्नीकी बुलेटिन तैयार करना . .	0.75
10	पंचायत उद्योगों को स्थापित करने के लिए चुने हुये ग्राम पंचायतों को अनुदान	13.60

योजना का विवरण	1965–66 के लिए दी गई राशि (लाख रुपयों में)
11. औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा देय ब्याज सम्बन्धी वित्तीय एजेंसियों को सहायता	2.00
12. औद्योगिक सहकारी समितियों के लेखा तथा लेखा परीक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण	1.20
13. पंचायत उद्योग अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को अनुदान	8.00
योग . .	48.03

लघु उद्योग निगम, उड़ीसा

113. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में लघु उद्योग निगम, उड़ीसा को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ख) 1965–66 में कुल कितनी धनराशि दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए (जिनमें छोटे पैमाने के उद्योग, हाथ करघा, दस्तकारी, रेशम और नारियल जटा उद्योग शामिल हैं) केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति योजना-वार नहीं की जाती। इस विकास शीर्ष के अधीन 1964–65 के लिए राज्य सरकार को उपलब्ध कुल केन्द्रीय सहायता 85 लाख रुपये थी।

(ख) ग्राम तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार 'ग्राम तथा लघु उद्योग' शीर्षक के अधीन 1965–66 के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि (जिसका अन्तिम निर्णय अभी करना है) 101.20 लाख रुपये है ।

कालीकट रेलवे स्टेशन

115. **श्री कोया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) नये स्टेशन के जनता के लिये कब तक खुलने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कालीकट का नया रेलवे स्टेशन पूरा किया जा चुका है और यातायात के लिए खुल गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में उद्योग

116. **श्री रामपुरे** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने-अपने उद्योग आरम्भ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तकनीशियनों को सहायता देने की एक नई योजना चलाई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए कितनी सहायता देगी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभूधेन्द्र मिश्र) : (क) अपने-अपने उद्योग आरम्भ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने तकनीशियनों को सहायता देने की एक योजना चलाई है। इस योजना का ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) राज्य सरकार को विशेष रूप से इस योजना के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

निर्यात संवर्धन संबंधी राज्य बोर्ड

117. **श्री कोया** :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से नीचे लिये कार्य करने के लिए निर्यात संवर्द्धन सलाहकार बोर्ड/समितियां स्थापित करने का अनुरोध किया गया था :

(1) निर्यात व्यापार की समस्याओं, विशेषत: उनके राज्यों में पैदा होने वाले उत्पादों, वस्तुओं के विषय में सलाह देना ।

(2) राज्य सरकारों के ध्यान में वे असुविधाएं लाना जो हमारे निर्यात का तेजी से विस्तार करने में बाधक हैं और उन्हें दूर करने के उपायों की सिफारिशें करना ।

(3) केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले निर्यात संवर्द्धन उपायों की विविध जानकारी निर्माताओं, निर्यातकों और आम व्यापारी समाज के ध्यान में लाने के लिए एक माध्यम की व्यवस्था करना ।

इस समय बिहार, मैसूर और गुजरात राज्यों में निर्यात संवर्द्धन सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में भी इनके शीघ्र बन जाने की संभावना है। इसी प्रकार का काम करने के लिये निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति के नाम के संगठन इससमय मध्य प्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं ।

कोयले का सेम्पलिंग तथा ग्रेडिंग

118. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 251 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1962 में कोयले के सेम्पलिंग तथा ग्रेडिंग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ख) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) सेम्पलिंग सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के अभिस्ताव स्वीकार हो चुके हैं तथा कोयला बोर्ड को उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। कोयला बोर्ड ने इस विषय में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। ग्रेडिंग के बारे में दिए गये अभिस्तावों को कार्यान्वित करने में कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं और इन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जांय इसकी परीक्षा की जा रही है। इसमें सम्मिलित हैं :–

(1) कोयले की उपयोगी ऊष्म अर्हा निश्चित करने का मूल सिद्धांत तथा रसायन और अन्य विशेषताओं का विस्तृत विवरण जो उसकी ऊष्म अर्हा को प्रभावित करती है, निश्चित करना।

(2) ऊष्म अर्हा के आधार पर वर्तमान मूल्य के ढांचे में कीमत कायम करना ; और

(3) आवश्यक संस्था स्थापित करना तथा आवश्यक उपकरण अवास करना जिसका अधिकांश विदेश से मंगवाना पड़ेगा।

घटिया किस्म का कोयला

119. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंटें पकाने के लिये सोफ्ट कोक तथा कोयले की बिक्री की अनुमति देने सम्बन्धी केन्द्र के आदेशों की कार्यान्विति का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों से, जिन्होंने अभी तक आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया है, जल्दी से जल्दी ऐसा करने के लिये कहा है ; और

(ग) 1 जुलाई, 1964 से कोयले की खरीद में राज्य-वार कितनी वृद्धि हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जुलाई से दिसम्बर, 1964 की अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों को ईंट पकाने के लिए भेजे गए कोयले तथा सोफ्ट कोक के दो विवरण संलग्न हैं जिससे कोयला उठाने की उपनति का पता चलता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.—3800/65]**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
MOTION FOR ADJOURNMENT
भारत प्रतिरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

अध्यक्ष महोदय : भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत जो राजनीतिक नेता गिरफ्तार हुए हैं, उनके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मुझे प्राप्त हो गया है । गृह कार्य मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी सभा पटल पर रखा है । उस पर चर्चा का नोटिस भी मुझे मिला है । इस समय तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती इसके लिये मैं अलग से समय निर्धारित करूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वह स्थगन प्रस्ताव पुराना है, नया नहीं जो आपने स्वीकार किया है । अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाला नोटिस रद्द कर दिया गया था । वक्तव्य तो पटल पर रखा गया है परन्तु यदि सरकार के पास और भी तथ्य हो तो बताये जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हां, यदि सरकार के पास कुछ और तथ्य होंगे तो वे भी बता दिये जायें । क्या गृह कार्य मंत्री कोई अन्य श्वेत पत्र पटल पर रख रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर आपत्ति की जा रही है कि श्वेत पत्र के स्थान पर केवल वक्तव्य ही पटल पर रखा गया है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता केन्द्रीय) : दिल्ली के अखबारों में छपा है कि गृह-कार्य मंत्री क्यों श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं कर रहे ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय आप यह सब बातें कर सकते हैं । परन्तु इस समय मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । अविलम्बनीय लोक महत्व का नोटिस ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
वियतनाम में हुई हाल की घटनाएं और उन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और उन्हें निवेदन करता हूं कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें :—

"वियतनाम में हाल ही में हुई घटनाएं और उनके सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रया

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जैसा कि सदन को मालूम ही है, इस महीने के दूसरे सप्ताह में वियतनाम में कुछ गम्भीर घटनाएं हुईं जिनका पूरा विवरण समाचार-पत्र दे चुके हैं । इन घटनाओं से वियतनाम में पूरे जोरों की लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं ।

7 फरवरी, 1965 को साइगोन से जारी की गई एक सम्मिलित घोषणा में वियतनाम गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका दूतावास ने अपनी सरकार की ओर से यह घोषणा की कि उत्तर वियतनाम के सैनिक अड्डों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की गई है। वियतनाम लोक-गणराज्य के रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी, 1965 को जारी की गई एक विज्ञप्ति में अमरीकी सेनाओं द्वारा किये गये अनुचित हवाई हमलों पर विरोध प्रकट किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन इन पर तथा दोनों पक्षों की ओर से जारी किये गये अन्य प्रलेखों पर विचार कर रहा है।

8 फरवरी, 1965 को भारत सरकार ने एक बयान जारी किया जिसमें वियतनाम की घटनाओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त की गई। इस बयान की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है। हमारा कहना यह है कि इस स्थिति से जिन-जिन का सम्बन्ध है, सबसे पहले वे वियतनाम में अपनी सभी उत्तेजक कार्रवाइयां तुरन्त बंद कर दें और ऐसा कोई काम न करें जिससे स्थिति बिगड़े। संबद्ध मुख्य देशों को चाहिये कि वे वियतनाम की समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए आपस में मिलें। वियतनाम की वर्तमान स्थिति में, जब कि विभिन्न देशों में लड़ाई का ख़तरा बढ़ गया है, जेनेवा की तरह का सम्मेलन तुरंत बुलाना बहुत आवश्यक हो गया है। इस बारे में हम कई मित्र देशों से संपर्क बनाये हुए हैं। हमारी यह पक्की धारणा है कि वियतनाम की समस्या सैनिक स्तर पर नहीं हल की जा सकती और इसके राजनीतिक हल के लिए धैर्य के साथ प्रयत्न किया जाना चाहिये।

इस क्षेत्र के एशियाई देश के नाते हम वियतनाम की गम्भीर घटनाओं पर केवल गहरी चिंता ही व्यक्त कर सकते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि वियतनाम के लोग बाहरी हस्तक्षेप के बगैर, चाहे वह किसी भी ओर से हो अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का आनंद उठाएं। हमें आशा है कि वियतनाम की आज़ादी और स्वाधीनता चाहने वाले सभी देश वियतनाम का राजनीतिक हल खोजने में ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे और वर्तमान स्थिति को और बिगड़ने से रोकेंगे जो कि विश्व शांति के लिए खतरनाक है। इस उद्देश्य से सम्बद्ध पक्षों को एक सम्मेलन करना चाहिये और इस समस्या को शांतिपूर्वक हल करने का प्रयत्न करना चाहिये।

वियतनाम की घटनाओं के बारे में ८-२-६५ का भारत सरकार का वक्तव्य।

दक्षिण और उत्तर वियतनाम में पिछले दो दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भारत सरकार को गहरी चिंता हुई है। इन घटनाओं से वियतनाम में बड़े पैमाने पर लड़ाई का ख़तरा पैदा हो गया है जिसके भयानक परिणाम होंगे। इस क्षेत्र का एशियाई देश होने के नाते, ये घटनायें भारत की सरकार और जनता के लिये भारी चिंता का कारण बन गई हैं।

एशिया में और संसार में, शांति बनाये रखने के लिए, वियतनाम में युद्ध न होने देना चाहिये। जो देश शांति-प्रिय हैं, उन्हें इसकी तत्काल कोशिश करनी चाहिये कि झगड़ा बढ़ने न पाये और ऐसे कदम तत्काल उठाये जाने चाहिये जिनसे वियतनाम की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकल आये और 1954 तथा 1962 के जैनेवा क़रारों के अनुसार, हिंद-चीन राज्यों के लोग किसी के हस्तक्षेप के बिना अपनी स्वाधीनता का आनन्द उठा सकें।

यह स्पष्ट है कि वियतनाम में एक बात से दूसरी बात हुई और बहुत-सी तरफ से हस्तक्षेप भी किये गये। भारत सरकार का ख्याल है कि सब से पहला क़दम तो यह होना चाहिये कि वियतनाम की इस स्थिति में उलझे हुए सभी पक्षों द्वारा दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में भी सारी भड़काने वाली कार्रवाई तत्काल बंद कर देनी चाहिये और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे स्थिति बिगड़े। इससे वियतनाम के लिए तत्काल जेनेवा की तरह का सम्मेलन आयोजित करने का आवश्यक वातावरण तैयार हो जायगा जिसे भारत सरकार वियतनाम की समस्या का शांतिपूर्ण और पक्का समाधान करने के लिए आवश्यक समझती है। हिंद-चीन पर एक नये सम्मेलन का संयोजन अक्तूबर, 1964 में गुटों से अलग राष्ट्रों के काहिरा सम्मेलन की घोषणा के अनुसार किया जायगा।

भारत सरकार सभी संबद्ध देशों से आवश्यक वातावरण तैयार करने के लिए ईमानदारी के साथ अपील करती है जससे कि कोई देरी किये बगैर जेनेवा की तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा सके।

श्री नि० च० चटर्जी : क्या भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें उत्तर वियतनाम की मांग का उल्लेख हो कि वे उस देश से चले जायं, और क्या जनेवा सम्मेलन जैसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की दिशा में कोई कदम उठा रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमें अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का प्रतिवेदन मिला है और हम आयोग की अन्य शक्तियों से इस बारे में परामर्श कर रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या फ्रैंच सम्वाद समिति को अपना वक्तव्य देते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने यह बात कही है कि बड़ी शक्तियों को वियतनाम के मामले से दूर हट जाना चाहिये ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मेरा मत यह है कि अन्ततोगत्वा दोनों ही वियतनामों को स्वतन्त्र रहना है, अतः हमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अभी तक हमें कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। हम आयोग की अन्य शक्तियों से परामर्श कर रहे हैं, जैसा कि हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने अभी हाल कहा है।

श्री त्रिविध कुमार चौधरी : क्या वियतनाम के लिए किसी प्रकार के जेनेवा सम्मेलन की सम्भावना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस दिशा में प्रयत्न शील हैं और हमें इस बारे में कठिनाइयों का पूरा अहसास है।

सभा-पटल पर रख गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

1964–65 का आर्थिक सर्वेक्षण

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं "1964–65 के आर्थिक सर्वेक्षण" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3786/65]**

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(1) दिनाक 18 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2467 में प्रकाशित सूती कपड़ा (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1964

(2) दिनांक 26 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4318 में प्रकाशित सूती कपड़ा (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 1964

(3) दिनांक 2 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 31 में प्रकाशित सूती कपड़ा नियंत्रण (सातवां संशोधन) आदेश, 1964

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3787/65]

औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन तथा लाइसैन्स देना (संशोधन) नियम

भारी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

संयुक्त राज्य अमरीका, जापान के कारखानों के प्रमापीकरण तथा किस्त घटाने संबंधी प्रतिवेदन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 11 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1781 में प्रकाशित औद्योगिक उपक्रमों का पंजीयन तथा लाइसेंस देना (संशोधन) नियम, 1964 **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3663/64]**

(2) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया), लिमिटेड, भोपाल की वर्ष 1963–64 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

अमरीका तथा जापान के कारखानों में प्रमापीकरण तथा किस्म घटाने सम्बन्धी भारतीय उत्पादिता दल का प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 3788/65, 3789/65, 3790/65]

चाय बोर्ड कर्मचारी (आचरण) (दूसरा संशोधन) नियम, कपास नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1964, नारियल जटा उद्योग बोर्ड की लेखा परीक्षण रिपोर्ट ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 19 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1798 में प्रकाशित चाय बोर्ड कर्मचारी (आचरण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति ।

(2) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 23 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4374 में प्रकाशित कपास नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1964 की एक प्रति ।

(3) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम, के वर्ष 1963–64 के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 3790/65, 3791/65, और 3792/65]

नमक विभाग का प्रतिवेदन, सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का ज्ञापन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : मैं निम्न लिखित पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नमक विभाग की वर्ष 1963–64 की रिपोर्ट की एक प्रति ।

(2) सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का ज्ञापन तथा संस्था के अन्तर्नियमों की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० 3793/65 और 3794/65]

ग्लोबल कर्मशियल कम्यूनिकेशन्स सेटेलाइट सिस्टम के लिये अन्तरिम व्यवस्था

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : मैं ग्लोबल कर्मशियल कम्यूनिकेशन्स सेटेलाईट सिस्टम के लिए अंतरिम व्यवस्था करने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाईटेड किंगडम आदि की सरकारों के बीच हुए करार तथा विशेष करार की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3795/65]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
इकत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक) 1962–63 में प्रकट हुए **दत्तमत** अनुदानों तथा प्रभृत विनियोगों से अतिरिक्त व्यय के बारे में लोक लेखा समिति (1964–65) का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं 22 फरवरी, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्यक्रम की घोषणा करता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा ।

(2) 1964–65 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(3) निम्न विधेयकों पर चर्चा तथा उनको पारित करना :—

(एक) सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) जारी रखना विधेयक, 1965

(दो) आयकर (संशोधन) विधेयक, 1965

(4) शक्रवार, 26 फरवरी, 1965 से 1965–66 के लिए रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

और जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है कि 1965–66 का सामान्य बजट निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार, 27 फरवरी, 1965 को 5 बजे म. प. पेश किया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलदाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से जो 18 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से जो 18 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आय-कर (संशोधन) विधेयक, 1965

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INCOME-TAX (AMENDMENT) ORDINANCE

वित मंत्री श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1965 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण दिखाने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3759/65]।**

राष्ट्रपति क अभिभाषण पर प्रस्ताव

MOTION ON PRESIDENT'S ADDRESS

Shri Heda (Nizamabad): I am getting the honour of moving the motion of thanks to the President for his address. I move:—

"That an address be presented to the President in the following terms:—

'That the Members of Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on the 17th February 1965,'."

I have been hearing the address of the President for the last 15 years. I feel that this time the address was very short and expressive. It gave the real picture of the nation. It has also vividly portrait the Government's policy towards all the problem. I would like to state that as has been pointed out in the address the Country has made very significant progress in the industrial field. The credit for their progress went to the planning Commission. However, the planning Commission sometimes planned too much in their over enthusiasm and became a prey to their own doings. The production of Sugar and Cement are the examples of such planning.

This can be stated very safely that our Prime Minister has adopted a very reasonable and practical attitude in laying emphasis on early maturing projects. It is hoped that would lead to an increase in production at a greater speed. We must understand that socialism has a direct connection with the production. Unless we produce more it will not be possible to establish the socialist pattern of society.

It is also a matter of great satisfaction that this year we are going to have a record crop. Our Prime Minister also made a broadcast appeal to the farmers to increase agricultural production. This is also a matter of fact that it is not possible to check the rise of food-grain prices without building up a buffer stock. But the claim of the Government that the prices have been stabilised is not completely correct. It appears from the situation that the enough food-grains are not being up into the buffer stock. This might result that after a few months the price will again begin to rise. Then it does not remain the stable solution of the most important problem before the country.

There is no doubt about it that we have tried our level best to achieve the advantages of Socialist economy by adopting the mixed economy. The prices as we know well, are being determined by the law of supply and demand. But this law can only work freely in free economy. I feel that it is very necessary to give serious thought to the matter and adopt measures which might keep the prices in check. And this is the Socialist economy. Together with that we should see that we dont resort to an economy of scarcity. Whatever we may produce, but it should be seen that it is enough for our requirements. If this fact will be ignored, the result will be that black market will prevail. We can quote the example of the production of Cars.

Now, I may come to the problem of production. In order to step up production, it is very necessary that the permission to import raw materials in greater quantity should be allowed. This facility should be given to the factories. They should be prevailed upon to increase production. Their maximum capacity of production should be increased by improving the labour-employer relations and allowing the labourers a share in the profits.

The incidents have told us that the Government will not be able to check the inflationary tendency. We could check the effect by increasing the production and creating more employment opportunities. I would also like to suggest the method of encouraging the house building activity. This should also be urged that restrictions on banks in this connection may be removed.

Character building is also a vital problem of the nation. This is a fundamental question. People here in this country are developing a tendency to resort ing to any method that led to the acquisition of riches or of political power. That mentality should be depreciated. The Government should learn to take the necessary steps in good time. Otherwise, they lost in prestige. The charges of corruption should be very promptly dealt with. The way in which the Orissa affairs were handled by the Government have not given any credit to them. We welcome the foreign aid, but we should try to stand on our own legs. Every effort should be done to make the country self-sufficient in every matter. I may also state that the plutonium plant in Bombay have been completed by our scientists without any foreign and technical aid. That is a very creditable thing. With courage and confidence, much can be achieved in my fields.

This is really satisfying to note that our relations with the neighbouring countries have sufficiently improved. This has been achieved under the leadership of the present Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. We have improved

our relations with Nepal, Bhutan and Ceylon. We are going on very friendly with Burma and Afghanistan. It is really sad that we have not been able to improve out relations with Pakistan. International situation is becoming very tense. But we hope that following the Policy of the late Prime Minister Nehru we will be able to bring about a peaceful solution of the difficult problem of the world.

Whatever has been done in connection with Nagaland is not very encouraging. The time that we are losing in Nagaland is only increasing the anti-national elements there. It is a high time now that Government gave a serious thought to the problem.

Now I come to pressing problem of today that the problem of official language. It is really very sad that the language agitation in South India was engineered by certain political interests. The D.M.K., the leftist Communists joined hand to use the situation for their political ends. They exploited and fanned the feelings of the people. I am of the opinion that in this matter the failure of the Government lay in not countering the misleading propaganda well in time. They ought to have dispelled the fears of the people to a great extent if the radio broadcast of the 11th February by the Prime Minister was made a month before.

This is also truth that little has been done by the Government during the last 15 years for the propagation of Hindi. Central Government ought to have taken the responsibility of teaching Hindi to the people of the South and to the people of the non-Hindi areas. They should also have stood the expenditure involved in it. Such an important matter should not have been left to the individual State Government. The education Ministry has slept over the suggestion of Loknagri script made by Shri Vinoba Bhave, this would have helped in the task of the propaganda of Hindi.

In the South, particularly in Andhra and Karnatak, there was a great deal o sympathy and support for the Hindi. In Madras and Kerala also more and more people were learning Hindi. We should understand this fact and tell the people also that Hindi and the regional languages were supplementary and not opposed to each other. It might be recalled that greater efforts were made by the non-Hindi people than by the Hindi people to propagate Hindi. Gandhiji's name is the foremost in this connection. I may also state that in order to allay the fears that have been raised, an amendment of the constitution or of the Official Language Act is not necessary. A resolution of the Parliament should be sufficient. Thereafter concrete steps should be taken for the propagation of Hindi. We should also try to dispel the fears of the people of South India. With these words I move this resolution.

महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : श्री हेडा ने जो पूरी योग्यता के साथ धन्यबाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं उन से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं। भाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जो विचार अपने अभिभाषण में व्यक्त किये हैं उसको देखते हुए हिंसा और सभी प्रकार के आन्दोलन बन्द हो जाने चाहिएं। अभी तक भी वहां लोग गड़बड़ कर रहे हैं और मौतें भी हुई हैं। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने भी पंडित जी के आश्वासनों को दोहराया है । इस हिंसक कार्यवाहियों से शांति पूर्वक हल तलाश करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । कितने खेद की बात है कि राष्ट्रपति का घर भी जला दिया गया । हमें किसी भी वस्तु को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । हम सब भारत मां के बेटे हैं, चाहे कोई उत्तर के हों अथवा दक्षिण के हों । अतः अब जब कि आश्वासन दे दिये गये हैं, यह सब गड़बड़ बंद होनी चाहिए । हमें आदान-प्रदान की भावना से काम करना चाहिए ।

राष्ट्रपति महोदय ने चीनी खतरे का भी उल्लेख किया है । उन्होंने कहा कि हम हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ रहे हैं परन्तु हमारे पर कोई आक्रमण हो तो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आज भी गुटों में शामिल न होना सहअस्तित्व के सिद्धान्त ही हमारी विदेश नीति के आधार हैं। और हम हमेशा इस विचार के रहे हैं कि मानव की प्रगति के लिए शांति का होना बड़ा आवश्यक है। मेरा निवेदन यह है, कि शांति शक्तिशाली के लिए नहीं है, परन्तु न्याय के लिए है ।

हमें यह जानकर सन्तोष होता है कि देश इस समय विदेशी किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार है । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शारीरिक शिक्षा का भी कुछ उल्लेख होना चाहिए था। । आशा करनी चाहिए कि झगड़ें वाली समस्याओं का निपटारा शीघ्र ही हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके साथ माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु इन बातों पर खेद व्यक्त करते हैं —

(क) संघ की भाषा नीति को हल करने के लिये उपयुक्त सूत्र निश्चित करने में असफलता ;

(ख) चीन से भारतीय भूमि वापिस लेने के लिये उचित कार्यवाही नहीं की गई ;

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों में वृद्धि और बिगड़ती हुई खाद्य स्थिति को रोकने में, उत्तर प्रदेश को आयात किये गये गेहूं का आश्वासित कोटा न देने और गन्ना उत्पादकों के हितों का संरक्षण करने में असफलता ;

(घ) पिछड़ी हुई जातियों को ऊंचा उठाने में असफलता ;

(ङ) कि अभिभाषण में प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा, अंग्रेजी को प्रोत्साहन और उत्तर तथा दक्षिण के बीच भेद-भाव उत्पन्न किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ;

(च) कि अभिभाषण में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नौकरशाही के प्रभाव को हटाने के लिये कोई सुझाव नहीं है ;

(छ) कि अभिभाषण में शोचनीय कानून तथा व्यवस्था और प्रशासकीय अकर्मण्यता तथा लापरवाही के बारे में जिसका ज्वलन्त उदाहरण कैरों जैसे व्यक्ति की हत्या और अब तक अपराधियों का न पकड़ा जाना है, कोई उल्लेख नहीं है ;

(ज) कि अभिभाषण में भारत सुरक्षा कानून की निरर्थकता, केरल चुनाव के अवसर पर बामपंथी साम्यवादियों की गिरफ्तारी और संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों के प्रति जेलों में दुर्व्यवहार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ;

(झ) कि अभिभाषण में प्रधान मंत्री के आश्वासन के अनुसार सामुदायिक विकास खंडों से जीपें न हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ;

(ञ) कि अभिभाषण में आर्थिक असमानता दूर करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है ।" (1)

डा० **लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् ——

"किन्तु इन बातों पर खेद व्यक्त करते हैं :——

(क) भाषा के प्रश्न के बारे में निदेशों की नितान्त असफलता ;

(ख) कि अभिभाषण में देश में उपलब्ध बेरोजगार जनशक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग किये जाने के बारे में और देश को समृद्ध बनाने के लिये विकास सम्बन्धी कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी लेने के लिये जन साधारण को प्रोत्साहित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ;

(ग) कि देश में खाद्य नीति की असफलता और खाद्य नीति की क्रियान्विति में उचित समन्वय प्राप्त करने में असफलता जिस से कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल होने पर भी खाद्य के अभाव की समस्यायें हमेशा की तरह जटिल रही हैं ;

(घ) कि बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारी आर्थिक प्रगति के समाप्त हो जाने की आशंका है ;

(ङ) कि स्कंडिनेविया के ओम्बुडसमैन जैसे "लोकायुक्त" का पद बनाने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

(च) चीन की अणु हथियारों की धमकी का मुकाबला करने के लिए फिर से आश्वासन दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।" (2)

श्री त्रिविध कुमार चौधरी (बेरहामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :——

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :——

"किन्तु खेद है ——

(क) कि भारत के वामपक्षी साम्यवादी दल के सदस्यों तथा अन्य वामपंक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा मजदूर संघ कार्यकर्ताओं की जिन में संसद्-सदस्य भी शामिल हैं, भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत झूठे आरोपों पर जिन्हें न्यायालय में सिद्ध नहीं किया गया है अविवेकपूर्ण ढंग से की गई गिरफ्तारी और नजरबन्दी तथा उन आरोपों को किसी भी प्रकार सिद्ध करने में सरकार की असफलता के बारे में जब कि गिरफ्तारी तथा नजरबन्दी के बारे में दिसम्बर, 1964 में आरम्भ की गई नीति को अब कई सप्ताह हो गये हैं, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है ।

(ख) कि अभिभाषण में इन के बारे में पर्याप्त उल्लेख नहीं है –

(एक) देश में खाद्य तथा मूल्य स्थिति और मूल्य स्थिर रखने में सरकार की असफलता ;

(दो) मुनाफाखोरों, जमाखोरों तथा सटोरियों के छिपे काले धन का प्रभाव तथा उसे हटाने में सरकार की असफलता ;

(तीन) अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिये, भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुरूप सामान्यतया स्वीकार्य राज-भाषा नीति निर्धारित करने में सरकार की असफलता तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिये समान प्रोत्साहन देने में उसकी असफलता ; और

(चार) पड़ौसी राज्यों के साथ सम्बन्धों में सुधार करने तथा चीन लोक गणतंत्र के साथ सम्बन्धों में हुए गति रोध को समाप्त करने अथवा भारत के विरुद्ध चीन या पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण को खाली कराने में सरकार की असफलता "। (3)

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में वह जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है —

(क) कि अभिभाषण में यह गलत कहा गया है कि अंग्रेजी तब तक जारी रहेगी जब तक कि अहिन्दी भाषी लोग उसकी आवश्यकता समझें जब कि स्थिति यह है कि किसी अहिन्दी राज्य की प्रादेशिक भाषा सह-राज-भाषा के रूप में तब तक रहनी चाहिए जब तक कि वे हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार न करें।

(ख) कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सभी राजनीतिक दलों का भावात्मक रूप में मिलकर, चीन की चुनौती का सामना करने के लिये केन्द्र में तथा राज्य में एक राष्ट्रीय सरकार कायम करने के लिये आह्वान नहीं किया है ।

(ग) कि अभिभाषण में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी मतदाता परिषदें संगठित करने में जो—

(एक) उत्तरदायी विधायकों को चुनें ;

(दो) उन्हें लोकतन्त्रात्मक राज्य के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी दें; और

(तीन) महत्वपूर्ण विधानों के संबंध में जनता की वास्तविक राय से अवगत हों ।

असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है " (4)

श्री उ. मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में

(क) खाद्य पदार्थों तथा उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि और उन्हें बढ़ाने से रोकने के लिये किये गये उपाय ;

(ख) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के क्षेत्रों और चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जे में किये गये राज्य क्षेत्र को वापस लेने के लिये उठाये गये कदम ;

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के जीवन-स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये उठाये जा रहे कदम ;

(घ) राजनीतिक नेताओं के जीवन की सुरक्षा के लिये उठाये गये कदम ;

(ङ) नागालैंड में सुरक्षा तथा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था ; और

(च) हिन्दी को भारत की राजभाषा बनाने में आमूल परिवर्तन करने के लिये उठाये गये कदम ;

के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ;" (5)

श्री मी० ह० मसानी (राजकोट): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं :—

(क) कि अभिभाषण अनुचित आत्मतुष्टि और आत्म सन्तोष की भावना का अतिशय मात्रा में व्यापक प्रदर्शन करता है और गम्भीर आर्थिक स्थिति, खाद्य की कमी तथा बढ़े हुए भावों के कारण लोगों को जिस यातना का सामना करना पड़ा है, और 17 फरवरी को लोक-सभा में वित्त मंत्री के वक्तव्य से प्रकट हुई देश की चरम-सीमा को पहुंची हुई आर्थिक दुर्दशा की ओर कोई संकेत नहीं करता है,

(ख) कि इस में मुद्रास्फीति को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के शीघ्र विकास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने की नीति के बारे में कोई संकेत नहीं है ,

(ग) कि किन्तु इस के विपरीत अभिभाषणों में चतुर्थ योजना के विषय में जो ज्ञापन दिया है, उस के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी और अर्थ-व्यवस्था ठप्प हो जायेगी जिस से पता लगता है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की असफलता से जो अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकी, कोई शिक्षा नहीं ली गई है ।

(घ) कि अभिभाषण में ऐसी सुनिश्चित नीति का सुझाव नहीं दिया गया है, जिससे कि भारत साम्यवादी चीन द्वारा आणविक दबाव का भली प्रकार सामना करने के योग्य हो सके ।

(ङ) कि दक्षिण-पूर्व एशिया में हाल में हुई घटनाओं पर चिन्ता प्रकट करते हुए अभिभाषण में जेनेवा के ढंग का एक और सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया गया है चाहेतथ्य यह है कि इस क्षेत्र में वर्तमान विकट स्थिति क्रमशः वियतनाम और लाओस सम्बन्धी पिछले दो जेनेवा सम्मेलनों का सीधा परिणाम है, और अभिभाषण से इस तथ्य को समुचित रूप से समझने का अभाव प्रकट होता है कि स्वयं भारत की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि चीन के साम्यवादी विस्तार वाद से लाओस, मलेशिया और वियतनाम की रक्षा की जाये ;

(च) कि अभिभाषण में मलेशिया की सरकार और लोगों को उन पर किये आक्रमण के प्रतिरोध करने में समर्थन व्यक्त नहीं किया गया है और मलेशिया को सैनिक सहायता देने के बारे में भारत के तैयार रहने का आश्वासन देने का उल्लेख नहीं है ।" (6)

श्री प्र. के. देव (कालाहांडी): मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं :—

(क) अभिभाषण में देश से भ्रष्टाचार का, जिस ने केन्सर की तरह फैल कर देश की नैतिकता को समाप्त कर दिया है, उन्मूलन करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।

(ख) कि अभिभाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं है :—

(एक) उड़ीसा के विपक्षी संसद्-सदस्यों , विधान सभा के सदस्यों तथा कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये स्मरण पत्र जिस में उन्होंने उड़ीसा के भूतपूर्व तथा वर्तमान मुख्य मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं और उस पर की गयी कार्यवाही ।

(दो) उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों पर मंत्रिमंडल उप-समिति का आरोपों को अपने आरोपों की पुष्टि का अवसर दिये बिना मन-माना निर्णय तथा केन्द्रीय जांच विभाग की रिपोर्ट को गुप्त रखने का निर्णय ।

(तीन) उड़ीसा के भूतपूर्व तथा वर्तमान मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपों पर जांच आयोग की नियुक्ति जब कि भूतपूर्व मंत्री ने इन आरोपों के विषय में केन्द्रीय जांच विभाग के प्रतिवेदन पर आपत्ति उठाई थी ।

(ग) कि देश में मितव्ययता की आवश्यकता पर जोर देते हुए भी अभिभाषण में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि देश में निरंकुश, अवैज्ञानिक तथा अलाभप्रद योजनाओं को, विशेष रूप से उड़ीसा की टिकरपारा बांध परियोजना को छोड़ दिया जाये ।" (7)

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं की ओर तथा दक्षिण में हाल में हुए दंगों और भारत सरकार की भाषा नीति को कार्यान्वित करने के फल-स्वरूप सेना के बुलाने से स्थिति के गम्भीर होने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता रही है ।" (8)

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये , अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि इन बातों में असफलता रही है —

(क) खाद्य संकट को दूर करने में और अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों को बढ़ने से रोकने में ,

(ख) प्रशासन में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को दूर करने में,

(ग) समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में पटेल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में,

(घ) देश में श्रमजीवियों विशेष कर सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक श्रमिकों , की वास्तविक मजूरी में कमी को रोकने में ,

(ङ) जनवरी, 1964 से पहले और बाद में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लाखों लोगों को उचित रूप से बसाने में,

(च) भाषा के प्रश्न को सुलझाने में, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं और पुलिस तथा सेना द्वारा लोगों पर बिना सोचे समझे गोलियां चलायी गई जिस से बहुत से लोग मारे गये और घायल हुए,

(छ) प्रशासन, शिक्षा तथा केन्द्रीय सेवाओं के सम्बन्ध में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं को मान्यता देने तथा वैध बनाने में,

(ज) आपातकालीन स्थिति को समाप्त करके नागरिकों को लोकतंत्रात्मक अधिकारों की गारण्टी देने तथा भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये और निरुद्ध सभी व्यक्तियों को रिहा करने में ।" (9)

श्री मोहम्मद इस्माइल (हावड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव (के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि

(क) कि भाषा के प्रश्न पर हुई गम्भीर घटनाओं को रोकने के लिये उचित उपाय करने और प्रशासन के समय पर दूरदर्शिता से काम न करने पर अभिभाषण में पर्याप्त बल नहीं दिया गया है,

(ख) 1964 के आरम्भ में देश के पूर्वी भागों में हुए विनाश के शिकार असंख्य व्यक्तियों को पुनः आश्वासन और सहायता देने के लिये किये गये उपायों की प्रगति के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) भारत रक्षा नियमों के अधीन निरपराध व्यक्तियों विशेषकर मुस्लिम जाति के अल्प-संख्यकों की अधांधुंध गिरफ्तारियों से उत्पन्न और बलात्कार की घटनाओं का जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में मृत्यु भी हुई है, अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हुआ है ;

(घ) देश के कुछ भागों जैसे आसाम और केरल के आर्थिक विकास में पिछड़ेपन को कम करने के विशेष प्रयोजनार्थ किये गये वास्तविक उपायों के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ;

(ङ) देश के विधान मण्डलों और विभिन्न सेवाओं में मुसलमान अल्पसंख्यक जाति के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ; और

(च) उर्दू भाषा के प्रादेशिक रूप को व्यवहार में मान्यता देने के संबंध में संविधान में यह जो गारंटी दी गई है उस में मान्यता देने के बारे में प्रशासन की निरन्तर असफलता का अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (10)

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद): में प्रस्ताव करता हूं :—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये ; अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं —

(क) कि जनता को शैक्षणिक तथा मनोवैज्ञानिक तौर पर संविधान में निर्धारित राजभाषा को स्वीकार करने के लिये तैयार करने के लिए उपयुक्त उपाय करने में सरकार असफल रही है जिस के फलस्वरूप कुछ राज्यों में भाषा संबंधी परिवर्तन से व्यापक असन्तोष तथा तीव्र विद्वेष की भावना व्यक्त हुई ;

(ख) मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए और खादान्नों तथा अन्य आत्यावश्यक वस्तुओं के मल्यों में अतिशय वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाने में असफलता रही है इसके परिणामस्वरूप समाज के निर्धन एवं मध्य वर्ग की जनता को असह्य कठिनाईयां सहन करनी पड़ी हैं ;

ग) कि अभिभाषण में चीनी आक्रमणकारियों को भारत की पवित्र भूमि से खदेड़ने के लिये संसद् द्वारा ली गई निष्ठापूर्ण शपथ का कोई उल्लेख नहीं है, और पाकिस्तान तथा चीन के बीच गठबन्धन से भारत को जो भावी खतरा पैदा हो गया है उस पर सरकार की जागरूकता का अभाव प्रकट होता है ;

(घ) जब कि अभिभाषण में सरकारी नीतियों का आधार सम्पन्न समाजवादी समाज का विकास घोषित किया गया है तथापि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बेरोजगारी, शोषण तथा पूंजीवादियों की सत्ता से मुक्त समाजवादी व्यवस्था की ओर राष्ट्र की प्रगति के लिए कोई सुनिश्चित कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया ;

(ङ) खेतीहर मजदूरों की आर्थिक दशा सुधारने में किसानों को सामाजिक न्याय तथा उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में जिसके बिना खाद्यान्नों का उत्पादन तथा विकास नहीं हो सकेगा और खाद्य समस्या हल न होगी, सरकार द्वारा जानबूझ कर अनवरत उपेक्षा की जा रही है । (11)

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

12. कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि अभिभाषण में इन बातों का उल्लेख नहीं है—

(क) आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की कमी जिसके कारण देश की वाणिज्यिक और वित्तीय स्थिरता खतरे में है ;

(ख) भारत-पाक सीमा पर निरन्तर आक्रमण की स्थिति और पाकिस्तानी पत्र-पत्रिकाओं और रेडियो में निरन्तर भारत विरोधी प्रचार ;

(ग) काश्मीर और नागालैंड के सम्बन्ध में कछ भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा भारत विरोधी कार्यवाहियां ;

(घ) मूल्यों को स्थिर रखने में असफलता और मध्यम वर्ग के तथा कम आमदनी वाले वर्गों की अत्यन्त कठिनाई ;

(ङ) सरदार प्रताप सिह कैरों की जो प्रधान मंत्री से मिलने दिल्ली आये थे, दुखद हत्या । " (12)

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव तथा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम एक दल के रूप में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उनका धन्यवाद नहीं कर सकते । यदि उनके अभिभाषण का गहन अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि उससे सरकार की सफलताओं को बड़ा अच्छा विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया । गत वर्ष लोगों को कष्ट हुए हैं उनका बहुत ही कम उल्लेख किया है । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह बताने का प्रयत्न किया है कि सरकार ने इस वर्ष बहुत कुछ कर दिखाया है । मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ बताया गया है वह बहुत ही बड़ा भ्रम है । देश में खाद्यान्नों का सर्वत्र अभाव महसूस किया गया है । और इससे देशवासियों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा है । परन्तु खेद की बात है कि अभिभाषण में इसका तनिक भी उल्लेख नहीं किया गया । गत वर्ष जो स्थिति देखने में आई थी उसका मुख्य कारण सरकार की नियंत्रण नीति तथा क्षेत्रीय नीति थी । लगाये गये प्रतिबन्ध भी इसके लिए उत्तरदायी

थे । कुछ उस स्थिति के चल रहे भूमि विधान भी कारण थे । सरकार स्थिति पर काबू पाने में बिल्कुल असमर्थ रही है । मंत्री महोदय को भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि स्थिति काफी गम्भीर है ।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के देहान्त का हमें बड़ा दुःख है परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम इस बात को भूल जायें कि किस प्रकार संविधान के सतरहवें संशोधन को पारित किया गया था । संविधान के सतरहवें संशोधन द्वारा सरकार ने लाखों कृषकों से उनका काफी लम्बे काल से स्थापित परम्परागत अधिकार छीन लिया । सरकार ने कृषक से उसका प्रोत्साहन ही छीन लिया । यह भी तथ्य बड़ी स्पष्टतः से देश के समक्ष आ गया है कि सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से लाभ बहुत ही कम हुआ है । जनता पर आय का भार 1955–56 के मुकाबले में तिगुना है ।

श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए
Shri Thurumal Rao *in the chair*

मेरा निवेदन यह है कि सरकार लोगों की कमर तोड़े बिना तथा उद्योग और खेती के क्षेत्रों में प्रोत्साहन छीने बिना अधिक कर लगा कर रुपया एकत्रित नहीं कर सकती । इससे यह भी सम्भावना हो सकती है कि उत्पादन कम हो जाय । हो सकता है कि इतनी राशि विदेशी सहायता के रूप में भी प्राप्त न हो सके । 4466 करोड़ रुपये हम विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त कर चुके हैं । अब आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क बढ़ाया जा रहा है और बैंक दर भी बढ़ाई जा रही है । कोई यह बात नहीं कह सकता कि हीन अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लिये बिना विशाल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें । मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो योजना टूट जायेगी और या लोगों की कमर टूट जायेगी ।

उत्पादन बढ़ाने और मूल्य कम करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा । दोनों पर आयात कर का प्रभाव विपरीत ही होगा । बैंक दर में वृद्धि भी उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन को मिटाने का कार्य करेगी । विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति चिन्ताजनक है । स्थिति वर्ष के आरम्भ में ही ज्ञात रहनी चाहिये थी तथा उस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिये थी । हमारा आयात निर्यात की तुलना में निरन्तर बढ़ता जा रहा है । देश में योजना निर्माण के कार्य में व्यर्थ के व्यय की मनोवृति पाई जाती है जो प्रशासन तथा औद्योगिक विकास दोनों क्षेत्रों में है । अतएव यह खतरनाक है कि हम योजनाकाल में इतनी बड़ी राशियों के व्यय की बात करें । अधिक अच्छा होगा कि हम योजना के वार्षिक व्यय के आंकड़ों से संबंध रखें । व्यय के प्रसंग में उससे अधिक अच्छे प्रमाण प्राप्त होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Deputy Speeker *in the chair*

पी एल 480 सहायता का दीर्घकालीन प्रभाव यह है कि आत्म अनुतोष की भावना उत्पन्न हो गई है जिससे हमारे उत्पादकों को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल सकेंगे । किसान लोग कृषि के कार्य में अपेक्षित वस्तुओं के अधिक दामों से पीड़ित तथा दुरुत्साहित हैं । वे उपभोग वस्तुओं के दामों के अधिक होने से भी पीड़ित हैं तथा उन निबन्धनों से भी जो उनके मार्ग में बाजार के दाम वसूल करने में रोड़ा अटकाती है । उन्हें अपने उत्पादन के लाभप्रद दाम मिलने चाहियें ।

सरकार अकेले ही चीनी आक्रमण के विरुद्ध देश की रक्षा नहीं कर सकेगी । हमें अमरीका से प्रतिरक्षा के लिये उस सहायता को स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिये जिसे देने का उसने प्रस्ताव किया है । जब हम अमरीका से बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता स्वीकार करते हैं तो कोई

और कारण भूतपूर्व प्रधान मंत्री की नीतियों पर न चलने या रूस के रोष का डर--हमारे प्रतिरक्षा सहायक प्राप्त करने के मार्ग में नहीं आना चाहिये । हम प्रतिरक्षा पर व्यय पर्याप्त रूप से घटा सकेंगे । मुद्रास्फीति का शिकार हुये बिना तथा जनता पर कर का भार बढ़ाये बिना हम औद्योगिक उत्पादन तथा औद्योगिक साज-सामान का विकास करने के योग्य हो जायेंगे ।

दक्षिण वियतनाम तथा लाओस में साम्यवादी चीन शांति भंग कर रहा है न कि दक्षिण वियतनामी और लाओस के लोग और न ही अमरीकी । भारत को 'मलेशिया' के पक्ष में आवाज उठानी चाहिये जहां के प्रधान मंत्री ने चीनी आक्रमण के समय घोषणा की थी कि सभी मलेशिया वाले हृदय से भारत के साथ हैं । सम्भवत: सांकेतिक रूप में अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां और कुछ हथियार 'मलेशिया' सरकार को दे सकते हैं ताकि वह उसे इंडोनेशिया के विरुद्ध युद्ध में प्रयोग कर सके । इससे हमारे पड़ौसी देशों और अमरीकी देशों में हमारा सम्मान बढ़ेगा ।

भाषा संबंधी आन्दोलन में केवल तामिल वालों ने ही नहीं बल्कि केरल और आंध्र के लोगों ने भी भाग लिया है । यह सभी घटनायें लोक राय के दबाव के कारण हुई हैं । लोगों का सरकार से विश्वास उठ गया है । जब तक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में इसकी नीतियों में परिवर्तन न किया जायेगा तब तक न केवल इस मंत्रालय के लिये बल्कि जनता के लिए भी विनाश और दुर्भाग्य होगा । इससे पहले कि हम जेनेवा जैसे किसी सम्मेलन आदि की बात करें पहले हमें मलेशिया को सैनिक सहायता देनी चाहिये जो अपने से बड़े देश इंडोनेशिया का सामना कर रहा है । तभी दूसरे देश हमें आदर की दृष्टि से देखेंगे । इस समय कोई भी देश चाहे वह अफ्रीका का हो या एशियाई भारत का आदर नहीं करता । हम तो पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं हैं और जैसा राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है संकट हमारे सिर पर छा रहा है । और यह संकट तभी टल सकता है जब हम अपनी गृह नीतियों को, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर पर और राष्ट्रीय मामलों में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर के उन्हें बदलें और यह कहें कि हमने गलत योजनाएं बनायी हैं हम अपने सामर्थ्य के अनुसार योजनाए बनायें और लोक वित्त व्यवस्था जिसे हमने समय समय पर विघ्न डाल कर खराब होने दिया है फिर से नियंत्रित करें और जीवन के हर क्षेत्र में लोगों को अच्छा आध्यात्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन बिताने का अवसर दें ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है । कई स्थानों पर आन्दोलन, हड़तालें आदि हुयी हैं परन्तु जनता इन सबसे उदासीन है यही कारण है कि यह सफल नहीं हुई । स्थिति हर जगह खराब होती जा रही है । केरल, आंध्र आदि में जो कुछ हो रहा है वहां राजनैतिक दल कुछ नहीं कर रहे जैसे मेरे दल के नेता ने अपनी पार्टी से कहा है कि वह इससे अलग रहे। यहां जनता ने अपने विचार से अपनी राय से काम लिया है और कई नवयुवकों की जानें गई हैं । चुनाव के समय सरकारी मशीनरी काम में लायी जाती है जो बिचारे मतदाताओं को 'समझाने' का कार्य करती है परन्तु शांत वातावरण में ऐसा कुछ नहीं किया जाता । चुनाव तो इन तरीकों से जीते जा सकते हैं परन्तु जनता का हृदय नहीं जीता जा सकता और जब तक यह नहीं होता हमें अपनी योजनाओं में सफलता नहीं मिल सकती सरकार को अपना रवैया सुधारना होगा तभी यह देश विनाश से बच सकता है । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उन लोगों को जो आज सरकार सम्भाले हुये हैं, सद्बुद्धि दे ।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : श्रीमान्, मेरे और श्री मनोहरन के नाम के आगे जो संशोधन है, वह, पहले जब आपने हमारे नाम पुकारे तो मेरी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अब इसे प्रस्तुत समझा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विशेष रूप से ऐसा कर रहा हूं ।

श्री सेझियान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये ; अर्थात् :—

"किन्तु खेद व्यक्त करते हैं कि दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं की ओर तथा दक्षिण में हाल में हुये दंगों और भारत सरकार की भाषा नीति को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप सेना के बुलाने से स्थिति के गम्भीर होने की ओर पर्याप्त ध्यान देने में असफलता रही है ।"

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : During the period when Dr. Rajendra Prasad was the President, the Address to both the Houses of Parliament was always delivered first in Hindi and then in English but this procedure has been reversed, some years back. Our Vice-President who does not know Devnagri script is able to read the Address in Hindi whereas the President, though he knows the Devnagri script quite well, is reluctant to deliver the Address in Hindi. It would have been better if he had delivered it either in Hindi or even in Telugu because under Article 120 of our Constitution, Hindi has become the official language of our country with effect from 26th January, 1965. I hope the President will do so in future.

As has been informed from time to time by the Government the Public Sector undertakings are running at a loss continuously and the total loss so far is Rs. 21,500 crores. I have to draw Government's attention to this aspect of running continuous losses. Plans should not be an end in themselves. These must be looked at for their effects. Government should, therefore, review them for the good of the country.

The law and order situation is deteriorating day by day. Today the life of the common man does not appear to be safe. Even after fifteen days' of Shri Kairon's murder nothing is known of the culprits. There was a time when police was quite alert and such cases were investigated expeditiously. The Government is losing its hold and chaotic conditions are prevailing all around. That may be our first 'achievement'.

The second 'achievement' is in respect of foreign loan. The burden of loan on Indian masses has enormously increased and whether it proves a boon or a curse for the future generation is best known to the Government who according to Hindu concept is like father and our mythology says that a father who bequeaths loans and credits is an enemy.

The third "achievement" is the continuing declining agricultural production in the country. The imports have increased from 5 lakh tons to 63 lakh tons in 14 years. In Gujarati there is a saying that when the Government comes to business, the public is reduced to begging. This is the condition of the country to-day.

The fourth "achievement" is the ever-rising prices. Wheat, rice, and ghee, everything is scarce and the prices are most exorbitant.

The fifth "achievement" is regarding inflation. No remedial measures are being taken to check this. The value of an Indian rupee today is only 17 paise.

The sixth "achievement" is the increasing phenomenon of English ways of life. The infiltration of these was less when the English ruled us. Today parents teach their children to address them as Daddy & Mummy and these are called progressive ways in civilisation.

The seventh "achievement" is the progress in taxation. Every commodity has been taxed. There are taxes on cycle and every part of it. Tobacco, the sick people who are alive also have to pay tax before they are treated, there are taxes even on the dead in the shape of Estate Duty.

The last "achievement" in the list is the circulation of obscene magazines like the Confidential Advisor. I do not know how such magazines have been allowed to be published and circulated in the market. Drinking, gambling, corruption and graft, prostitution and moral turpitude of every description is rampant in the country.

I could mention many more such 'achievements' but I would not mention them here for the present. I admit the rail and road facilities have increased and there are radios in practically every house. But the Government cannot claim cudos for this progress. These are the reactions of universal revolutionary process. 21,500 crores of rupees also are being lost. Already we have paid 119 crores of rupees on 1700 crores of investment in three years. The Government should be sorry for that.

The five year plans are nothing but a wild goose chase. The Government have, on the basis of bookish knowledge, acted quite contrary to commonsense and reality. Do the Government want to waste another amount of Rs. 21,500 crores? I would request the Government to refrain from this and save the coming generation from the back-breaking burden of loans.

I regret to say that I do not follow our five year defence plan. The enemy may come to kill us tomorrow but our rifles and pistols will come out of factories only day after to-morrow. The essence should be that before the enemy attacks us, we may be already in a position to defend ourselves.

Now if we look at our policy towards China, we will come to know that we have made many mistakes. We did not help those, whom we should have and now the result is that China has come in direct contact with us. Now impregnable Himalaya has been crossed over. At the time of necessity, one should be prepared even to befriend a devil. A delegation of our M.Ps. went to Taiwan but the Chinese Government has objected to it. What right has China got to do so?

I had an occasion to see some statistics about petrol which is reaching China through Hong Kong. When Russians stopped supply of petrol to China, the British supplied it to Hong Kong and which in turn is being smuggled into China. But we did not object to it. Every country is awake now except our country.

Now when I am speaking on the defence policy I have in mind the questions of East Pakistan, Kashmir and the new trouble in Nagaland. All these problems are due to our policy of appeasement. In Kashmir we are adopting a policy of appeasement of Shiekh Abdullah and Mridula Sarabai. This daughter of one Gujerati Ambalal Sarabai, is also after us with a cudgel. I do not know whether she holds any office in Congress. To-day, we are in a position neither to face Pakistan nor any other country. Pakistan has occupied a large

chunk of our territory but we cannot retake it. China too after aggression has occupied 18,000 square miles of our territory but we have not prepared ourselves even to retake it. I do not find any word in the President's Address about these things. Have we forgotten that we in this House took a pledge that we will not take rest until we get back every inch of our territory? Was that pledge only an exercise in futility? Has that also gone with the passing away of Jawaharlal Nehru?

Our Government also talks about non-alignment and co-existence. I do not know with whom they want us to co-exist. We do not befriend even Israel. It is not that we are afraid of Russia that we have refused to be friendly with Israel but it is due to our being afraid even of Arabs that we do not do it. We should tell the Arabs frankly that if there is a quarrel between them and Israel, that should not be a reason for us to be against Israel. I say that we should pay compliments to the Israil that they with a population of only 20 lakhs people are boldly facing the Arabs who number 7 crores. Why do not we support Malaysia which is a small country and yet has tewenity enough to face Indonesia, which in turn is getting all help from China.

I may also mention something about our laws as given in our Directive Principles which says that "there shall be a uniform civil code for the whole country". Why have you forgotten it? For Hindu women a law has been passed which has given them more powers than men but in the case of Mohammedan women, they are still devoid of those rights. If the husband of a Mohammedan woman dies and her father-in-law is alive, then her condition is most pitiable as she can have no share in the property as long as he is alive. The only alternatives left to her are either she beg alms or she may re-marry. So, there is need for change in that law. Why are we afraid to do so ?

In the end I want to say a few words about language policy. We have not given any encouragement to the study of Sanskrit to the extent to which we should have done. Israel has enlivened its dead language called Hebrew and now it has been made the language of their country. Similarly we have not given any encouragement to the Sindhi language. I find no mention about it in the Address.

With these words I will have to support reluctantly the motion of Shri Heda.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

पचपनवां प्रतिवेदन

Fifty fifth Report

श्री अ. शं. आल्वा (मंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति के पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 18 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की पचपनवें प्रतिवेदन से, जो 18 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 368)

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Yashpal Singh : I beg to introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 124 तथा 220 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Articles 124 and 220)

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was addopted.

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

समवाय (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 13-क का रखा जाना । धारा 293 आदि का संशोधन)

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

Insertion of new section 13 A, Amendment of section 293 etc)

Shri Yashpal Singh : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the companies Act, 1956.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

Shri Yashpal Singh : Sir, I introduce the Bill.

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—जारी

(धारा 3, 4 आदि का संशोधन)

SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(Amendment of sections 3, 4 etc.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री हरि विष्णु कामत के 18 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक को पेश करते समय, 18 दिसम्बर को एक छोटा सा भाषण दिया था । उस समय मैंने कहा था कि स्वतन्त्र भारत में मंत्रिगण अपने वेतन से भी अधिक ऊपरी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं । आज मैं अपनी बात की पुष्टि करने के लिए कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो मैंने प्राप्त किये हैं ।

मंत्रियों के वेतन 1952 के अधिनियम के अनुसार निर्धारित किये गये थे । इस अधिनियम में कुछ संशोधन पहली मई, 1962 को निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अभिसूचना से किये गये । उसके अनुसार एक मंत्रिमंडल के सदस्य तथा राज्य मंत्री को ऐसा निवास स्थान मिलेगा जिसका नियमोचित किराया 650 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होना चाहिये और उपमंत्री को ऐसा निवासस्थान मिलेगा जिसका नियमोचित किराया 350 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं होना चाहिये । मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को तथा किसी राज्य-मंत्री को मुफ्त फर्नीचर लेने का अधिकार 32,000 रुपये तक है और एक उपमंत्री को ऐसे ही 16,000 रु० तक के मुफ्त फर्नीचर लेने का अधिकार है । यह मुफ्त फर्नीचर उसे मिल सकता है चाहे वह एक वर्ष तक ही अपने पद पर रहे, चाहे 6 महीने तक रहे अथवा 5 वर्ष तक रहे ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

बाकी रहा बिजली का सामान जैसे---रेफरीजरेटर, हीटर और कूलर आदि उन्हें 6,500 रु० तक के मूल्य के मिल सकते हैं। और इस मामले में कोई भेदभाव नहीं कि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य है अथवा उपमंत्री। यह सुविधा उन्हें 9 सितम्बर, 1964 के संशोधन द्वारा की गई।

जो मंत्रियों को यात्रा भत्ता मिलता है उसमें उन्हें अधिकार है कि वे अपने साथ अपने परिवार तथा बच्चों को ले जा सकते हैं।

इसी प्रकार चिकित्सा सुविधा यद्यपि विशेष रूप से नहीं लिखी अपितु वह भी उनके लिये तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त उन्हें मिलती है।

मंत्रिमंडल के सदस्य जब इस सदन में छोटी कार के बारे में बात हो रही थी तो संसद्-सदस्यों को परामर्श दे रहे थे कि उन्हें केवल भारत में बनी कारें ही प्रयोग में लानी चाहियें। मैं मंत्री महोदय श्री हाथी से कहूंगा कि वह इस सदन के पटल पर एक विवरण रख और बतायें कि मंत्रिमंडल के कितने सदस्यों के पास भारत की बनी हुई कारें है।

30 अक्टूबर, 1964 को एक असाधारण गज़ट अधिसूचना जारी की गयी, जो बहुत ही रहस्यपूर्ण है। उसमें लिखा है कि 28 मई, 1964 से, अर्थात् जवाहरलाल नेहरू के स्वर्गवास के एक दिन बाद से, जिसके अनुसार प्रधान मंत्री 28 मई से 500 रु० प्रति मास के हिसाब से आतिथ्य-भत्ता ले सकते हैं और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य यह भत्ता 12 अगस्त, 1952 से ले सकते हैं। मेरे विचार में श्री नेहरू 500 रु० प्रति मास के हिसाब से आतिथ्य-भत्ता लेते थे। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य मंत्रिगण यह भत्ता 12 अगस्त, 1952 तक से ले सकते हैं।

अब मैं विदेशों के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह पता चलेगा कि वहां एक मत्री की तथा एक संसद्-सदस्य के वेतन में कितना अन्तर है। इंग्लैण्ड में मंत्रिमंडल के सदस्य को प्रधान मंत्री को छोड़ कर क्योंकि उसे 10,000 पौंड मिलते हैं, बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों को 5,000 पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं। राज्य मंत्रियों को 3,750 पौंड वार्षिक दर से मिलते हैं। और एक हाउस आफ कामन्स के सदस्य को 1,750 पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। इस प्रकार एक संसद्-सदस्य और एक मंत्री के वेतन में 1:3 का अनुपात है। यह जो आंकड़े मैंने ऊपर दिये हैं यह 15 अक्तूबर, 1964 से पहले के हैं। उसके बाद तो हाउस आफ कामन्स के सदस्यों के वेतन और बढ़ गये हैं---शायद कुछ सौ पौंड बढ़ गये हैं।

कनेडा में प्रधान मंत्री को 25,000 डॉलर वेतन मिलता है और अन्य मंत्रियों को 15,000 डॉलर के हिसाब से मिलते हैं। और हाउस आफ कामन्स के सदस्य को वहां 8,000 डॉलर वेतन मिलता है। इसलिये वहां भी अनुपात 1:3 का है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में राष्ट्रपति की कैबिनट के सदस्यों को जिन्हें वहां राष्ट्रपति के सचिव कहा जाता है, 25,000 डॉलर वेतन मिलता है और वहां संसद्-सदस्य का वेतन 22,500 डॉलर है।

हमारे देश में एक संसद् सदस्य को केवल 500 रु० वेतन मिलता है और एक कैबीनट के मंत्री को 2250 रु० वेतन मिलता है। वैसे यहां पिछले सितम्बर तक तो संसद् सदस्य को केवल 400 रु० मासिक ही मिलते थे। यहां अनुपात 1:5 का है। और हम अपने

आपको इंगलैंड और अमरीका के मुकाबले एक अधिक समाजवादी तथा लोकतंत्रित कहते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों के यात्रा भत्ते भी बहुत होते हैं। मुझे मध्य प्रदेश का तो पता है कि वहा मंत्रियों के यात्रा भत्ते उनके वेतनों से अधिक हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि यहां मंत्रियों और संसद्-सदस्यों के वेतन बराबर होने चाहिये। मैं तो कहता हूं कि कुछ ठीक अनुपात तो उस में हो।

मुझे विश्वास है कि सदन इस बात के लिए सहमत है कि मंत्रियों की यह ऊपरी आमदनी की चीजें कम करदी जावें यदि आप इन्हें बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। उसके बाद भले ही आप इनके वेतन को थोड़ा बढ़ा दें।

सदस्यों को अपनी बिजली पानी आदि के खर्च अपने वेतन से देने पड़ते हैं। ऐसी ही मंत्रियों को भी अपने बिजली, पानी आदि के खर्च अपने वेतन से देने चाहियें। वैसे चाहे मंत्रि-मंडल के सदस्यों को 2500 रु० और दूसरे मत्रियों को 2000 रु० मासिक का वेतन कर दिया जाये। जैसे सदस्यों को एक स्टैण्डर्ड स्केल (Standard Scale) से फर्नीचर मिलता है वैसे ही मंत्रियों को भी मिलना चाहिये। मुझे खुशी है कि मंत्रियों ने स्वेच्छा से बिजली व पानी की एक हद अर्थात् 200 रु० मासिक तक निर्धारित कर ली है। ऐसे ही मेरे संशोधन को भी वे मान लें कि वे कार के लिए पेशगी 12000 रु० से अधिक नहीं लें। और उन्हें भारत में बनी हुई कार ही लेनी चाहिये और विदेशी कार नहीं लेनी चाहिये।

मैं अपने मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को चर्चा के लिए पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं श्री कामत के विधेयक का समर्थन करता हूं। अंग्रेज इस देश से चले गये लेकिन उनके शान व शौकत के तरीके अभी यहीं रह गये हैं। मुझे विश्वास है कि यहां मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के वेतनों में बड़ा अन्तर है। जैसे अभी श्री कामत ने कहा कि अमरीका और इंगलैण्ड में संसद् सदस्यों तथा वहां के मंत्रियों के वेतनों में इतना अन्तर नहीं है जितना यहां है। यह अन्तर समाप्त होना चाहिये।

मंत्रिगण तथा सदस्य सब संसद् के सदस्य हैं फिर जो सुविधायें सदस्यों को नहीं मिलती वे मंत्रियों को क्यों मिलती हैं। हमें तो दस पैसे का टिकट भी मुफ्त नहीं मिलता और मंत्रियों को डाक टिकटें मुफ्त मिलती हैं। ऐसे ही हमें तो एक रेफरीजरेटर भी मुफ्त नहीं मिलता और मंत्रियों को बिजली के सारे सामान मुफ्त मिलते हैं। यदि हम यह सुविधायें मांगते हैं तो हमारे वेतनों से उनका किराया कट जाता है। इसलिये यह भेदभाव जो मंत्रियों और सदस्यों के बीच है वह समाप्त होना चाहिये।

यदि निजी क्षेत्र में वहां के अधिकारियों को अधिक वेतन अथवा और सुविधायें मिलती हैं तो हम चिल्लाना प्रारम्भ कर देते हैं कि वे कम्पनियों का 20 प्रतिशत भाग ऐसे ले जाते हैं परन्तु यहां मंत्रिगण सादी सुविधायें भोग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि मत्रियों तथा निजी क्षेत्र के अधिकारियों को समान सुविधायें मिलनी चाहिये।

हम कहते हैं कि हम गांधी जी के मार्ग पर चल रहे हैं। इस लिये मैं चाहता हूं कि मंत्रियों को भी उसी मार्ग पर चलना चाहिये। श्री कामत ने ठीक ही कहा कि छोटी कारें उपयोग में लानी चाहियें। मुझे प्रसन्नता है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री तथा इस समय के प्रधान मंत्री छोटी कार का उपयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि अन्य मंत्रियों को भी उनके उदाहरण पर चलना चाहिये। सरकारी कार केवल सरकारी काम के लिए उपयोग करनी चाहिये और जब मंत्रिगण अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जावें तो उनके लिए सरकारी कारों का उपयोग करना अच्छा काम नहीं है।

श्री कामत ने मंत्रियों को दिये गये फर्नीचर की बात कही। होता यह है कि जब कि मंत्री को अपना घर बदलना होता है तो साथ में सारा फर्नीचर भी बदल दिया जाता है क्योंकि मंत्रिगणों के रंग आदि के बारे में अपने अपने विचार होते हैं और वे अपनी ही पसंद के रंग के गलीचे इत्यादि रखना पसन्द करते हैं।

यदि हमें फर्नीचर बिजली और दूसरी सुविधायें मिलें तो मैं संसद सदस्यों को 500 रु० की जगह 250 रु० मासिक वेतन के भी हक में हूं। इसलिये मंत्रियों और सदस्यों के बीच जो अन्तर है वह समाप्त होना चाहिये।

हमें गांधी जी के बताये हुए मार्ग पर चलना चाहिये कि किसी को भी 500 रु० मासिक वेतन से अधिक नहीं मिलना चाहिये। यह नहीं कि रोजाना वेतन बढ़ाते चलें जावें और कर बढ़ाते चले जावें। यदि ऐसे ही चलते रहे तो फिर इसका कोई अन्त न होगा। इस लिये हमें सादा रहना तथा ऊंचा सोचना के सिद्धान्त पर चलना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill. There is a great disparity in emoluments of our Ministers and the Ministers in other countries. Ours is a poor country. We have decided to establish a socialistic pattern of society. I cannot understand as to why ministers are provided so many facilities at the cost of public exchequer. They are already getting high salaries. Common man in the country has not got adequate essential necessities like food, clothing and shelter.

We talk of Gandhiji very much and quote him very often. He taught us the lesson of simple living and high thinking, but our friends in Congress Party exploit his name for getting votes. They do not care to give practical shape to the indeals enunciated by Gandhiji.

It is not the question of salaries of ministers only, I would like a reduction in the salaries of Member of Parliament and M.L.A.s and highly paid Government officials who have no work to do.

I cannot understand as to why Rajya Sabha has been established. Government is pleasing its partymen in this way. It is a burden on our poor country. There is great frustation in the country. In the case of disputes Communist Party is labelled as mischief monger.

In our country some people are leading a life of luxury and are rolling a life in wealth where as others find it difficult to make both ends meet and are living in hand-to-mouth condition. In such circumstances there is bound to be a feeling of frustration.

This Bill seeks to end this bad state of affairs. The Government should accept it and add to the prestige of this House. People will realise that our Government has sympathetic feeling towards them. Then there will be no disputes.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill. My friend Mr. Kamath has brought it forward at an appropriate time.

Our country is a poor country. At the time of election our ministers make many promises to the poor masses and talk of service for the country. Once they are elected they forget their promises and pay no heed to the difficulties of poor people, who are leading a life of abject poverty.

High officials of our Government get very high salaries. They do not care for the poorer sections of society. They have got a very rigid bureaucratie attitude. Their salaries should also be reduced. Now I will say something about electricity. On 9th of this month notices have been served on Government employees here that they should deposit the security money otherwise their connection would be disconnected. I cannot understand why it has been done ? Government should stand surity for its employees.

Mr. Deputy Speaker : That is a separate question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Electricity is supplied of free of cost to ministers. I referred to it in that connection.

Ministers claim travelling allowances for their private visits to places particularly in Madhya Pradesh . Similar cases can be found here. I would say that standard of ministers and M.Ps. should be equal. High officials should also have same standard. Then we will have full confidence of people.

श्री दी० चं० शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मित्र श्री कामत का अभिप्राय इस विधेयक को लाने में बहुत अच्छा है । मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में आय की विषमतायें जहां तक हो सके समाप्त की जानी चाहिये । कम से कम और अधिक से अधिक वेतन में 1 तथा 10 का अनुपात होना चाहिये । एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक का न्यूनतम वेतन 100 रु० निर्धारित कर दिया जाना चाहिये ।

हमें सभी वर्गों के वेतनों में सुधार करना है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से आरम्भ कर के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के वेतन में उचित परिवर्तन करना चाहिये । इसे केवल मंत्रियों तक ही सीमित नहीं करना चाहिये । मेरे विचार में इस विधेयक में समस्या के अंश मात्र को ही लिया गया है । हमें सभी भिन्नतायें समाप्त करनी चाहियें ।

इसके साथ साथ जो सुविधायें कुछ लोग पहले ही ले रहे हैं वे समाप्त नहीं होनी चाहियें बल्कि हमें कहना चाहिये कि संसद सदस्यों को कुछ और सुविधायें दी जायें । हमें पहले छोटे दर्जे के कर्मचारियों के वेतन में सुधार करना चाहिये और मंत्रियों के सबके पश्चात् । हमें यह वर्ग भेद समाप्त करना चाहिये ।

हमारे यहां मंत्रियों, बड़े तथा छोटे अधिकारियों के वेतन का ढांचा हमारी राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के समनुरूप होना चाहिये । मैं "माई मिशन टु मास्को" नामक पुस्तक जो कि राजदूत डाड ने द्वितीय युद्ध के समय लिखी थी, पढ़ रहा था । यह बहुत अच्छी पुस्तक है । इस में उन्होंने मास्को

का एक अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है। उस पुस्तक में एक वाक्य था जो मुझे याद है, उस में कहा गया है कि रूस में मंत्री परिषद के सदस्य प्रतिष्ठा से रहते हैं और दिखावे से नहीं। हमारे यहां दिखावा बहुत चल पड़ा है। यह प्रवृति अच्छी नहीं। हमें प्रतिष्ठा और गरिमा से रहना चाहिये। यह बात समाज के सभी वर्गों को अपनानी चाहिये।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं इस विधेयक पर कुछ एक बातें कहना चाहता हूं। इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह ठीक दिशा की ओर संकेत करती है।

हमें देश में विषमताओं को समाप्त करना है। क्यों न हम इसका समारम्भ मंत्रियों से ही करें। हमें यह सुधार सबसे पहले मंत्री परिषद, संसद सदस्यों, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों पर लागू करना चाहिये।

हमारे गृह-कार्य मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा सदाचार समिति जैसी संस्थायें बनाने के लिये उत्सुक हैं। उन्हें चाहिये उपरोक्त लोगों में यह सद्व्यवहार की भावना पहले जागृत करें।

ऊंचे और नीचे की भावना समाप्त होनी चाहिये। हमें यहां पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। उस के पश्चात सम्पूर्ण देश में उसका प्रभाव हो सकता है।

अब मैं आपको भदभाव का एक और उदाहरण देता हूं। संसद भवन के केन्द्रीय हाल में जब भी कोई महत्वपूर्ण समारोह होता है जैसे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो उस समय आगे के स्थान मंत्रियों के लिये रक्षित कर दिये जाते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिये स्थान रक्षित करने की बात तो समझ में आती है परन्तु मंत्रियों के लिये यह क्यों होता है। वे भी तो सदस्य ही हैं। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

मैं श्री कामत के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अन्य समाजवादी देशों में विषमतायें इतनी गम्भीर नहीं हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate my hon. Shri Kamath for having brought this Bill. It would have been better if this Bill had been brought by Government. At the time of elections our ministers make big promises and give sermons.

I would suggest that the salaries of ministers and members of Parliament should be brought at par with each other.

They talk of socialism too much, but in practice they do things contrary to that. They spend lavishly at the cost of public exchequer. They should vacate the palatial buildings and these should be allotted to people like Vinoba Bhave, who are doing real service.

The ministers should set examples of service. Mahatama Gandhi was of opinion that ministers should live in huts. The number of our ministers is large.

Our Country cannot afford to maintain their highly expensive status.

In the end I would suggest that there should not be any difference between the salaries of ministers and members of Parliament.

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं इस विधेयक का आशय अच्छी प्रकार समझ गया हूं। वह मंत्रियों के वेतन के ढांचे पर पुनर्विचार करना चाहते हैं।

हम समाजवाद का राग बहुत अलापते हैं। परन्तु हम इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं कर रहे। उसके लिये हमें पहले आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना होगा।

हमें अपने समाज में भी परिवर्तन लाने होंगे। अपने पुराने दृष्टिकोण बदलने होंगे। आप हमारे यहां के बड़े बड़े अधिकारियों जैसे सचिवों, संयक्त सचिवों, उपसचिवों तथा अवर सचिवों को ही देखें। उन में भी वर्ग की भावना बहुत अधिक है। हमारे प्रशासनिक सेवाओं में आवश्यक परिवर्तन नहीं आया है जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आना चाहिये था।

मैं मानता हूं कि प्रधान मंत्री ने अपने मंत्री सहयोगियों का चयन उन के सामर्थ्य तथा योग्यता पर ही केवल नहीं किया। बहुत सी अन्य बातों का भी ध्यान रखा जाता है। एक प्रजातंत्र में मंत्री की स्थिति बहुत अनिश्चित सी होती है। अतः जितने समय तक वह मंत्री रहता है उसे अपना स्तर बनाये रखना होता है और उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना होता है।

मैं अन्य देशों के बारे में भी कहूंगा। क्योंकि मेरे मित्र ने इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। हमें उन देशों के रहन सहन के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिये। हमारे देश में आय और वेतनों के बीच ठीक अनुपात होना चाहिये। योजना आयोग के अनुसार 1975 में इस देश में एक औसत परिवार की आय 125 रु० महीना होगी। हमें अपने मंत्रियों के वेतन निर्धारित करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिये।

खेद की बात है कि हमारे कुछ मंत्री कपटभद्रता का शिकार हैं। वे अपने आप को कुछ उच्च दृष्टि से देखते हैं। ऐसी बात ब्रिटेन तथा अमरीका में नहीं। मैं जब अभी हाल ही में अमरीका में था तो मैंने देखा कि वहां श्री हैरीमेन वहां की संसद के सदस्यों के बीच बिल्कुल अनौपचारिक रूप में फिर रहे थे। यह भावना एक मनोवैज्ञानिक भावना है। हमें भी इसी ही प्रकार की भावना उत्पन्न करनी है। हमें इस देश में भी ऐसा ही वातावरण उत्पन्न करना है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I support this Bill. Some time back the Housing Minister had informed the House that the expenditure on electricity consumed by Ministers runs into thousands of rupees. It has given a vivid picture of lavish spending of our ministers. Our country is a poor country and we talk of socialism as our aim. In reality, it seems, we are going to the other direction.

I suggest that ministers should get a fixed salary and other allowances and facilities should not be provided. Heavy taxation is already breaking the back of poor masses, and the coming budget, it is feared, will add to the existing burden. The persons, who were servants of the people before, have now become the masters. They are exploiting common man.

I would request Shri Hathi that he should accept the principle which this Bill aims at. It is a private member's bill.

I was glad to learn that in the West Bengal budget they have reduced the salaries of ministers by Rs. 100/-. I have sent acongratulatory letter to the Chief Minister of West Bengal Shri P.C. Sen. I welcome the suggestion of Shri Vibhuti Mishra that ministers should stay with farmers when they go out on Tours. In this way they will be in a position to see for themselves the prevailing conditions. It is said that it will not be safe from security point of view. I do not know if any thing is secure in this country.

In the Durgapur session of Congress a businessman from West Bengal distributed enamel utensils to the 800 delegates free of cost.

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]
[SHRI KHADILKAR *in the Chair.*]

India is a country of idealists. We learnt so many good things from Gandhiji. We should try to emulate those noble ideals. We claim that our standard of living has gone up. Production of industrial products has increased. All this tall talk pales into insignificance when we see that man in street is not happy.

I congratulate Shri Kamath for having brought this Bill. It should be accepted by the Government.

Shri K. L. Balmiki (Khurja) : We have entered the last phase of third five-year plan and the fourth plan is about to commence but still we find that there exists a gulf between the life of a common man and that of a highly placed individual e.g. a Minister. We have the ideal of Socialism before us but the ratio of the income of the lowest and the highest is 1:60. The facilities if any, have accrued only to the privileged few. We have to see as to how far we have removed monopoly and disparity in incomes, social well-being, social order, social justice and social security. The life of a common man is in danger, even well-known and highly placed persons like Shri Kairon are murdered and we remain helpless spectators. This requires attention.

Socialism means equality of opportunity which is absent in today's life. There should be equality among all sections of the people whether one is Minister or a sweeper. The Ministers today lead a life of pomp and show whereas they ought to have followed what the lives of Gandhiji, Gokhale and Lala Lajpat Rai have taught us i.e. simple living. I have seen water and electricity being wasted in Ministers' bungalows here and in States where Legislators have free water and electric supply. The expenditure on these should be cut down.

Today equality and equality of opportunity are mere slogans and we should not only apply this principle of simplicity to Ministers alone but extend its application to all high officials also and efforts should be made that they also inculcate the essence of simplicity, truthfullness and high thinking. With these words, I support the Bill.

Shri R.S. Pandey (Guna) : The Bill presented by my hon. friend Shri H.V. Kamath suggests withdrawal of certain facilities to Ministers and some increment in their salaries. The matter is not so simple as it appears to be, and I have come to the conclusion after listening to the speeches of many members here that Ministers lead a very luxurious life and money is being wasted on water & electricity being used by them. But the proposal of my hon. friend Shri Kamath is in no way consistent with the ideal of socialism. Socialism will not come by increasing or decreasing the salaries of Ministers but by an integrated programme to expand production—both industrial and agricultural. This Bill seeks to create some sort of a political scandal or say political atmosphere the advantage of which will be taken by others like Communists etc. Surprisingly the amenities provided to Ministers in Communist countries of Eastern Europe and Yugoslavia are much more as compared to those given

to them here. In America the difference is still greater. But in India the disparity is great and according to Dr. Lohia 23 crore Indians live in starved condition and they earn 3 Annas per day but even in his case there is a difference in his word and deed even he did not say that he would accept 2-1/2 Annas a day. This will not bring socialism. It can be brought only when we adopt a scientific approach to society and the country. Labour, imagination and power will increase the wealth of the country and this wealth when properly distributed will bring socialism in the country. So the creation of such a political stunt to belittle the position of Ministers and thus create an impression on the minds of the public is not healthy. On an average a Minister after deduction such as income-tax etc. gets Rs. 1200/- or 1300/- p.m. and we M. Ps. also get almost the same and this has no relation with socialism.

I would like Shri Kamath to bring a Bill which might help to expansion of production, strength and forging the country march forward and then socialism will dawn on the country.

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : यद्यपि मैं विधेयक का इस रूप में समर्थन नहीं कर सकती फिर भी मेरे विचार में इसमें छिपी आत्मा के बारे में विचार किया जाना चाहिये । मैं श्री पांडेय से सहमत नहीं हूं कि चूंकि अमरीका और भारत के मंत्रियों के वेतनों और जीवन स्तर में बड़ा अन्तर है इसलिये उनके वेतन और भत्ते नहीं घटाने चाहियें । मैं यह भी नहीं चाहती कि मंत्री छोटे-छोटे मकानों में रहें । मैं चाहती हूं कि मंत्रिगण जो सरकार में जनता के प्रतिनिधि हैं अच्छी तरह रहें चाहे हमारा देश निर्धन ही है । परन्तु मेरा विचार है कि राजधानी का वातावरण वैसा ही है जैसा 1947 से पूर्व था । और यह स्वतंत्रता आते ही समाप्त हो जाना चाहिये था । राज्यों में भी ऐसा ही है चाहे बंगाल में ऐसा न भी हो परन्तु फिर भी यहां मंत्रियों को सादा जीवन बिताना चाहिये । मैं मानती हूं कि इससे समाजवादी समाज लाने में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा परन्तु मेरे विचार में जो अन्तर हमारे राष्ट्रीय नेताओं और शेष जनता में नहीं था जीवन स्तर में वह अन्तर नहीं होना चाहिये । यह ठीक है कि मंत्रियों की सुविधायें कम करने से आर्थिक दृष्टि से विशेष अन्तर नहीं पड़ता परन्तु फिर भी इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो जनता पर पड़ेगा ही और भारत जैसे देश में जहां हम सब योजनाएं चलाने में जनता का सहयोग और भाग लेने की भावना अधिकाधिक चाहते हैं यह प्रभाव और भी आवश्यक है । मैं मंत्रियों का बड़े-बड़े भवनों में रहना आपत्तिजनक नहीं मानती परन्तु जब देश में आवास सुविधाओं का इतना अभाव है तो एक ही मत्री का एक बड़े भवन में रहना बुरी बात है । मैं यक्तिगत रूप से मंत्रियों को दोष नहीं देती परन्तु जीवन की उस धारा को दोष देती हूं कि यह वैसी ही है जैसी स्वतंत्रता से पूर्व थी । और जिसके बारे में हम सोचते थे कि यह समाप्त हो जायेगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ । आज की राजधानी भारत की राजधानी नहीं लगती । यह देश की वास्तविकताओं से दूर होती जा रही है और मंत्री जो केन्द्र में जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वह भी अपने आपको कठिनता से इस कार्य को चला पाते हैं मैं यही चाहती हूं कि वह यहां अच्छी तरह रहें, परन्तु उन्हें जनता की कठिनाइयों का कुछ तो अनुभव हो ।

इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार कुछ ऐसा प्रबन्ध अवश्य करे जिनसे वह दिखावा और झूठी शान कम कर सकें ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, I do not want to go into the details of the Bill but I think that in the context of misunderstandings and existing economic conditions, this question of salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers etc. needs to be re-examined.

[Shri Bhagwat Jha Azad]

In America the per capita income is the highest in the world. I do not mean that Ministers and Members here enjoy the same facilities but I want that we should compare ourselves with other small countries, where Ministers and Deputy Ministers get less emoluments than our Ministers and fulfil their duties easily. So, the question arises of affecting reduction in the salaries and not increase. After that we shall have to reduce salaries of other bureaucrats who get thousands per month and after that the salaries of Members of Parliament should be revised. The extreme disparity in income should also be reduced.

This is not necessarily related to the question of socialism but it is a matter of psychological influence on the people.

There is an impression among the people that our Ministers are living a very luxurious life. That might not be true in all cases but this impression has to be removed. I want that the Ministers should be given only that much facilities that is necessary to enable them to fulfil their duties efficiently. For this in view of our economic condition and the impression among the people the principle underlying the Bill should be accepted.

Some of my hon. friends have referred to more production. People want to produce more but they are compelled not to do so because of lack of irrigational facilities etc. The conditions in which the people of the country are living should be kept in view and our Ministers should set an ideal before them.

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : श्रीमन्, मैंने श्री कामत का भाषण सुना। मुझ खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने स्थिति का एक ही पहलू देखा और दूसरा नहीं। मैं पूछता हूं कि क्या कोई ऐसा देश है जहां प्रधान मंत्री को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से आधा वेतन मिलता हो या उसके द्वारा नामजद व्यक्तियों अर्थात् राज्यपालों और राजदूतों से कम वेतन मिलता हो या विभिन्न सरकारी परियोजनाओं, प्रबन्ध निदेशकों अथवा अन्य व्यक्तियों से कम वेतन मिलता हो। हमें स्थिति का दूसरा पहलू भी देखना होगा।

इसमें आर्थिक पहलू की बात नहीं है। यदि कोई ईमानदार मंत्री अपने वेतन से ही गुजारा करना चाहे तो उसके लिए ऐसा करना बड़ा कठिन होगा। यह हमारा अनुभव है। पहले हमें 400 रुपये मिलते थे और अब 500 रुपये मिल रहे हैं। इस पर भी दो-दो जगह रहना-सहना मुश्किल पड़ रहा है। समाज में भी मेल-जोल बढ़ाना पड़ता है और राजनीतिक जीवन बनाए रखना पड़ता है। अतः यदि इस पर इस दृष्टि से देखा जाय तो इसमें आर्थिक पहलू शामिल नहीं होता।

आज कानून ऐसे हैं कि मंत्रियों को विशेष मकान लेने पड़ते हैं और एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यह बड़ी गलत बात है। मेरे विचार से यदि कोई मंत्री बनने से पूर्व के स्थान पर ही रहना चाहे और लोगों से मिलना जुलना रखना चाहे, तो उसे ऐसा करने दिया जाना चाहिए। बड़ी जगह पर नौकरों की भी अधिक आवश्यकता होगी और उनके लिये क्वार्टरों की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार मंत्री लोग जनता से दूर हो जाते हैं। यदि हम इस सामाजिक पद्धति पर चलें तो आप देखें कि मंत्रियों का समाज के व्यक्तियों से कितना सम्पर्क होता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा और इस मनोविज्ञान को बदलना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : Sir, I agree with the principles underlying the Bill but the difficulty is that only principles would not do. We have to see whether by enforcing the Bill, its objects would be achieved. Keeping in view of the existing conditions in our country we have to consider as to how we can go ahead with our principles. I would request the Government and especially the Ministers & other big officials that they should effect economy in expenses on allowances, furniture, electricity, water etc. In Czechoslovakia and Russia, Ministers get much more.

It would be better if a commission is appointed to go into this entire question of pay and allowances of Ministers, Members, high officials etc.

श्री हाथी : सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि मंत्री लोग बड़ी शान की जिन्दगी बिता रहे हैं और इस कारण देश को उन पर काफी धन खर्च करना पड़ रहा है, जो बचाया जा सकता है ।

विलास के जीवन में उस संस्था या संगठन का विश्वास नहीं है जिससे हमारा सम्बन्ध है और न ही हम देश को यह दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि हम शासन चला रहे हैं, इसलिये हमें कारों में घूमना चाहिए । लोगों में गलत धारणा फैलाने का कोई प्रयत्न नहीं होना चाहिये । मंत्रियों के आतिथ्य सत्कार भत्ते सम्बन्धी अधिसूचना का ठीक मतलब नहीं निकाला गया इसमें केवल प्रधान मंत्री के लिए भत्ता शामिल नहीं था जो अब जोड़ा गया । इसका भूतलक्षी प्रभाव से कोई प्रश्न ही नहीं है ।

मैं मानता हूं कि मंत्रियों को सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए । जहां तक सादा और विनम्र जीवन बिताने का सम्बन्ध है, इस पर किसी से कोई मतभेद नहीं हो सकता ।

यदि प्रस्तावक यह कहते कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते कम दिये जाएं तो बात और होती । परन्तु कठिनाई यह है कि वह वेतन को 2250 से बढ़ा कर 2500 करना चाहते हैं । प्रश्न यह उठता है कि क्या परिलब्धियां इतनी हैं कि वेतन बढ़ाने से धारणा भिन्न हो जाएगी । ऐसी बात नहीं है ।

जहां तक बिजली और पानी का सम्बन्ध है, हमें 200 रुपये तक मुफ्त खर्च होता है । इससे अधिक व्यय स्वयं उठाना पड़ता है । जहां तक मुफ्त मकान का प्रश्न है, श्री कामत भी इस बात को मानते हैं । वेतन का 19 प्रतिशत आय कर के तौर पर कट जाता है ।

मंत्रियों को अपने पत्नी, बच्चों आदि के लिए यात्रा भत्ते के रूप में केवल तब ही भत्ता दिया जाता है जब वे अपना कार्यभार संभालने अपने स्थान से आयें और जब मंत्रिपद छोड़ने के बाद अपने स्थान पर जाएं । मंत्रिपद पर बने रहने के दौरान उनको अपने पत्नी अथवा बच्चों के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता । जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो हमें अपने परिवार के सदस्यों को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है ।

दूसरी बात आदर्श की कही गयी है । मैं तो यह चाहता हूं कि किसी की आय में अधिक विषमता न हो । लेकिन जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है कि मंत्री लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहेहैं, यह ठीक नहीं है । यदि इस विधेयक को इस प्रकार पेश किया जाता कि समाजवादी समाज में वेतन मान एक विशेष तरीके से निर्धारित किए जा ें, तो बात और होती ।

मैं तो यहां तक कहूंगा कि मंत्री लोग यदि मंत्री न होते तो इससे कहीं अच्छा और आराम का जीवन बिता सकते और अधिक धन कमा सकते । मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता । हम यहां रुपया कमाने के लिए नहीं बैठे हैं और न ही हमारा यह इरादा है कि हमें अधिकाधिक आराम और धन

[श्री हाथी]

मिले। धन बर्बाद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक पाई भी बर्बाद नहीं होती। सब कुछ कट कटा कर मंत्री को केवल 900 रुपये प्रति मास ही मिल पाता है। अब आप ही सोचिए कि क्या दिल्ली में जीवन व्यतीत करने के लिए इतना धन पर्याप्त है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के सिद्धांतों का तो, यदि समूचे विधेयक का नहीं, समर्थन किया गया है। मंत्री महोदय का यह कहना है कि विधेयक में मंत्रियों को जितना वेतन देने को कहा गया है और जितना उनको अब मिल रहा है, उसमें अधिक अन्तर नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर वह इस विधेयक के सिद्धांतों को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ? यदि उन्होंने उपयुक्त समय पर एक विधेयक पेश करने का आश्वासन दिया होता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती।

मंत्रियों को 38000 रुपये फर्नीचर के लिए मिलते हैं। यदि वे पांच वर्ष तक मंत्री रहें तो यह रकम 500 रुपया महीना बैठती है। 500 रुपये आतिथ्य सत्कार भत्ते के मिलते हैं। यह सब रुपया करदाताओं का है। आतिथ्य सत्कार भत्ते का दुरुपयोग होता है। कितने ऐसे मंत्री हैं जो इस भत्ते को सही रूप में खर्च करते हैं। इसके अतिरिक्त 650 रुपये मकान किराये के रूप में मिलते हैं मैंने यह कभी नहीं कहा कि मंत्री लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि मंत्रियों के वेतन बढ़ा दिए जायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं तो यह चाहता हूं कि उनकी परिलब्धियों में कमी की जाए। अतः मैं सभा से अपील करता हूं कि इस विधेयक पर इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए विचार करें। यह एक उचित सुझाव है मैं यह मानता हूं कि मंत्रियों को कुछ आराम मिले लेकिन उसमें कुछ समानता और न्याय होना चाहिए।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे और विधेयक पर विचार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मतदान हुआ —

Lok Sabha divided

पक्ष में 10, विपक्ष में 106

Ayes 10, Noes 106

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 22 फरवरी, 1965/3 फाल्गुण, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 22, 1965/Phalguna 3, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2459 (Ai) LS—11- 6-65—600.